

व्यापार जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट

खंड ए: सामान्य प्रकटीकरण:

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण:

1. सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
 - लागू नहीं
 - आईआरडीआई पंजीकरण संख्या - 512
2. सूचीबद्ध इकाई का नाम-
 - भारतीय जीवन बीमा निगम (जीवन बीमा निगम अधिनियम - 1956 के तहत गठित)
3. निगमन का वर्ष-
 - 1956
4. पंजीकृत कार्यालय का पता
 - केंद्रीय कार्यालय, योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
5. कॉर्पोरेट पता
 - केंद्रीय कार्यालय, योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
6. ई-मेल
 - ed_rns@licindia.com
7. दूरभाष
 - 022-22022615
8. वेबसाइट
 - www.licindia.in
9. वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है
 - वित्तीय वर्ष 2025-26
10. स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं
 - एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) और बीएसई लिमिटेड
11. चुकता पूंजी:
 - ₹ 6324.99 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक 10 रुपये के कुल 6,32,49,97,701 शेयर हैं।
12. बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) -
 - सुश्री रोसलिन कुरियन/ 022-22022615 / ed_rns@licindia.com
13. रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत खुलासे एक स्टैंडअलोन आधार पर किए गए हैं (यानी केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया)
 - इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।
14. आश्वासन प्रदाता का नाम: में. रमा के गुप्ता एंड कम्पनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
15. प्राप्त आश्वासन का प्रकार:
 - व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट के लिए आश्वासन।

आश्वासन प्रदाता द्वारा जारी रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ख' के रूप में संलग्न है

II. उत्पाद/सेवाएं

16 व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार का 90% हिस्सा):

अनुक्रमांक	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का%
1.	बीमा सेवाएं पेंशन और स्वास्थ्य (सहित)	जीवन बीमा	100%

17. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (इकाई के कारोबार का 90% हिस्सा):

अनुक्रमांक	उत्पाद / सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का % योगदान दिया
1.	जीवन बीमा	65110	100%

III. संचालन:

18. उन स्थानों की संख्या जहां संयंत्र और/या संस्था के संचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं	5,004	5,004
अंतरराष्ट्रीय	लागू नहीं	121*	121

* कुल कार्यालयों की संख्या (अंतरराष्ट्रीय):

क्र. स.	इकाई	काँपोरिट	शाखा कार्यालय
1	एलआईसी फ़िजी		1
2	एलआईसी मॉरीशस		1
3	एलआईसी यूके*		1
4	एलआईसी (इंटरनेशनल) बीएससी (सी)#	1	4
5	एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड	1	76
6	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	1	23
7	एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड	1	9
8	एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड।*	1	0
9	आई एफ एस सी इशोरेंस आफिस गिफ्ट सिटी गांधीनगर		1
कुल :		5	116
		121	

#एलआईसी (इंटरनेशनल) बीएससी (सी), बहरीन कंपनी जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) देशों बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (दुबई और अबू धाबी) में काम करती है;

* नव व्यवसाय के लिए बंद

19. संस्था द्वारा सेवित बाजार:

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या)	36 (भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश)
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	10

ख. इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त विवरण

जीवन बीमा, निगम का प्राथमिक व्यवसाय है। हम विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों की एक विस्तृत विविधता को पूरा करते हैं। जनसांख्यिकी, जरूरतों, वित्तीय लक्ष्यों आदि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर, ग्राहकों को मोटे तौर पर निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- अ. नियमित आय वाले व्यक्ति जीवन कवर, कर लाभ, बचत आदि की तलाश में हैं और जो एंडोमेंट, मनी बैक और टर्म प्लान पसंद करते हैं
- आ. स्व-नियोजित व्यवसाय के मालिक जो जोखिम कवर के साथ धन सृजन में रुचि रखते हैं, यूलिप और पेंशन योजनाओं के लिए प्राथमिकता के साथ लचीले प्रीमियम विकल्पों की तलाश करते हैं।
- इ. नाबालिग, छात्र और युवा पेशेवर: वे ज्यादातर टर्म या सरल एंडोमेंट प्लान द्वारा कवर किए जाते हैं और कम प्रीमियम की तलाश करते हैं
- ई. वरिष्ठ नागरिक: वे पेंशन योजनाओं की ओर देखते हैं और गारंटीकृत आय और दीर्घकालिक सुरक्षा चाहते हैं
- उ. समूह ग्राहक: उनमें कॉर्पोरेट ग्राहक, सरकारी संगठन, संघ, गैर सरकारी संगठन आदि शामिल हैं। ग्रुप टर्म लाइफ, ग्रेच्युटी, सुपरएनुएशन, लीव एनकैशमेंट आदि मांगी जाने वाली योजनाओं के प्रकार हैं।
- ऊ. एनआरआई ग्राहक: वे भारत में पारिवारिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा लेते हैं, दीर्घकालिक बचत या टर्म प्लान पसंद करते हैं और हमें एक सुरक्षित और विश्वसनीय ब्रांड के रूप में देखते हैं।
- ऋ. ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के ग्राहक: हमने पीएमजेजेबीवाई आदि जैसे सरकारी जनादेश के तहत उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें कम आय वाले समूहों के लिए किफायती बीमा दिया जाता है और किसानों, मजदूरों आदि के लिए नीतियां बनाई जाती हैं।
- ए. उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति: वे एक अलग समूह हैं और बड़े कवरेज के साथ यूलिप, धन योजना या पेंशन योजनाओं जैसे निवेश उन्मुख योजनाओं की तलाश करते हैं।

IV. कर्मचारियों

20. वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांगजन सहित):

कर्मचारियों					
विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
		सं (बी)	% (बी/ए)	सं (सी)	% (सी/ए)
स्थायी (डी)	84565	64161	75.87	20404	24.13
स्थायी के अलावा अन्य (ई)	13	12	92.31	1	7.69
कुल कर्मचारी (डी + ई)	84578	64173	75.87	20405	24.13
श्रमिक					
विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
		सं (बी)	% (बी/ए)	सं (सी)	% (सी/ए)
स्थायी (फ)		निगम में श्रमिक वर्ग के कोई कर्मचारी नहीं है			
स्थायी (जी) के अलावा अन्य					
कुल कर्मचारी (फ + जी)					

ख. दिव्यांगजन कर्मचारी और कर्मी

क्रमांक	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिलाएं	
			सं (बी)	% (बी/ए)	सं (सी)	% (सी/ए)
दिव्यांगजन कर्मचारी						
1.	स्थायी (डी)	888	723	81.42	165	18.58
2.	स्थायी (ई) के अलावा अन्य	0	0	0	0	0
3.	कुल अलग-अलग विकलांग कर्मचारी (डी+ई)	888	723	81.42	165	18.58

क्रमांक	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिलाएं	
			सं (बी)	% (बी/ए)	सं (सी)	% (सी/ए)
दिव्यांगजन कर्मचारी						
4.	स्थायी (एफ)		निगम में श्रमिक वर्ग के कोई कर्मचारी नहीं है			
5.	स्थायी (जी) के अलावा अन्य					
6.	कुल विकलांग कर्मचारी (एफ + जी)					

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (ए)	संख्या व महिलाओं का प्रतिशत	
		सं (बी)	% (बी/ए)
निदेशक मंडल	10	1	10.00%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	10	0	0

* केएमपी में चार पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं

22. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर: (पिछले 3 वर्षों के रुझानों का खुलासा करें)

	स्थायी कर्मचारियों के लिए टर्नओवर दर (पिछले 3 वर्षों का)								
	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	8.36	7.23	8.09	8.60	7.14	8.25	6.80	5.67	6.54

नोट :

अ. निगम में कर्मचारियों का कोई वर्ग श्रमिक नहीं कहा जाता है।

आ. टर्नओवर दरों में सुपरएनुएशन नंबर भी शामिल हैं।

V. होल्टिंग, सहायक और एसोसिएट कंपनियां

23. (क) होल्टिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों के नाम

क्रमांक	होल्टिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों का नाम कॉलम 'अ'	इंगित करें कि होल्टिंग/सहायक/एसोसिएट	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम अ में इंगित इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हाँ/नहीं)
अंतरराष्ट्रीय				
1	एलआईसी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड	सहायक	100%	नहीं
2	एलआईसी (इंटरनेशनल) बीएससी (सी), बहरीन	सहायक	99.66%	नहीं
3	एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड	सहायक	55%	नहीं
4	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	सहायक	97.22%	नहीं
5	एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड	सहायक	83.33%	नहीं
राष्ट्रीय				
1	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
2	एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड	सहायक	100	नहीं

क्रमांक	होलिडिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों का नाम कॉलम 'अ'	इंगित करें कि होलिडिंग/ सहायक/एसोसिएट	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम अ में इंगित इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हाँ/नहीं)
3	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	49.24	नहीं
4	एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी	49.00	नहीं
5	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड.	सहयोगी	45.24	नहीं
6	एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	49.87	नहीं
7	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी	29.84	नहीं
8	एलआईसी एचएफएल एएमसी लिमिटेड	सहयोगी	5.38	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

24. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: (हां/नहीं)

- नहीं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू नहीं है।

भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना एलआईसी अधिनियम 1956 द्वारा की गई थी, जिसे भारत में जीवन बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस प्रकार, एलआईसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों द्वारा शासित कंपनी नहीं है। एलआईसी अधिनियम, 1956 में हाल ही में किए गए संशोधनों के बाद भी निगम भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य सीएसआर गतिविधियों के दायरे से बाहर है।

हालांकि, सामाजिक ज़िम्मेदारी और राष्ट्र-निर्माण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, LIC ने साल 2006 में अपनी गोल्डन जुबली (स्वर्ण जयंती) के दौरान 'LIC गोल्डन जुबली फ़ाउंडेशन' की स्थापना की। यह फ़ाउंडेशन 'बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950' के तहत एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड है और देश भर में अपनी मर्ज़ी से समुदाय के विकास से जुड़े सार्थक काम कर रहा है।

यह फ़ाउंडेशन गरीबी और मुश्किलों को दूर करने, शिक्षा को बढ़ावा देने, चिकित्सा सहायता और आम जनता के काम आने वाले प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों के लिए समर्पित है। लोगों पर केंद्रित अपने नज़रिए से, यह समाज के वंचित, हाशिए पर रहने वाले और कमज़ोर वर्गों की मदद करता है और सार्थक व टिकाऊ बदलाव लाने की कोशिश करता है।

फ़ाउंडेशन द्वारा शुरू की गई पहलें कई तरह की सामाजिक कल्याण गतिविधियों में फैली हुई हैं, जिनमें काबिल छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा सहायता, ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक और कौशल विकास पहल, और शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे में मदद शामिल है। इन लगातार प्रयासों के ज़रिए, LIC गोल्डन जुबली फ़ाउंडेशन, LIC की करुणा, सेवा और समावेशी विकास व सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता की विरासत को आगे बढ़ा रहा है।

फ़ाउंडेशन के लिए वित्त वर्ष 2025-26 वाकई बहुत खास रहा है। इस दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर खास ध्यान देते हुए कई अहम उपलब्धियां हासिल की गईं और समाज के लिए सार्थक पहल की गईं। अपनी लगन और पक्के इरादे से फ़ाउंडेशन ने अपनी पहुंच बढ़ाई है और देश भर में कई लोगों की ज़िंदगी पर सकारात्मक असर डाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में हमारी पहलों ने स्थायी बदलाव लाए हैं और सबके साथ मिलकर विकास करने के हमारे मिशन को मज़बूत किया है। इस साल सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट मंज़ूर किए गए - कुल 119 प्रोजेक्ट, जिनकी कीमत 77.74 करोड़ रुपये थी। स्वास्थ्य से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए अब तक की सबसे ज़्यादा रकम, यानी 62.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। नई स्कॉलरशिप की संख्या तीन गुना बढ़कर 10,660 हो गई है। ये स्कॉलरशिप कमज़ोर परिवारों के होनहार छात्रों को दी जाती हैं, ताकि वे पूरे आत्मविश्वास और सम्मान के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकें। 2025-2026 में स्कॉलरशिप के लिए सबसे ज़्यादा रकम बांटी गई।

शुरुआत से लेकर 31 मार्च 2026 तक, फ़ाउंडेशन ने 303 करोड़ रुपये के 1045 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनमें से 417 प्रोजेक्ट्स शिक्षा के क्षेत्र से, 437 स्वास्थ्य सेवा से और 191 प्रोजेक्ट्स आम जनता की भलाई से जुड़े हैं। फ़ाउंडेशन का सफ़र इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे मकसद के साथ किए गए काम समुदायों में बदलाव ला सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं।

- (ii) टर्नओवर (₹ में) - 536748.56 करोड़
(iii) नेट वर्थ (₹ में) - 175356.38 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें / शिकायतें:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त-वर्ष 2025-26			वित्त-वर्ष 2024-25		
		चालू वित्तीय वर्ष			पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
शेयरधारक	हां, कॉर्पोरेशन ने केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को शेयरधारक सेवाओं से संबंधित शिकायतों और प्रश्नों को हल करने में सहायता के लिए निगम के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है। निगम के पास एक निर्दिष्ट ई-मेल आईडी (investors@licindia.com) है और शेयरधारकों के लिए एक पोर्टल भी है ताकि वे शिकायतें दर्ज कर सकें। निवेशक सहायता के लिए लिंक: https://licindia.in/investors-support	922	3	31.3.26 को लंबित 3 प्रश्न 01.04.26 को हल किया गया था	1671	1	वित्त वर्ष 31.3 25 को एक मात्र शिकायत का समाधान 1.4.25 को कर दिया गया
कर्मचारियों	हां, निगम ने शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक तंत्र प्रणाली विकसित की है। इस उद्देश्य के लिए इंटरनेट पर ई-समाधान नामक एक पोर्टल जहां शिकायतों को किसी भी कर्मचारी द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है जिसे कर्मचारी शिकायत अधिकारी को ऑनलाइन अप्रेषित किया जाता है।	351	11	शून्य	369	12	वित्त वर्ष 2025-26 में सभी का समाधान कर दिया गया

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त-वर्ष 2025-26			वित्त-वर्ष 2024-25		
		चालू वित्तीय वर्ष			पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
ग्राहकों	https://licindia.in/web/guest/policy-for-protection-of-interests-of-policyholders	66,424	0		74,290	शून्य	
समुदायों	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
मूल्य श्रृंखला साझीदार	हां, मूल्य श्रृंखला भागीदार अपनी शिकायत, यदि कोई हो, निकटतम कार्यालय में तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से दर्ज करा सकते हैं।	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
अन्य-मंत्रालय	ईमेल के माध्यम से मंत्रालय का अनुपालन	141	1	अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रिया में है	168	1	एक मात्र लंबित शिकायत का समाधान वित्त वर्ष 2025-26 में किया गया

26. संस्थाके महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, उसी की पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के लिए दृष्टिकोण, इसके वित्तीय निहितार्थों के साथ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (R/O)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
1	नियामक और अनुपालन वातावरण	जोखिम और अवसर	विनियामक अनुपालन एलआईसी की कार्य नीति का एक अभिन्न अंग है। किसी भी लागू कानून का समय पर पालन न करने पर संभावित कानूनी कार्रवाई, प्रतिष्ठा को नुकसान या यहां तक कि वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। एलआईसी, एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने का प्रयास करती है।	एलआईसी के पास विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली है जो विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करती है	पहचाने गए जोखिमों को संबोधित न करने के वित्तीय निहितार्थों में ग्राहक शिकायतों का समाधान करते समय विनियामकों या अन्य कानूनी मंचों से उत्पन्न दंड शामिल हो सकते हैं। नकारात्मक ग्राहक भावनाओं के कारण नए व्यवसाय के मोर्चे पर भी नुकसान हो सकता है।

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (R/O)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
			निर्धारित मानकों को अपनाकर हम मानते हैं कि हम अपने सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने में सक्षम होंगे। हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सभी हितधारकों को प्रभावित करने वाले हमारे सभी नियम और विनियम कानूनी और विनियामक ढांचे के भीतर हों। एक सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के रूप में, हम आरटीआई दिशानिर्देशों से भी बंधे हैं जो जांच की एक अतिरिक्त परत के रूप में कार्य करते हैं।		विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करने से ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि हो सकती है, जिससे हमारी ग्राहक निष्ठा बढ़ेगी और बदले में हमारे ग्राहकों की निरंतरता और नए ग्राहकों की आमद बढ़ सकती है।
2	मानव पूंजी विकास	जोखिम और अवसर	अवसर: ज्ञान उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, हमारी मानव पूंजी ताकत और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का एक प्रमुख स्रोत है। निरंतर अप-स्किलिंग हमें अपनी नेतृत्व की स्थिति को मजबूत करने और उद्योग के सामने आने वाली सभी चुनौतियों का बेहतर तरीके से मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। जोखिम: वर्तमान प्रतिस्पर्धी परिदृश्य और तेजी से बदलती विपणन स्थितियों में, प्रमुख प्रतिभाओं को बनाए रखना एक चुनौती है।	एलआईसी लगभग 85 हजार कर्मचारियों के साथ एक विशाल ट्रांस-नेशनल संगठन है। आकार और भौगोलिक प्रसार के साथ-साथ कर्मियों की नीतियों को ध्यान में रखते हुए संगठन में निरंतर ऊर्ध्वाधर और पार्श्व आंदोलन होता है। इन सभी कारकों के लिए आवश्यक है कि संगठन के भीतर कौशल विकास और ज्ञान आधार को बढ़ाने की एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। महामारी की स्थिति ने संगठन को डिजिटल मोड के माध्यम से स्व-शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसने भौतिक बुनियादी ढांचे और सुविधाकर्ताओं पर निर्भरता के बिना मानकीकृत सामग्री को सक्षम किया है और हमारे इंटरनेट पर कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध है। वर्तमान फोकस नए कार्य अनुभव के हिस्से के रूप में संचार और सहयोग को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। इसके अलावा, स्व-शिक्षण/स्व-कौशल के उद्देश्य से, कर्मचारियों के लिए एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, 'एलआईसी ज्ञानपीठ' शुरू की गई थी।	उच्च कर्मचारी टर्नओवर से उत्पादकता में कमी, काम पर रखने की लागत में वृद्धि और सामान्य रूप से कम कर्मचारी मनोबल के साथ-साथ दक्षता में कमी हो सकती है।

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (R/O)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
3	जलवायु परिवर्तन - जोखिम और लचीलापन	जोखिम	समाज में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है। पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम बन रहे हैं। अगर हम समाज की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते या संबंधित नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इससे हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है और भारी जुर्माना भी लग सकता है।	सस्टेनेबल बिज़नेस प्रैक्टिस, जिम्मेदार मैनेजमेंट और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, हमारे संगठन में बोर्ड से मंजूर ESG फ्रेमवर्क और क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क मौजूद हैं। ESG और क्लाइमेट से जुड़े कई तरह के रिस्क की पहचान की गई है और उन्हें रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। कॉर्पोरेशन के सभी ऑफिस समय-समय पर इन रिस्क का आकलन करते हैं। रिस्क ओनर्स के लिए एक नया रिस्क मॉड्यूल उपलब्ध है, ताकि वे नए एडवॉन्स और क्लाइमेट रिस्क की पहचान कर सकें और उन्हें रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में शामिल कर सकें।	नकारात्मक
4	सूचना सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित	जोखिम	ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने के लिए मज़बूत डेटा प्राइवैसी और साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। जैसे-जैसे हम डिजिटल बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ग्राहक-केंद्रित बने रहें और डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन कर सकें। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी घटनाएं हमारी प्रतिष्ठा, ग्राहकों और हमारे कारोबार पर असर डाल सकती हैं। इसलिए, ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा के लिए साइबर सिक्योरिटी और प्राइवैसी से जुड़े उपायों का लगातार मूल्यांकन करना, उन्हें लागू करना और उनसे जुड़े जोखिमों को कम करना ज़रूरी हो जाता है।	LIC साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवैसी को सबसे ज़्यादा अहमियत देती है। कंपनी लगातार नई और मज़बूत टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही है और इंडस्ट्री की सबसे अच्छी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, प्रोसेस और नियमों का पालन कर रही है। बोर्ड की IT स्ट्रैटेजी कमिटी और एग्जीक्यूटिव लेवल की कमेटियां साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवैसी से जुड़े मामलों की निगरानी करती हैं। LIC साइबर खतरों और उनके समाधान के लिए ऑडिट, सिक्योरिटी असेसमेंट और कंट्रोल के वैलिडेशन का काम करती है। हम ISO 27001 सर्टिफाइड हैं और DPDP एक्ट को लागू करने की प्रक्रिया में हैं।	वित्तीय और प्रतिष्ठित नुकसान हानिकारक हो सकता है।

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (R/O)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
5	जोखिम प्रबंधन और व्यवसाय निरंतरता	जोखिम	लंबे समय तक टिके रहने, मार्केट वैल्यूएशन और ब्रांड इमेज को बेहतर बनाने और स्टेकहोल्डर्स का भरोसा मज़बूत करने के लिए, व्यवस्थित रूप से तैयार किया गया रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान ज़रूरी है। यह बेहतर फ़ाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और बिज़नेस की मज़बूती में मदद करता है।	कॉरपोरेशन के पास बोर्ड से मंज़ूर 'बिज़नेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट' (BCM) प्लान है। इसे सिस्टम फेलियर, प्राकृतिक आपदाओं या साइबर घटनाओं जैसी रुकावटों के दौरान भी ज़रूरी कामकाज को जारी रखने के लिए बनाया गया है। इस प्लान का मकसद कामकाज में रुकावट के समय को कम करना, ज़रूरी कामों को सुरक्षित रखना, आर्थिक नुकसान घटाना और तेज़ी से रिकवरी सुनिश्चित करना है। BCM प्लान में ज़रूरी बिज़नेस कामों को जारी रखने या उन्हें तेज़ी से बहाल करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ बताई गई हैं। कॉरपोरेशन अपने 'बिज़नेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम' के लिए ISO 22301 सर्टिफाइड है, जो ऑपरेशनल तैयारी के प्रति उसकी मज़बूत प्रतिबद्धता को दिखाता है।	नकारात्मक

खंड बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

प्रकटीकरण सवाल	सि.1	सि.2	सि.3	सि.4	सि.5	सि.6	सि.7	सि.8	सि.9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ									
1. क. क्या आपकी इकाई की पॉलिसी/पॉलिसी प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्व कवर करती हैं (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	ना	हां	हां
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	https://licindia.in/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct . निगम की कुछ पॉलिसियां केवल कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।								
2. क्या इकाई ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हाँ/नहीं)	हमारे मूल्य श्रृंखला भागीदार सुरक्षा और स्वस्थ पर्यावरण, बाल श्रम और जबरन श्रम के निषेध, गैर-भेदभाव, रोजगार की स्थिति, मजदूरी के प्रावधान और काम के घंटों से संबंधित आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अनुबंधात्मक रूप से बाध्य हैं।								

प्रकटीकरण सवाल	सि.1	सि.2	सि.3	सि.4	सि.5	सि.6	सि.7	सि.8	सि.9	
4. आपकी इकाई द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों (जैसे वन प्रबंधन परिषद, निष्पक्ष व्यापार, वर्षावन गठबंधन, ट्रस्टी) मानकों (जैसे SA8000, OHSAS, ISO, BIS) का नाम और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया।	सिद्धांत 4 के तहत, एलआईसी ने प्राप्त किया है: ईआरएम के लिए आईएसओ 31000 बीसीपी के लिए आईएसओ 22301									
5. विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और लक्ष्य इकाई द्वारा निर्धारित समय-सीमा के साथ सेट, यदि कोई हो	अ.	हम अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में ईएसजी सिद्धांतों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं	आ.	हम जल संरक्षण, ऊर्जा उपयोग को कम करने और अपने कार्बन फुटप्रिंट के साथ-साथ जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।	इ.	हम एक समान अवसर नियोक्ता हैं जो किसी भी आधार पर कोई भेदभाव सुनिश्चित नहीं करते हैं।	ई.	देश में सभी बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुंचने और उन्हें उचित लागत पर मृत्यु के खिलाफ पर्याप्त वित्तीय कवर प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापक रूप से और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जीवन बीमा का प्रसार करना।	उ.	बीमा से जुड़ी बचतों को पर्याप्त रूप से आकर्षक बनाकर बचत को अधिकतम करना।
	ऊ.	धन के निवेश में, अपने पॉलिसीधारकों के लिए प्राथमिक दायित्व, जिसका पैसा विश्वास में रखता है, समग्र रूप से समुदाय के हित की दृष्टि खोए बिना; राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और आकर्षक लाभ की बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए निवेशकों तथा समग्र रूप से समुदाय के सर्वोत्तम लाभ के लिए निधियों का उपयोग किया जाएगा।	ऋ.	अत्यंत अर्थव्यवस्था के साथ और पूर्ण अहसास के साथ व्यापार का संचालन करें कि पैसा पॉलिसीधारकों का है।	ए.	अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमताओं में बीमित जनता के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना।	ऐ.	बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश में उत्पन्न होने वाली समुदाय की विभिन्न जीवन बीमा आवश्यकताओं को पूरा करें।	ओ.	शिष्टाचार के साथ कुशल सेवा प्रदान करके बीमित जनता के हितों को आगे बढ़ाने में निगम में काम करने वाले सभी लोगों को उनकी सर्वोत्तम क्षमता में शामिल करना।
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के खिलाफ इकाई का प्रदर्शन, साथ ही कारणों के साथ-साथ यदि वे पूरे नहीं होते हैं।	अ.	हमने सिर्फ 2025-2026 में 8,30,399 मृत्यु दावों और 2,41,25,943 व्यक्तिगत परिपक्वता दावों क्लेम का निपटारा किया है, जिसमें क्रमशः 19,019.79 करोड़ रुपये और 2,37,353.14 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस तरह, हमने आश्रित परिवारों, लेनदारों, साझेदारों और बिज़नेस इंश्योरेंस के मामले में मुख्य व्यक्तियों (key men) आदि को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है।								

प्रकटीकरण सवाल	सि.1	सि.2	सि.3	सि.4	सि.5	सि.6	सि.7	सि.8	सि.9
	आ.	हम 31.03.2026 तक पीएमजेजेबीवाई के तहत 3,70,40,056 करोड़ जीवन कवर किया हैं और समाज के कमजोर वर्गों को पूरा करने के लिए अन्य सूक्ष्म बीमा उत्पादों को डिजाइन करते हैं।							
	इ.	वंशानुगत कमीशन का भुगतान 60,297 से अधिक एजेंटों के आश्रितों को किया जाता है जिनकी मृत्यु हो गयी हैं और नवीनीकरण कमीशन के लिए पात्र थे।							
	ई.	59% ग्राम पंचायतों को कम से कम एक बीमा सखी के साथ कवर किया गया है, जिससे महिला बीमा एजेंटों को प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान किया जा रहा है और साथ ही जीवन बीमा का प्रसार करने के लिए देश के कोने-कोने तक पहुंच बनाई जा रही है।							
	उ.	ग्रामीण इलाकों में इंश्योरेंस कवर को बढ़ावा देने के लिए हमने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं और 31.03.2026 तक 2,83,249 बीमा सखियाँ कार्यरत थीं।							
शासन, नेतृत्व और निरीक्षण									
7. व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के प्लेसमेंट के संबंध में लचीलापन है)									व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट के बारे में बोर्ड की समग्र जिम्मेदारी है और निगम के ईएसजी मुद्दों की पहचान और प्रबंधन करना है
8. कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति									श्री आर दुरैस्वामि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक डिन: 10358884
9. क्या संस्था के पास बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हाँ /ना) यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।									हाँ, कॉर्पोरेशन के गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े कामों की पूरी जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स (बोर्ड) की है। बोर्ड ने एक एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस (ESG) कमिटी बनाई है। यह कमिटी ESG लक्ष्यों, टारगेट और रणनीति को मंजूरी देती है और उन पर हुए काम की निगरानी करती है। इसमें ESG से जुड़े ऐसे काम भी शामिल हैं जिनसे स्टैकहोल्डर्स के लिए लंबे समय तक वैल्यू बन सके। साथ ही, यह कमिटी कॉर्पोरेशन की ESG गतिविधियों की समय-समय पर समीक्षा भी करती है। बोर्ड ने ESG कमिटी की सिफ़ारिश पर ESG फ़्रेमवर्क और क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट फ़्रेमवर्क को मंजूरी दी।
10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण									
उपरोक्त नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई									बोर्ड / बोर्ड की समिति / कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन ने उन नीतियों को अनुमोदित किया है जो ऊपर बताई गई हैं जैसा कि वर्तमान नियमों द्वारा आवश्यक है।
बताएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									अंतर-विभागीय रूप से की गई समीक्षा
आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)									अर्धवार्षिक
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार									कंपनी सभी लागू नियमों का अनुपालन करती है।

प्रकटीकरण सवाल	सि.1	सि.2	सि.3	सि.4	सि.5	सि.6	सि.7	सि.8	सि.9
11. क्या इकाई ने बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन किया है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएँ।	निगम की सभी नीतियों का आंतरिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है								

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर 'नहीं' है अर्थात् सभी सिद्धांत नीति द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो बताए जाने वाले कारण:

सवाल	सि.1	सि.2	सि.3	सि.4	सि.5	सि.6	सि.7	सि.8	सि.9
इकाई अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांतों को सामग्री नहीं मानती है (हाँ/नहीं)	-	-	-	-	-	-	नहीं	-	-
इकाई उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों (हाँ/नहीं) पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं	-	-
इकाई के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं	-	-
इसे अगले वित्तीय वर्ष में किए जाने की योजना है (हाँ/नहीं)	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं	-	-
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	**	-	-

**एक सूचीबद्ध इकाई के रूप में, एलआईसी एक उच्च विनियमित वातावरण में काम करती है। इसके अलावा, निगम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखता है। निगम नियमित रूप से उक्त नियामक प्राधिकरणों द्वारा गठित विभिन्न मंचों और समितियों में भी भाग लेता है। हालांकि इस सिद्धांत के लिए कोई विशेष नीति नहीं बताई गई है, लेकिन स्टाफ रेगुलेशन, 1960 उन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को नियंत्रित करता है, जिन्हें उच्च पेशेवर और नैतिक मानकों के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। निगम, व्यापार निकायों और संघों के माध्यम से, अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से बीमा क्षेत्र के संबंध में कई सुझाव देता है।

खंड सी: सिद्धांत वार प्रदर्शन प्रकटीकरण:

सिद्धांत 1: व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से खुद को संचालित और नियंत्रित करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

हिस्सा	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसके प्रभाव	जागरूकता द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत कार्यक्रम
निदेशक मंडल	4	1) स्ट्रैटेजी मीट - बिज़नेस स्ट्रैटेजी, शेयरहोल्डर वैल्यू, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, रिस्क मैनेजमेंट, HR स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल एसेट पर सेशन 2) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर सेशन 3) स्ट्रैटेजी मीट - बिज़नेस स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन-IT, एक्चुअरियल प्रेजेंटेशन, HR स्ट्रैटेजी और रियल एस्टेट मैनेजमेंट पर सेशन 4) डायरेक्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम - III	96.43% 100% 100% 30% (10 निदेशकों में से 3 उपस्थिति)

हिस्सा	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसके प्रभाव	जागरूकता द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत कार्यक्रम
अत्यंत महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक	9	<ol style="list-style-type: none"> 44वां इंडिया फेलोशिप सेमिनार, मुंबई जर्मनी में म्यूनिख री ग्लोबल लाइफ इश्योरेंस सेमिनार MDC में ESG लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइफ एश्योरेंस में 20वां करंट इश्यूज सेमिनार (20वां CILA) 45वां इंडिया फेलोशिप सेमिनार (IFS) एक्चुअरीज का 25वां ग्लोबल कॉन्फ्रेंस (GCA) कंपनी सेक्रेटरीज का राष्ट्रीय सम्मेलन इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रिटायरमेंट ट्रेनिंग और ESG लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 	50% (10 में से 5 अ. म. का. उपस्थिति)
निदेशक मंडल एवं महत्वपूर्ण प्रबंधकीय के अलावा अन्य कर्मचारी	5713	<p>LIC एक्ट, 1956 ICSI का नेशनल कन्वेंशन SDD में UPSI की गतिविधियों को ट्रैक करने पर सेशन कंप्लायंस के लिए नॉमिनेट किए गए नोडल अधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन सेशन</p> <p>IT और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बदलता माहौल, खद पहल, सोशल मीडिया, बिजनेस एटिकेट्स, पर्सिस्टेंसी में बढ़ोतरी, प्रीमियम कलेक्शन बढ़ाने पर फोकस, BCP, ERM, KYC/AML/CFT सेशन, IT/मोबाइल ऐप्स, चड ऑफिस, IRDAI रेगुलेशन/रेगुलेटरी जानकारी, नए प्रोडक्ट्स/प्रोडक्ट-बेस्ड प्रोग्राम, कस्टमर सर्विस के प्रति जागरूकता/शिकायत निवारण, करियर ग्रोथ के लिए एजेंट्स, टेलीफोन और ईमेल एटिकेट्स/लेटर राइटिंग/ईमेल पॉलिसी, रिटायर होने वाले अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग, PLLI, मल्टीफंक्शनल ट्रेनिंग, हेल्थ और सेफ्टी/वेलनेस/PoSH, दिव्यांगों (PwD) के लिए आसान KYC, कंप्लायंस सर्टिफिकेशन प्रोसेस, अलग-अलग कैडर के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेन द ट्रेनर्स, RTI एक्ट, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल मॉडलिंग और फोरकास्टिंग के बेसिक्स, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रेगुलेटरी कंप्लायंस, फिक्स्ड इनकम डेरिवेटिव्स, GST इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, BRSR, प्रिवेंटिव फोरेंसिक्स, बॉन्ड मैथमेटिक्स और इंडियन ट्रेजरी मार्केट का परिचय, रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शंस और मुख्य रेगुलेशंस में महारत, इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, सिक्योर कोडिंग प्रिंसिपल, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड एथिक्स, POSH, मानवाधिकार और ESG को शामिल करना, डिजिटल फ्रॉड के प्रति जागरूकता, आरक्षण के मामलों पर ट्रेनिंग सेशन, शिकायत निवारण (GR) को मज़बूत करना, दिव्यांगों (PwD) के प्रति जागरूकता प्रोग्राम, प्रभावी प्रोक्योरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट</p>	81.53% 68,946 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया

प्रशिक्षण कार्यकलाप आंतरिक प्रशिक्षण केन्द्रों और बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से किए जाते हैं।

इन-हाउस प्रशिक्षण:

एलआईसी के पास अच्छी तरह से सुसज्जित इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों का एक नेटवर्क है। सभी केंद्र छात्रावास आवास, कक्षाओं, सभागारों, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, एलसीडी सुविधाओं, मनोरंजन और खेल सुविधाओं से सुसज्जित हैं। एलआईसी के इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों में शामिल हैं:

- प्रबंधन विकास केंद्र (MDC): निगम का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान।
- क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (ZTC): एलआईसी के आठ क्षेत्रों में से प्रत्येक में स्थित एक।
- कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र (ETC) / कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र (CTC): 113. प्रत्येक डिवीजन में एक
- डिविज़नल ट्रेनिंग सेंटर (DTCs): एजेंटों के लिए 113 डिविज़नल ऑफिस में प्रत्येक में एक सेंटर।

बाहरी प्रशिक्षण:

अभिनव दृष्टिकोण प्रदान करने, विशेष उद्योग ज्ञान प्राप्त करने और वैश्विक मानव संसाधन प्रथाओं के साथ सरेखित करने के लिए, एलआईसी अपने अधिकारियों को बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला में भाग लेने के लिए नामित करता है। ये प्रोग्राम नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी - NIA (पुणे), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट - IIMs, इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस - ISB (हैदराबाद), इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स - IOD (मुंबई), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिविलियन इंजीनियरिंग - NISM (मुंबई), ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन - AIMA (दिल्ली), डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज़ - DFS (दिल्ली), इंस्टीट्यूट ऑफ एक्ज्यूटिव्स ऑफ इंडिया - IAI (मुंबई), नेशनल फोर्सिक साइंसेज़ यूनिवर्सिटी - NFSU (गांधीनगर), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड - SAIL (रांची), अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट - AJNIFM (फरीदाबाद), दिल्ली मेट्रो रेल एकेडमी - DMRA (दिल्ली), द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया - ICSI (दिल्ली), एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया - ASCI (हैदराबाद), कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस - COI (मुंबई), बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री - BCCI (मुंबई), FIMMDA (मुंबई), ब्लूमएशिया इनकॉर्पोरेटेड (मुंबई), प्रिंसटन एकेडमी (मुंबई), टाइम्स इंटरनेट (मुंबई), ICICI बैंक लिमिटेड, नोल्स्केप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (बेंगलुरु), NAHRD (दिल्ली) और इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट - IIRM (हैदराबाद), स्पेस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एकेडमी नागपुर, IISWBM - कोलकाता, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (MDI) गुरुग्राम, BML मुंजाल, दिल्ली, वगैरह जैसे जाने-माने संस्थानों द्वारा कराए जाते हैं।

एमडीसी और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा इन-हाउस आयोजित विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या 1,51,176 है। एनआईए सहित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या 6,935 थी। इस प्रकार 1,58,111 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से कुछ ने इसी अवधि के दौरान विभिन्न विषयों पर और भूमिकाओं के परिवर्तन पर कई प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया।

लघु अवधि के वेबिनार:

कर्मचारियों और फील्ड फोर्स के बड़े हिस्से तक पहुंचने के लिए, बाहरी ट्रेनिंग संस्थानों और हमारे इन-हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ मिलकर कम समय वाले वेबिनार की एक सीरीज़ आयोजित की गई। इन वेबिनार में कई तरह के विषयों को शामिल किया गया, जैसे:

- नई डिजिटल पहल, साइबर सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी से बचाव
- नए बिज़नेस पैरामीटर और परफॉर्मेंस इंडिकेटर
- मार्केटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिनमें इंटरमीडियरी, प्रोडक्ट और सेल्स तकनीकें शामिल हैं।
- अंडरराइटिंग नियम, जिनमें 'की-मैन इंश्योरेंस', एम्प्लॉयर-एम्प्लॉई स्कीम, MWP एक्ट, महिलाओं और नाबालिगों का जीवन बीमा और नॉन-मेडिकल बीमा शामिल हैं।
- पॉलिसी सर्विसिंग, रिवाइवल, पर्सिस्टेंसी और क्लेम सेटलमेंट (जिसमें री-इन्वेस्टमेंट भी शामिल है)
- प्रिवेंटिव विजिलेंस (सतर्कता)।

एलआईसी ज्ञानपीठ-सेल्फ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल:

- एलआईसी ज्ञानपीठ एक सेल्फ-लर्निंग और सेल्फ-स्किलिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कि साल 2020 में शुरू किया गया। यह मानकीकृत सामग्री प्रदान करता है जो भौतिक बुनियादी ढांचे और सुविधाकर्ताओं की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे 24/7 इंटरनेट/इंटरनेट वेब ब्राउज़र के माध्यम से कर्मचारियों को कभी भी, कहीं भी प्रशिक्षण सुलभ हो जाता है।

- एलआईसी ज्ञानपीठ, विशेष रूप से विभिन्न कार्यात्मक पहलुओं पर निर्बाध प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पोर्टल को बढ़ाने और अपडेट करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 31 मार्च 2026 तक, पोर्टल में 19 मुख्य मॉड्यूल, 8180 MCQ के साथ 166 उप-मॉड्यूल शामिल हैं।
- 'एलआईसी ज्ञानपीठ' को कर्मचारियों से भारी प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें लगभग 75,057 (89.69%) कर्मचारियों ने कुल 24,29,843 एलआईसी ज्ञानपीठ प्रमाणपत्र अर्जित किए हैं।
- ज्ञानपीठ मॉड्यूल के तहत जारी किए गए मुख्य मॉड्यूल प्रमाणपत्रों की संख्या 2,91,712 थी और जिन उप मॉड्यूलों के लिए प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, उनकी संख्या 21,38,131 थी, इस प्रकार कुल मिलाकर कुल 24,29,843 प्रमाण पत्र जारी किए गए।

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/दंड/पुरस्कार/कंपाउंडिंग फीस/निपटारा राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में

(नोट: इकाई सेबी के विनियमन 30 (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण दायित्वों) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट भौतिकता के आधार पर और इकाई की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार प्रकटीकरण करेगी:

वित्तीय					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम	राशि (₹ में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/नहीं)
जुर्माना/जुर्माना	शून्य	राजस्व अधिकारी जैसे आयकर अधिकारी, GST अधिकारी आदि	0.02 करोड़	ITC का गलत इस्तेमाल, ई-वे बिल जारी न करना, TDS रिटर्न देर से दाखिल करना, एजेंट को खर्चों की भरपाई पर सर्विस टैक्स के लिए जुर्माना।	नहीं
निपटारा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
कंपाउंडिंग शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
गैर-मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/नहीं)	
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में प्राथमिकता दी गई अपील/पुनरीक्षण का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम
शून्य	शून्य

4. क्या इकाई के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्त विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्त विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

निगम की रिश्तखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति है। इसमें व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी भी है। इसके अतिरिक्त, भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) नियमावली, 1960 के नियम 32 के उपबंधों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी अथवा कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को मामूली मूल्य से अधिक के उपहार स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। रिश्त विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति के लिए लिंक निम्नानुसार है:

<https://licindia.in/documents/d/guest/anti-bribery-and-anti-corruption-policy-1->

5. उन निदेशकों/केएमपी / कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके खिलाफ रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:

	वित्त वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
निर्देशकों	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य
कर्मचारियों	02	01

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

	वित्तीय वर्ष 2025-26		वित्तीय वर्ष 2024-25	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/शास्तियों/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज दो मामलों में कार्यवाही चल रही है।

8. देय खातों के दिन: (देय खाते *365)/खरीदे गए माल/सेवाओं की लागत):

	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
देय खातों के दिनों की संख्या	23.53	12.12

9. व्यापार का खुलापन:

निम्नलिखित प्रारूप में, संबंधित पार्टियों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश के साथ-साथ व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पार्टियों के साथ खरीद और बिक्री की एकाग्रता का विवरण प्रदान करें:

बीमा/सेवा क्षेत्र के लिए कुछ पैरामीटर लागू नहीं होते हैं, इसलिए जानकारी केवल जहाँ तक लागू है, वहीं तक प्रदान की गई है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान गलत व्याख्या के कारण यह जानकारी प्रदान कर दी गई थी।

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26	पिछला वित्त वर्ष 2024-25
खरीद का संकेन्द्रण**	अ. कुल खरीद के % के रूप में दलालों से खरीद	लागू नहीं	16.64% द्वितीयक बाजार व्यापार
	आ. दलालों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है	लागू नहीं	142
	इ. दलालों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 दलालों से खरीद	लागू नहीं	9.87%

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26	पिछला वित्त वर्ष 2024-25
बिक्री का संकेन्द्रण**	अ. कुल बिक्री के % के रूप में दलालों को बिक्री	लागू नहीं	12.96% द्वितीयक बाजार व्यापार
	आ. दलालों की संख्या जिनके माध्यम से बिक्री की जाती है	लागू नहीं	142
	इ. दलालों को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 दलालों को बिक्री	लागू नहीं	9.54%
आर पी टी का हिस्सा	अ. खरीद (संबंधित पार्टियों के साथ खरीद/कुल खरीद)	2.15%	1.54%
	आ. बिक्री (संबंधित करने के लिए बिक्री पार्टियों/कुल बिक्री)	2.66%	1.89%
	इ. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम / कुल ऋण और अग्रिम)	लागू नहीं	लागू नहीं
	ई. निवेश (संबंधित पार्टियों में निवेश/किए गए कुल निवेश)	लागू नहीं	लागू नहीं

**खरीद और बिक्री का केंद्रीकरण लागू नहीं होता है क्योंकि यह 'सामान' से संबंधित है, न कि 'सेवाओं' से। इसलिए, इस साल इसे शामिल नहीं किया गया है।

नेतृत्व संकेतक

- वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए:

कुल प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत
3971 सत्र	प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की तुलना, कौशल विकास, फाइनेंशियल मार्केट का अध्ययन।	20.72%
30 सत्र	योग, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता से जुड़े विषय, सतर्कता जागरूकता, नई योजनाएं, फायर ड्रिल, कार्यालय के काम में हिंदी का प्रयोग	48.64%

- क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने / प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं)

यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान करें।

- हाँ, प्रक्रियाएं चल रही हैं। निदेशकों से हितों के प्रकटन के साथ-साथ निदेशकों की स्वतंत्रता की घोषणा नियमित रूप से प्राप्त की जा रही है और बोर्ड को प्रस्तुत की जा रही है। निदेशक उन कार्यसूची मर्दों पर चर्चा या निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, जिनमें

उनका व्यक्तिगत हित जुड़ा होता है। बैठकों के दौरान ऐसे विषयों पर विचार किए जाने पर हितों के टकराव से बचने के लिए वे स्वयं को चर्चा और निर्णय प्रक्रिया से अलग रखते हैं। इसके अलावा, निदेशक मंडल हर साल यह पुष्टि करता है कि उन्होंने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए तय आचार संहिता का पालन किया है।

सिद्धांत 2: व्यवसाय को वस्तुओं और सेवाओं को इस तरह से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो

आवश्यक संकेतक

1. संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश के लिए उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में शोध एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत

आर एंड डी मुख्य रूप से उत्पाद विकास, निगरानी, संशोधन, समापन के साथ-साथ इसके पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव पर जोर देने के साथ नए संस्करणों को पेश करने पर केंद्रित है। ग्राहक अनुभव और संतुष्टि वह आधार बना हुआ है जिस पर बोर्ड भर में कागज के उपयोग को कम करने सहित इस पहलू में पहल की जाती है।

पुराने ऊर्जा अक्षम उपकरणों जैसे एसी, लाइट बल्ब, लिफ्ट आदि को आधुनिक ऊर्जा कुशल उपकरणों से बदलने, नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए सौर उपकरणों की स्थापना, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्षा जल संचयन आदि पर पूंजीगत व्यय किया जाता है। इसका प्रभाव बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता, सूर्य के प्रकाश जैसे पुनर्चक्रण योग्य संसाधनों के उपयोग और पानी के संरक्षण में महसूस किया जाता है।

2. अ) क्या स्थायी सोर्सिंग के लिए संस्था के पास प्रक्रियाएं हैं? – (हाँ/नहीं)

आ) यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

अ) हाँ।

बीमा उद्योग के एक हिस्से के रूप में, हमारे संचालन मुख्य रूप से डिजिटल समाधानों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। हालांकि हमारी प्रक्रियाएं सीधे पारंपरिक विनिर्माण को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं, हम दिशानिर्देशों और प्रथाओं का पालन करने का प्रयास करते हैं जो प्रौद्योगिकी से संबंधित इनपुट के नैतिक और टिकाऊ सोर्सिंग को बढ़ावा देते हैं। हमारे संचालन की प्रकृति को देखते हुए, टिकाऊ सोर्सिंग और पहचान प्रतिशत के पारंपरिक उपाय सीधे लागू नहीं होते हैं। हालांकि, हम स्थिरता बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए व्यापक संगठनात्मक पहल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हालांकि, सस्टेनेबल सोर्सिंग के लिए कोई खास प्रक्रिया नहीं है, फिर भी हम कॉर्पोरेशन की खरीद नीति का पालन करते हैं जो उतउ के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है, प्रतिभागियों के बीच समानता सुनिश्चित होती है और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलता है। सभी अधिप्राप्तियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करके संसाधित किया जाता है, केवल भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाता है।

आ) लागू नहीं

3. उपयोगिता के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट

चूंकि निगम बीमा व्यवसाय में है, इसलिए पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग करने की सीमित गुंजाइश है। बीमा प्रोडक्ट अपने आप में इनटॅन्जीबल है। हालांकि, हमारे कार्यालयों को ई-कचरे को पुनर्चक्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सर्वर, कम्प्यूटर, कार्ट्रिज, रिबन प्राथमिक ई-अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान प्राधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है, जो निराकरण करने के बाद सभी स्थानों से हार्डवेयर ई-अपशिष्ट उठाते हैं। रि-साइक्लिंग प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाते हैं। ई-अपशिष्ट और विद्युत अपशिष्ट के संग्रह और निपटान के लिए, सुरक्षित निपटान संग्रह बॉक्स एलआईसी विविध कार्यालय परिसर में रखे गए हैं। हार्डवेयर आइटम जो जीवन के अंत में हैं, बायबैक के तहत हार्डवेयर आपूर्ति विक्रेता को सौंप दिए जाते हैं। बदले में, विक्रेता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पंजीकृत ई-अपशिष्ट निपटान विक्रेता की नियुक्ति करता है जो सभी स्थानों से हार्डवेयर उठाता है। ई-कचरा निपटान विक्रेता से एक निर्धारित प्रमाण पत्र लिया जाता है।

हम ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस देते हैं जिनमें प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी तरह के खतरनाक या गैर-खतरनाक मटीरियल का इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए, इस्तेमाल के बाद निकलने वाला कचरा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इश्योरेंस सेक्टर होने की वजह से कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ आईटी का काम करने के कारण हमारा मुख्य ध्यान डिजिटल कचरे को मैनेज करने पर होता है, न कि फिजिकल

प्रोडक्ट पर। हम जिम्मेदारी से ई-कचरे को डिस्पोज़ करके, सुरक्षित तरीके से डेटा हैंडल करके और पेपरलेस कामकाज को बढ़ावा देकर पर्यावरण पर पड़ने वाले अपने असर को कम करने पर ध्यान देते हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ़साइकल में सस्टेनेबल तरीकों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

89.08% कचरे का निपटान मेटल स्ट्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के ज़रिए किया गया है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर (MDC) कैम्पस में निकलने वाले खाने और बगीचे के कचरे को खाद में बदला जाता है और पौधों की बढ़त के लिए MDC के बगीचे में इस्तेमाल किया जाता है। पेपरलेस HRMS/TE मॉड्यूल जैसे कदमों से कागज़ के कचरे में कमी आई है। रोज़ाना का कचरा नगर पालिका को सौंप दिया जाता है।

4. क्या विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होती है (हां/नहीं)? यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत की गई विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए।

पारंपरिक अर्थों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) हमारे लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि हमारी गतिविधियां भौतिक वस्तुओं के उत्पादनसे सीधे जुड़ी नहीं है।

हालांकि, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित ई-कचरा निपटान भागीदारों के साथ सहयोग करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कचरे को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्रबंधित किया जाता है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था ने अपने किसी भी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

सेवा उद्योग में होने के कारण, सामान्य बोलचाल की भाषा में जीवन चक्र मूल्यांकन जीवन बीमा अनुबंधों पर लागू नहीं होता है। हालांकि, उत्पाद विकास के दृष्टिकोण से, आवधिक मूल्यांकन या मूल्यांकन एक आदर्श है। शुरू की गई प्रत्येक योजना में मृत्यु दर, रूग्णता, ब्याज दरों, प्रशासनिक लागतों आदि जैसे विभिन्न पैरामीटरों के संबंध में कतिपय अनुमान लगाए गए हैं। समय बीतने के दौरान, जब कभी यह महसूस किया जाता है कि उसमें लगाई गई धारणाएं और क्षेत्र से निकलने वाले वास्तविक परिणाम विभिन्न परिदृश्यों में प्रदान की गई सीमाओं से अधिक भिन्न हो रहे हैं, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है। यह एक छोर पर योजना को नियंत्रित करने वाले मापदंडों में बदलाव का रूप ले सकता है और दूसरे छोर पर योजना को वापस ले सकता है और यदि आवश्यक हो तो संशोधित योजना के साथ आ सकता है।

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उसका संक्षेप में वर्णन करें।

व्यवसाय की प्रकृति के साथ-साथ नियमित आधार पर इसकी निगरानी की जा रही है, इससे कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता या जोखिम विकसित नहीं होता है।

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जाने वाली सामग्री लागू नहीं होती है क्योंकि जीवन बीमा एक अमूर्त उत्पाद होने के नाते ऐसी प्रक्रियाओं में हिस्सा नहीं लेता है। 89.08% कचरे का निपटान MSTC के ज़रिए किया जाता है।

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मीट्रिक टन में) पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटाया गया:

एक अमूर्त उत्पाद होने के नाते, ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न नहीं होती है।

	FY 2025-26			2024-25		
	पुन उपयोग	रिसायकल	सुरक्षित निपटान	पुन उपयोग	रिसायकल	सुरक्षित निपटान
प्लास्टिक (पैकिंग सहित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ई-वेस्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	54 MT	लागू नहीं	लागू नहीं	13.24 MT
जोखिम युक्त वेस्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य वेस्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

एक अमूर्त उत्पाद होने के नाते, ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न नहीं होती है।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान और प्रचार करना चाहिए, जिसमें उनकी मूल्य श्रृंखला भी शामिल है

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों की भलाई के उपायों का विवरण:

कोटि	द्वारा कवर किए गए % कर्मचारी										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	64161	64161	100	64161	100			64161	100	शून्य	शून्य
महिला	20404	20404	100	20404	100	20404	100			शून्य	शून्य
कुल	84565	84565	100	84565	100	20404	100	64161	100	शून्य	शून्य
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य											
पुरुष	12	2	16.66	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
कुल	13	2	15.38	0	0	1	100	0	0	0	0

ख. श्रमिकों की भलाई के उपायों का विवरण:

कोटि	द्वारा कवर किए गए % कार्यकर्ता										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		दिवस देखभाल सुविधा	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी श्रमिक											
पुरुष	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है										
महिला											
कुल											
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य											
पुरुष	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है										
महिला											
कुल											

ग. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य) की भलाई के उपायों पर खर्च:

	वित्तीय वर्ष 2025-2026	वित्तीय वर्ष 2024-25
कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण उपायों पर खर्च की गई लागत	(i) समूह कार्मिक दुर्घटना लाभ - 0.00074% (ii) मेडीक्लेम:-0.05169% (iii) उच्च लागत लंबा उपचार:-0.000054% (iv) निवारक स्वास्थ्य जांच:- 0.0011%	(i) समूह कार्मिक दुर्घटना लाभ:- 0.001934% (ii) मेडीक्लेम:-0.0931228% (iii) उच्च लागत लंबा उपचार:-0.000156% (iv) निवारक स्वास्थ्य जांच- 0.002841%

इन आंकड़ों में 18% जीएसटी शामिल नहीं है।

*वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेशन के कुल रेवेन्यू के प्रतिशत के तौर पर वेलफेयर उपायों पर हुए खर्च की गणना 'नई प्रीमियम आय' के आधार पर की गई थी, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिशत की गणना कॉर्पोरेशन के कुल रेवेन्यू के आधार पर की गई है; इसलिए वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 के डेटा में अंतर है।

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	चालू वित्तीय वर्ष			पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की और प्राधिकरण के पास जमा किया (वाई/एन/एनए)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की और प्राधिकरण के पास जमा किया (वाई/एन/एनए)
पीएफ (*) पेंशन	65.74% (84565 में से 55640)	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है	निगम का अपना एलआईसी ऑफ इंडिया भविष्य निधि नंबर 1 नियम है और इसका प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है।	100% - सभी पात्र कर्मचारी इसमें शामिल हैं।	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है	निगम का अपना एलआईसी ऑफ इंडिया भविष्य निधि नियम नंबर 1 है और इसका प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है।
एनपीएस	34.26%		हाँ	100%		हाँ
उपदान	100% (84565)		निगम की एक समूह उपदान नीति है और इसका प्रबंधन निगम के पी एंड जीएस विभाग द्वारा किया जाता है।	100%		निगम की एक समूह उपदान नीति है और इसका प्रबंधन निगम के पी एंड जीएस विभाग द्वारा किया जाता है।
ईएसआई	लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें (#)	100% (84565)		सभी योजनाओं का प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है। प्रबंधन के पास न्यू इंडिया इंश्योरेंस से ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी है।	100%		सभी योजनाओं का प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है। प्रबंधन के पास न्यू इंडिया इंश्योरेंस से ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी है।

(#) कॉर्पोरेशन की सेवा से रिटायर होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद कई तरह के लाभ मिलते हैं। इनमें प्रिविलेज लीव (छुट्टी) के बदले नकद भुगतान, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ग्रुप मेडिकलेम स्कीम, ग्रुप सेविंग्स लिंकड इंश्योरेंस स्कीम के तहत जमा राशि और पेंशन लाभ (जिन्होंने इसे चुना है) शामिल हैं।

(*) जो कर्मचारी 01.04.2010 को या उसके बाद कॉर्पोरेशन की सेवा में नियुक्त हुए हैं, वे नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आते हैं और उन पर LIC ऑफ़ इंडिया प्रोविडेंट फंड नंबर 1 नियम लागू नहीं होता है; और इसके उलट भी यही बात लागू होती है।

3. कार्य स्थलों की सुगमता

क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय अलग-अलग विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं?

निगम ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार समान अवसर नीति तैयार की है। निगम के सभी कार्यालयों को नए और मौजूदा कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त पहुंच और अन्य प्रावधान करने की सलाह दी गई है।

निगम ने अपने केंद्रीय कार्यालय को विशेष सुविधाओं जैसे कि रैंप, रेलिंग, विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए भौतिक अवरोधों आदि के साथ संशोधित किया है। हमारे पास विशेष रूप से डिजाइन किए गए वॉशरूम हैं (पहुंच योग्य दरवाजे, ग्रैब रेलिंग आदि के साथ) जो कि दिव्यांग व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। हमारे पास दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप कई कार्यालयों में रैंप, ग्रैब रेलिंग आदि भी हैं। इसके अतिरिक्त, निर्माण स्थलों पर कार्यस्थलों की उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मार्ग, मचान, निर्माण लिफ्ट आदि प्रदान किए गए हैं।

दृष्टि-बाधित कर्मचारियों के लिए सहायक तकनीक: कॉर्पोरेशन के सभी कार्यालयों में सभी LINUX डेस्कटॉप पर "ORCA" नाम का स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है। इस सॉफ्टवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद के लिए, उपयुक्त ऑडियो डिवाइस/हेडफोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, कॉर्पोरेशन ने दिव्यांग कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए 'चीफ़ लाइज़न ऑफ़िसर' नियुक्त किए हैं।

RPWD एक्ट के तहत सभी ज़ोन में रैंप बनाकर 806 ब्रांच को दिव्यांगों (PwDs) के लिए सुलभ बनाया गया है। हमारे कई ऑफिस में लिफ्ट की सुविधा भी मौजूद है। जिन बिल्डिंग में लिफ्ट की सुविधा नहीं है, वहां लिफ्ट लगाने का काम किया जा रहा है। अब तक दिव्यांगों के लिए 117 टॉयलेट बनाए गए हैं। बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए ESG फ्रेमवर्क में एक्सेसिबिलिटी इंडिकेटर को शामिल किया गया है। रैंप की मदद से हमारे सभी ऑफिस को सुलभ बनाया जा रहा है।

4. क्या दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016के अनुसार संस्था के पास समान अवसर नीति है? यदि हां, तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, निगम ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार एक समान अवसर नीति अपनाई है। यह विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। समान अवसर नीति के लिए लिंक निम्नानुसार है:

लिंक: <https://licindia.in/web/guest/equal-opportunity-policy>

5. अभिभावकीय अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों की कार्य वापसी दर व प्रतिधारण दर:

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कार्यकर्ता	
	काम की दर पर लौटें	प्रतिधारण दर	काम की दर पर लौटें	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है	
महिला	100%	100%		
कुल	100%	100%		

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

स्थायी श्रमिक	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है
स्थायी कर्मचारी	हमारे पास एक कर्मचारी शिकायत निवारण पोर्टल है जिसे ई-समाधान कहा जाता है। शिकायतें कर्मचारी शिकायत अधिकारी को ऑन-लाइन अप्रेषित की जाती हैं। अगले उच्च अधिकारी के पास अपील करने का प्रावधान है। शिकायत समाधान का समय 90 दिन है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए केन्द्रीय कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, मंडल कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियां भी हैं।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य	हाँ।

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघ (संघों)/यूनियनों में कर्मचारियों/श्रमिकों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों की, जो संघ (संघों) या संघ का हिस्सा हैं	% (बी/ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों/श्रमिकों की, जो संघों या संघ का हिस्सा हैं	% (डी/सी)
	(क)	(ख)	% (बी/ए)	(ग)	(डी)	% (डी/सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	84,565	निगम किसी यूनियन को मान्यता नहीं देता है। अतः आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।	लागू नहीं	91,606	निगम किसी यूनियन को मान्यता नहीं देता है। अतः आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।	लागू नहीं
- पुरुष	64,161		लागू नहीं	69,740		लागू नहीं
- महिला	20,404		लागू नहीं	21,866		लागू नहीं
कुल स्थायी श्रमिक	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है					
- पुरुष						
- महिला						

8. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26				पिछला वित्त वर्ष 2024-25					
	कुल (क)	स्वास्थ्य पर और सुरक्षा उपाय		पर निपुणता उन्नयन		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (च)	% (च/घ)	संख्या (छ)	% (छ/घ)
कर्मचारी										
पुरुष	64,161	*	*	52,566	81.93%	69,740	**	**	46,081	66.07%
महिला	20,404	*	*	16,324	80.00%	21,866	**	**	15,196	69.50%
कुल	84,565	48,368	57%	68,890	81.46%	91,606	**	**	61,277	66.89%

* हमारे सभी इन-हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 'योग और स्वास्थ्य' सेशन को शामिल किया गया। 21 जून 2025 को पूरे भारत में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) मनाया गया।

सभी 113 डिवीज़नल ऑफिस की ओर से एक दिन का 'एम्प्लॉई एंगेजमेंट प्रोग्राम' (EEP) आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में देश भर के हमारे 57% कर्मचारियों-रिकॉर्ड क्लर्क से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तक-को शामिल किया गया। EEP एजेंडा में 'स्वास्थ्य और वेलनेस' पर एक सेशन भी शामिल था, जिसमें 48,368 कर्मचारी शामिल हुए। इस प्रोग्राम का मकसद अपनापन की भावना को बढ़ावा देना, टीमवर्क को प्रोत्साहित करना और कर्मचारियों व संगठन के बीच भावनात्मक और पेशेवर जुड़ाव को मजबूत करना था।

** वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए यह जानकारी शामिल नहीं की गयी है

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण:

कोटि	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26			पिछला वित्त वर्ष 2024-25		
	कुल (ए)	संख्या (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	संख्या (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
पुरुष	64,161	64,161	100	69,740	69,740	100
महिला	20,404	20,404	100	21,866	21,866	100
कुल	84,565	84,565	100	91,606	91,606	100

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

अ. क्या इकाई द्वारा एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं) यदि हां, तो ऐसी प्रणाली क्या है?

हाँ, कर्मचारियों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगम के कड़े दिशा-निर्देश हैं। इसमें अग्नि सुरक्षा के लिए नीति, अग्नि सुरक्षा के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनमें अग्निशमन उपकरण, अग्नि शमन ड्रिल, हमारे सभी कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा समितियों का गठन, विद्युत और अग्नि सुरक्षा पैरामीटरों की आवधिक जांच आदि से संबंधित नियम शामिल हैं। साथ ही, प्रमुख विभागों तक सीमित पहुंच का कार्य शुरू किया गया है। हमारे पास सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा उपायों पर एसओपी हैं, जिसमें किसी भी घटना के मामले में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा परिभाषित भूमिकाओं का पालन किया जाना है। अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ताकि कर्मचारी तेजी से और कुशलता से प्रतिक्रिया दें और प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ हो। कर्मचारियों को समूह बीमा, समूह अवधि बीमा और 24 घंटे समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, कर्मचारियों को ग्रुप मेडिकलेम स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है जहां कर्मचारियों और उनके परिवारों को अपने और अपने परिवारों के लिए अतिरिक्त कवर लेने के विकल्प के साथ अस्पताल में भर्ती करने के लिए कवर किया जाता है। निवारक स्वास्थ्य जांच योजना और उच्च लागत उपचार के मामले में चिकित्सा व्यय की अनुग्रह प्रतिपूर्ति की योजना भी कर्मचारियों के लिए अन्य लाभ हैं।

इसके अलावा, सभी कर्मचारी मेडिकलेम सुविधा के दायरे में आते हैं। आग से बचाव और सुरक्षा संबंधी गाइडलाइंस (SOP) और सिक्योरिटी मैनुअल भी मौजूद हैं।

आ. इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर काम से संबंधित खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

लागू नहीं है क्योंकि हम एक वित्तीय सेवा इकाई हैं।

इ. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को हटाने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हाँ /नहीं)

लागू नहीं

ई. क्या संस्था के कर्मचारियों/श्रमिकों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच है? (हाँ /नहीं)

हाँ। सभी कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना पॉलिसी के तहत कवर किए जाते हैं। कंपनी के पास अच्छी तरह से परिभाषित चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल नीतियां हैं। समूह सावधि बीमा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर सभी कर्मचारियों के लिए लागू हैं। स्वास्थ्य जांच, योग, नेत्र जांच, अस्थि घनत्व आदि जैसी पहल और विशेषज्ञों द्वारा स्वस्थ और खुशहाल जीवन शैली को शिक्षित और सक्षम करने के लिए बातचीत की जाती है।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्न स्वरूप में:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
विगत समय चोट लगने की आवृत्ति दर (इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट) (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख- व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारियों	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारियों	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं
मरने वालों की संख्या	कर्मचारियों	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं
उच्च परिणाम काम से संबंधित चोट या बीमार स्वास्थ्य (घातक घटनाओं को छोड़कर)	कर्मचारियों	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं

12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थान सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

कार्यालय परिसर और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड और चौकीदार नियुक्त किए गए हैं। विभिन्न कार्यालयों के प्रवेश द्वारों पर बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं। निगम के संवेदनशील विभागों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा समितियां गठित की गई हैं, नियमित आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है और निकासी अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। अग्नि सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। निगम का प्रत्येक कर्मचारी मासिक परिवेश सर्वेक्षण में अपनी रेटिंग देता है, जहां कार्यालयों में सफाई के विभिन्न मापदंडों के आधार पर रेटिंग दी जाती है। सफाई और रिकॉर्ड रखरखाव को प्रोत्साहित करने के लिए मॉडल डीओ और मॉडल बीओ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। नियमित कीट नियंत्रण सेवाएं, कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों की सफाई, स्क्रेप का निपटान, खाली स्थानों की पहचान और उचित उपयोग, पौधे लगाना, वर्षा जल संचयन, विकलांगों के लिए रैंप और रेलिंग की स्थापना, सौर पैनल लगाना आदि सुरक्षित और स्वच्छ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए की जा रही हैं। आज की तारीख में हमारे अधिकांश कार्यालय एलईडी लाइटिंग का उपयोग कर रहे हैं।

हमने अपने सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध प्रचलित नीति के बारे में जागरूक किया है तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में भी जागरूक किया है।

ऑफिस परिसर को साफ-सुथरा रखा जाता है। सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए कई अतिरिक्त उपाय किए गए हैं, जैसे पेस्ट कंट्रोल सर्विस, आग बुझाने के उपकरण, इमरजेंसी एग्जिट, हर फ्लोर पर फ्लोर मार्शल, फायर ड्रिल और सिक्योरिटी सर्विस। इसके अलावा, फायर एंड सेफ्टी एडवाइजरी (SOP) और सिक्योरिटी मैनुअल भी मौजूद हैं।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

14. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का% जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	हमारे सभी कार्यालयों का निरीक्षण हर साल हमारी निरीक्षण टीमों द्वारा किया जाता है
काम करने की स्थिति	

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं से निपटने के लिए, बैगेज स्कैनर मशीनें और अग्निशामक यंत्र लगाए गए हैं, और सुरक्षा गार्डों को सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए फायर एंड सेफ्टी एडवाइजरी (SOP) और सिक्वोरिटी मैनुअल मौजूद हैं।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज देती है।

कर्मचारी: हाँ। निगम कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवारों को सहायता के रूप में निम्नानुसार लाभ प्रदान करता है:

1. समूह बीमा -2004 यदि चुना गया हो
2. समूह आवधिक बीमा जिसका भुगतान नामिती/कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाता है। यह विशेष रूप से पेंशन के कम्यूटेशन के नुकसान से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है, अगर कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक निगम की सेवाओं में बना रहता है।
3. समूह बचत लिंकड बीमा का जोखिम और बचत भाग
4. 24 घंटे ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट कवर यदि कर्मचारी की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी।

इसके अलावा, मृतक कर्मचारी के परिवार को निम्नलिखित टर्मिनल देय राशियों का भुगतान किया जाता है:

1. ग्रेच्युटी का भुगतान तब भी किया जाता है जब कर्मचारी ने कंपनी के साथ पांच साल की निरंतर सेवा पूरी नहीं की हो। इसके अलावा, ग्रेच्युटी की गणना एलआईसी ऑफ इंडिया (स्टाफ) नियम, 1960 और ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के अनुसार भी की जाती है और मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को उच्चतर भुगतान किया जाता है।
2. यदि लागू हो तो अतिरिक्त ग्रेच्युटी का भुगतान भी किया जाता है।
3. पारिवारिक पेंशन यथा लागू
4. भविष्य निधि में कर्मचारियों का योगदान
5. निधि के लिए निगम अंशदान (पीएफ ऑप्टीज़ के लिए)
6. पीएल नकदीकरण के बदले एक मुश्त

मृतक कर्मचारी के पति/पत्नी अथवा आयु पात्र बच्चे को अनुकंपा के आधार पर रोजगार का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जहाँ भी लागू हो

निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है

2. संस्था द्वारा किए गए उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान करें कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा धानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा की गई है।

निगम यह सुनिश्चित करता है कि निगम के प्रेषण के भीतर लेनदेन पर लागू करों की कटौती की जाती है और मौजूदा नियमों के अनुसार जमा की जाती है। आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में इस गतिविधि की समीक्षा की जाती है। निगम अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों से अपेक्षा करता है कि वे पारदर्शिता और जवाबदेही के व्यावसायिक जिम्मेदारी, सिद्धांतों और मूल्यों को बनाए रखेंगे। यह चैनल भागीदारों के साथ निष्पादित सेवा स्तर समझौते का भी हिस्सा है।

GST का भुगतान वैल्यू चेन पार्टनर को किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसे ऋद्ध अधिकारियों को जमा कर दिया गया है। वैल्यू चेन पार्टनर के बिल से कानूनी कटौतियां की जाती हैं और उन्हें संबंधित विभाग में जमा किया जाता है।

ऑनबोर्डिंग के समय कानूनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जांच की जाती है। एग्रीमेंट में ऐसी शर्तें शामिल होती हैं जिनके तहत वेंडर्स को सभी लागू लेबर और टैक्स कानूनों का पालन करना होता है। नियमों का पालन न करने पर पेनल्टी, पेमेंट रोकने और एग्रीमेंट खत्म करने जैसी शर्तें शामिल हैं; साथ ही, नियमों के पालन की समय-समय पर जांच भी की जाती है। वेंडर्स से चालान, रिटर्न, वेज रजिस्टर, PF/ESIC कंट्रीब्यूशन के सबूत और GST सहित टैक्स फाइलिंग की कॉपी ली जाती हैं। कानूनी नियमों के पालन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और सबूत मिलने के बाद ही पेमेंट किया जाता है। इनवाइस का मिलान GST पोर्टल के डेटा से किया जाता है। ऑडिट के मकसद से सभी वेरिफिकेशन और बातचीत का सही रिकॉर्ड रखा जाता है।

3. उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या बताना, जिन्हें कार्य संबंधी उच्च परिणाम वाली चोट/अस्वस्थता/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की प्रश्न 11 में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:

श्रेणी	कुल संख्या प्रभावित कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या		नहीं। उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कर्मचारियों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट: निगम में 'वर्कर्स' (Workers) नाम की कर्मचारियों की कोई श्रेणी नहीं है।

4. क्या संस्था निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर के अंत के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ/नहीं)

हाँ। सभी कर्मचारियों को इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों और बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने प्रबंधकीय, कार्यात्मक और व्यवहार कौशल में उत्कृष्टता के लिए निगम के साथ अपने कैरियर के दौरान निरंतर सीखने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण मंच प्रदान किए गए हैं। इस तरह के निरंतर प्रशिक्षण कर्मचारियों को उनके कार्य प्रदर्शन को बढ़ाने और बढ़ाने में मदद करते हैं। निगम का एक स्व-शिक्षण, स्व-मूल्यांकन पोर्टल 'ज्ञानपीठ' भी है जो निगम के विभिन्न कार्यों, नियमों / विनियमों को कवर करने वाली सामग्री प्रदान करता है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अपने वित्त और स्वास्थ्य का प्रबंधन करने में मदद मिल सके।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन पर विवरण:

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	सरकार या अन्य वैधानिक एजेंसियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट/समझौते में शर्तें शामिल की जाती हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनका पालन हो। ऐसे वैल्यू चेन पार्टनर्स से सालाना सर्टिफिकेशन भी लिया जाता है
काम करने की स्थिति	यह सुनिश्चित किया जाता है कि कामगार क्षतिपूर्ति नीति मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा ली जाए। इसके अलावा सुरक्षा हेलमेट, बाँड़ी हार्नेस, सुरक्षा जूते और अन्य सुरक्षा मानदंडों के प्रावधान के लिए भी सुनिश्चित किया जाता है। उचित वॉशरूम, पीने योग्य पानी आदि प्रदान करके साइट की स्वच्छता की स्थिति बनाए रखना।

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के (वैल्यू चैन पार्टनर) स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थिति के मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

जीवन बीमा निगम का प्राथमिक व्यवसाय है। हालांकि, वित्तीय नियोजन समाधान जो व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, गंभीर बीमारियों के साथ-साथ मृत्यु जैसी आकस्मिकताओं के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। लाइफ कवर के साथ, विभिन्न बीमा उत्पाद परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और व्यक्तियों को परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं।

ग्राहकों में स्व-नियोजित व्यक्तियों के साथ-साथ वेतनभोगी व्यक्ति और उनके आश्रित, प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति आदि शामिल हैं। हमारे जीवन बीमा उत्पाद कमाने वाले की आकस्मित मृत्यु के खिलाफ परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं, मृत्यु, दुर्घटना, गंभीर बीमारी आदि के मामले में लिए गए ऋण के लिए सुरक्षा कवर प्रदान करते हैं। यह बचत, निवेश और बच्चे की शिक्षा, विवाह आदि के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने का एक उपकरण भी है।

पॉलिसीधारक हमारे स्टैकहोल्डर्स में से एक हैं और उनकी पहचान उनके पॉलिसी नंबर के आधार पर की जाती है। ज़रूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जाता है, जैसे कि प्रीमियम/लोन/लोन के ब्याज का पेमेंट, SB/मैच्योरिटी/एन्युइटी पेमेंट का समय आने पर, आदि। क्लेम से जुड़े मामलों में, हम उन स्टैकहोल्डर्स की पहचान करते हैं जिनकी पॉलिसी 'पेड-अप' स्थिति में हैं और अगले 6 महीनों में मैच्योर होने वाली हैं, और उन स्टैकहोल्डर्स की भी जिनकी पॉलिसी चालू हैं और अगले 3 महीनों में मैच्योर होने वाली हैं। सिस्टम से कुछ आउटपुट जेनरेट होते हैं जिन्हें यूजर डिपार्टमेंट हर महीने चलाता है ताकि संबंधित पॉलिसीधारकों को सूचना, रिमाइंडर आदि भेजे जा सकें।

हम संगठनों को ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी देते हैं, ताकि वे अपने कर्मचारियों के लिए लाइफ कवर के साथ-साथ ग्रेच्युटी और सुपरएनुएशन मैनेजमेंट की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें।

जीवन बीमा के हमारे व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, हमारे जोखिम और अवसर मानव पूंजी, जिम्मेदार निवेश, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, वित्त तक पहुंच, उभरते जोखिम और शासन के आसपास घूमते हैं। तदनुसार, हमारे प्रमुख हितधारकों को आंतरिक हितधारकों और बाहरी हितधारकों के रूप में पहचाना जा सकता है। आंतरिक हितधारक हमारे कर्मचारी और एजेंट हैं जबकि बाहरी हितधारक वे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यवसाय में योगदान करते हैं। हमारे कुछ प्रमुख बाहरी हितधारक हैं: निवेशक और शेयरधारक, ग्राहक (पॉलिसीधारक), सरकार और नियामक निकाय, व्यापार भागीदार (सीए / ब्रोकर / आईएमएफ / सीएससी), वितरण चैनल।

2. आपकी इकाई के लिए कुंजी के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति की सूची बनाएं।

हितधारक समूह	चाहे कमजोर और हाशिए वाले समूह के रूप में पहचाना जाए	संचार के चैनल (ई-मेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पत्र, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट)	सगाई की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/ अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह की सगाई के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा।
निवेशक और शेयरधारक	नहीं	आवश्यकता के अनुसार: ईमेल, वार्षिक सामान्य बैठक, त्रैमासिक परिणाम, स्टॉक पर फाइलिंग एक्सचेंज, प्रेस विज्ञापन, मीडिया इंटरैक्शन, समाचार पत्रों के लिए साक्षात्कार	त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परिणाम और वार्षिक आम बैठक। कॉर्पोरेट की फाइलिंग स्टॉक एक्सचेंजों के साथ घोषणाएं।	निगम की रणनीति पर अद्यतन प्रदान करना, विभिन्न नियामक तंत्रों के माध्यम से शिकायतों का निवारण।
कर्मचारियों	नहीं	सीधा संपर्क, ई-मेल, कर्मचारी वेबसाइट, एसएमएस, कॉल, नोटिस बोर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग	नियमित रूप से	सूचना साझा करना, और प्रश्नों को संबोधित करना। विभाग में कार्य प्रगति पर नियमित जुड़ाव को समझना मार्केटिंग गतिविधियों की समीक्षा करना और उनसे जुड़ी चिंताओं व उनके समाधान।
ग्राहकों	नहीं	सूचना पत्र, एसएमएस, एलआईसी डिजिटल ऐप, व्हाट्सएप माय एल आई सी एप एसबी और परिपक्वता मामलों के मामले में संदेश और ईमेल। बकाया दावों और एनईएफटी अद्यतन के लिए विज्ञापन। हमारी फील्ड फोर्स, जैसे कि एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर, पॉलिसीहोल्डर्स से ज़रूरी दस्तावेज़ या जानकारी जमा करवाने के लिए समय-समय पर फॉलो-अप करती है।	बार-बार या जब और जब आवश्यक हो।	नए ग्राहक प्राप्त करना और मौजूदा ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करना; दावों के प्रसंस्करण को सक्षम करने के लिए देय दावे और प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यकताओं के बारे में उन्हें सूचित करना, हमारी चिंता नवीनतम पता और मोबाइल नंबर की अनुपलब्धता है। शुरु की गई नई ऑनलाइन योजनाओं की जानकारी देना, विपणन गतिविधियों की समीक्षा करना और उनकी चिंताओं और समाधानों को समझना पॉलिसीधारकों को भुगतान देय होने के साथ-साथ पॉलिसीधारकों से देय होने पर जानकारी और उनके द्वारा अनुरोधित सेवाओं के बारे में अपडेट।

हितधारक समूह	चाहे कमजोर और हाशिए वाले समूह के रूप में पहचाना जाए	संचार के चैनल (ई-मेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पत्र, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट)	सगाई की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/ अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह की सगाई के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा।
व्यापार भागीदार (सीए/ब्रोकर/ आईएमएफ/सीएससी)	नहीं	ईमेल, एसएमएस, मीटिंग और वेबसाइट काल के माध्यम से	बार-बार या जब और जब आवश्यक हो	मौजूदा व्यवसाय की सेवा और आगे विस्तार की गुंजाइश
सरकार और नियामक निकाय	नहीं	ईमेल, व्यक्तिगत मीटिंग्स, कॉल, वीडियो कॉल	जब और जब आवश्यक हो	नियामक अनुपालन, निरीक्षण और शिकायत मामलों में
वितरण चैनल: प्रीमियम पॉइंट, एजेंट, सीएलआईएस, सीओएस, डीएसए, सीएलआईए / समुदाय-भावना	नहीं	संचार के कई चैनल - भौतिक और डिजिटल	बार-बार या जब और जब आवश्यक हो	मौजूदा पॉलिसीधारक को सेवाएं प्रदान करना और नए व्यवसाय की खरीद करना
	नहीं	समाचार पत्र, विज्ञापन, आदि	नियमित आधार पर	बीमा जागरूकता

नेतृत्व संकेतक

1. **आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को इस तरह के परामर्श से प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है।**

बोर्ड और इसकी समितियों को हितधारकों की प्रतिक्रिया सहित विविध विषयों पर समय-समय पर अपडेट प्राप्त होते हैं। सरकार और विनियामक निकायों के साथ जुड़ने के लिए, बैठकों, सम्मेलनों, मंचों और ईमेल का उपयोग किया जाता है। निगम विनियामक निकायों से परामर्श पत्रों का निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर जवाब देता है। बोर्ड में अलग-अलग समितियाँ हैं और प्रत्येक समिति की एक परिभाषित भूमिका और चार्टर है। हम सर्वेक्षण, एसएमएस, कॉल सेंटर, विज्ञापन और सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतों, नई पहलों, सेवाओं और उत्पादों के बारे में ग्राहकों से जुड़ते हैं। सर्वेक्षणों और फीडबैक से ग्राहक विश्लेषण का उपयोग अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, सेवा पेशकशों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। निगम अपने कर्मचारियों को महत्व देता है और पर्यावरणीय प्रभाव और अन्य मामलों को कम करने के लिए शिकायतों, चिंताओं और विचारों को संबोधित करने पर सक्रिय रूप से उनका इनपुट मांगता है।

निगम की निवेशक संबंध टीम निवेशकों और बाजार विश्लेषकों के साथ जुड़ती है। विश्लेषकों की रिपोर्ट के प्रमुख संकेतक और निवेशकों की बैठक से फीडबैक निगम के बोर्ड को रखे जाते हैं। शेयरधारकों द्वारा उठाई गई शिकायतें और प्रश्न और समाधान की स्थिति बोर्ड की हितधारक संबंध समिति के साथ-साथ निगम के बोर्ड के समक्ष रखी जाती है। बोर्ड की ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) समिति निगम की ईएसजी गतिविधियों की समीक्षा करती है। शेयरधारकों द्वारा आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर उठाए गए प्रश्नों को, यदि कोई हो, चर्चा के लिए रखा जाता है। बोर्ड की पॉलिसीधारक सुरक्षा, शिकायत निवारण और दावा निगरानी समिति पॉलिसीधारकों के हितों से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करती है।

2. **क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण, और सामाजिक विषयों (हां/नहीं) की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए किया जाता है। यदि हां, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया था।**

जी हां शेयरधारकों द्वारा उठाई गई शिकायतों और प्रश्नों तथा समाधान की स्थिति को बोर्ड की स्टेकहोल्डरों की संबंध समिति के समक्ष रखा जाता है जिसकी कम से कम वर्ष में 2 बार बैठक होती है। इसे प्रत्येक बैठक में निगम के बोर्ड के समक्ष भी रखा जाता है। आथक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर यदि कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन्हें चर्चा के लिए रखा जाता है।

निगम ने लंबे समय से उन ग्राहकों से प्रतिक्रिया के महत्व और उपयोगिता को समझा है जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं। इसके अतिरिक्त, आइडिया बॉक्स में योगदान के रूप में सभी कर्मचारियों से प्रतिक्रिया मांगी जाती है, जिसके लिए चयनित और कार्यान्वित किए गए सर्वोत्तम विचारों के लिए प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिए जाते हैं। यह स्तरित दृष्टिकोण जमीनी स्तर पर बारीकियों से संबंधित मामलों को उच्च स्तरों पर मैक्रो मुद्दों तक हमारे ध्यान में लाता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद और सर्विसिंग पहलुओं में सूचित परिवर्तन होते हैं।

3. **कमजोर/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों के साथ सहभागिता के मामलों और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा प्रदान करना।**

कमजोर/सीमांत हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए, निगम ने पहुंच और वित्तीय समावेशन में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहलों को लागू किया है:

अनुकूलित उत्पाद प्रसाद: कम आय वाले व्यक्तियों, ग्रामीण आबादी और अन्य अयोग्य समूहों के लिए बीमा उत्पाद विकसित किए गए हैं। इन उत्पादों को समझने और पहुंच में आसानी सुनिश्चित करने के लिए सरलीकृत सुविधाओं के साथ किफायती प्रीमियम की पेशकश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमारे माइक्रो-इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए प्लान उपलब्ध हैं। साप्ताहिक भुगतान पद्धति सहित सुविधाजनक भुगतान विधियां उपलब्ध हैं। माइक्रो-बीमा पॉलिसीधारकों को एनजीओ और बंधे एजेंटों के माध्यम से सेवित किया जाता है।

प्रौद्योगिकी-संचालित आउटरीच: मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच का विस्तार किया जहां पारंपरिक बैंकिंग बुनियादी ढांचा सीमित है। निगम के मोबाइल एप्लिकेशन सूचना और नीति सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हितधारक अपनी नीतियों को दूरस्थ रूप से प्रबंधित कर सकते हैं।

गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग: हम गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ भागीदारी करते हैं जो सीधे हाशिए के समूहों के साथ काम करते हैं। यह हमें विश्वसनीय स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से कमजोर/हाशिए वाले हितधारक तक पहुंचने में मदद करता है, बेहतर जुड़ाव और विश्वास-निर्माण सुनिश्चित करता है।

शिकायत निवारण: निगम ने पॉलिसीधारकों के लिए समर्पित हेल्पलाइन, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए हैं, जिसमें हाशिए के हितधारक भी शामिल हैं ताकि वे चिंताओं को दूर कर सकें।

चैनल पार्टनर्स के लिए प्रशिक्षण: कॉर्पोरेशन का मार्केटिंग फील्ड फोर्स चैनल पार्टनर्स को कमजोर ग्राहकों के साथ जुड़ने और उनकी सेवा करने के तरीके पर प्रशिक्षण प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि फ्रंट-लाइन स्टाफ इन हितधारकों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सुसज्जित है।

जी जे एफ (GJF): यह फ़ाउंडेशन पारदर्शी और ईमानदार बने रहने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेहतरी के लिए लगातार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोजेक्ट और स्कॉलरशिप चुनने के नियम पारदर्शी हैं। LIC GJF समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है जो उसके उद्देश्यों - जैसे गरीबी दूर करना, शिक्षा, चिकित्सा सहायता और देश भर में आम लोगों के काम आने वाले अन्य कार्यों - से जुड़े हों। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ जुड़ने का तरीका प्रोजेक्ट वाली जगह के पास मौजूद LIC डिविज़नल ऑफिस के सर्विस प्रतिनिधियों के ज़रिए होता है। इन संपर्कों के आधार पर, ज़रूरतमंद समुदायों को सशक्त बनाने और विकास के लिए टिकाऊ अवसर पैदा करने के लिए स्कॉलरशिप देना, स्किल डेवलपमेंट में मदद और कल्याणकारी पहल जैसे खास कदम उठाए गए। ये प्रयास समावेश, करुणा और सामाजिक बदलाव के प्रति फ़ाउंडेशन की मज़बूत प्रतिबद्धता को दिखाते हैं।

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानव अधिकारों के मुद्दों और इकाई की नीति (ओं) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

श्रेणी	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26			विगत वित्तीय वर्ष 2024-25		
	कुल (ए)	की संख्या कर्मचारी/ कामगार कवर किया गया (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	की संख्या कर्मचारी/ कामगार कवर किया गया (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारियों						
स्थायी	84,565	31,597	37.36%	91,606	33,371	36.43%
स्थायी के अलावा अन्य	13	NA	NA	14	0	0
कुल कर्मचारी	84,578	31,597	37.36%	91,620	33,371	36.42%
श्रमिक						
स्थायी	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है					
स्थायी के अलावा अन्य						
कुल कार्यकर्ता						

2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान किए गए न्यूनतम वेतन का विवरण:

श्रेणी	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26					पिछला वित्त वर्ष 2024-25				
	कुल (ए)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)		संख्या (ई)	% (ई/डी)	संख्या (एफ)	% (एफ/डी)
कर्मचारियों										
स्थायी	84,565	शून्य	शून्य	84,565	100	91,606	शून्य	शून्य	91,606	100
पुरुष	64,161	शून्य	शून्य	64,161	100	69,740	शून्य	शून्य	69,740	100
महिला	20,404	शून्य	शून्य	20,404	100	21,866	शून्य	शून्य	21,866	100
स्थायी के अलावा अन्य	13	शून्य	शून्य	13	100	14	शून्य	शून्य	14	100
पुरुष	12	शून्य	शून्य	12	100	13	शून्य	शून्य	13	100
महिला	1	शून्य	शून्य	1	100	1	शून्य	शून्य	1	100
श्रमिक**										
स्थायी	निगम में "श्रमिक" के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है									
पुरुष										
महिला										
स्थायी के अलावा अन्य										
पुरुष										
महिला										

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:

अ. माध्यिका पारिश्रमिक/मजदूरी:

वित्त वर्ष 2025-26	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का माध्यिका पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का माध्यिका पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	4	60,56,100.58	0	लागू नहीं
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक(के एम पी) (निदेशक के आलावा)	6	58,27,293.99	0	लागू नहीं
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	64,152	20,85,996.18	20,404	23,23,205.77

*पारिश्रमिक के विवरण में केवल निगम के सीईओ और एमडी तथा प्रबंध निदेशकों के पारिश्रमिक शामिल हैं। इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और बोर्ड विविधता ('बोर्ड नीति') पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निगम के स्वतंत्र निदेशक बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि सरकारी नामित निदेशक कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

आ. निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी:

	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी	24.77%	24.48%

4. क्या आपके पास मानव अधिकारों के प्रभावों या व्यवसाय के कारण या योगदान किए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार एक केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है? (हाँ/नहीं)

कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) मानव संसाधन प्रशासन के लिए जिम्मेदार है और प्रबंधन कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मानवाधिकार प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे की देखरेख और समाधान करेगा।

5. मानव अधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

निगम के पास शिकायत के निवारण के लिए एक आंतरिक तंत्र प्रणाली है। शिकायतों को किसी भी कर्मचारी द्वारा इंटरनेट साइट पर ई-समाधान नामक पोर्टल पर पंजीकृत किया जा सकता है। इन्हें कर्मचारी शिकायत अधिकारी को ऑनलाइन भेजा जाएगा। पोर्टल के माध्यम से अगले उच्च अधिकारी को अपील करने का भी प्रावधान है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार, विभाग ने महिलाओं की स्थिति सुधरने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। निगम के सभी कार्यालयों में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। निगम की महिला कर्मचारी पुरुष कर्मचारियों के बराबर हैं।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26			पिछला वित्त वर्ष 2024-25		
	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	16	5	इस रिपोर्ट की तारीख तक सभी 5 शिकायतें सुलझा ली गई हैं।	9	2	वित्तीय वर्ष 2025-2026 में बंद
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बाल श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वेतन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कॉर्पोरेशन में वर्कर्स (थीज़श्री) नाम की कर्मचारियों की कोई श्रेणी नहीं है।

7. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:

	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के तहत कुल शिकायतें दर्ज की गईं।	16	9
महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के % के रूप में POSH पर शिकायतें	0.08%	0.041%
पॉश पर शिकायतों को बरकरार रखी गईं	7	2

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र

निगम ने शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र सहित एक विस्तृत सूचना प्रदाता प्रक्रिया निर्धारित की है। व्हिसल ब्लोअर नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्हिसल ब्लोअर और/या संरक्षित प्रकटीकरण संसाधित करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने के लिए पीड़ित नहीं किया जाता है। व्हिसल ब्लोअर निम्नलिखित संरक्षण का हकदार है:

- निगम यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्हिसल ब्लोअर जिसने इस नीति के तहत प्रकटीकरण किया है, किसी भी कार्यवाही की शुरुआत से या अन्यथा केवल इस आधार पर पीड़ित नहीं है कि ऐसे शिकायतकर्ता ने इस नीति के तहत जांच में प्रकटीकरण किया था या सहायता प्रदान की थी।
- जहां कहीं भी सूचना प्रदाता ने उत्पीड़न/उत्पीड़न का आरोप लगाया है, सतर्कता अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि पहचान ज्ञात हो जाती है तो उसे बार-बार स्थानान्तरण आदि के माध्यम से उत्पीड़ित/पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए।
- यदि कोई सूचना प्रदाता सुरक्षा चाहता है और यह सूचित करता है कि उसका जीवन खतरे में है तो सतर्कता अधिकारी मामले की जांच करेगा और सूचना प्रदाताओं को सुरक्षा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ गृह मंत्रालय/राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाने के लिए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर को अपनी सिफारिश भेजेगा।

- iv. व्हिसलब्लोअर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी जब तक कि न्यायालय/अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य के लिए वारंट न हो। इसके अलावा, 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' के तहत, कॉर्पोरेशन ने उत्पीड़न के मामलों में शिकायत करने वाली महिला को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जांच चलने के दौरान, कॉर्पोरेशन पीड़ित महिला या आरोपी का तबादला किसी दूसरी जगह कर सकता है, पीड़ित महिला को तीन महीने तक की छुट्टी दे सकता है, या कोई और राहत दे सकता है; जैसे कि जांच के दौरान आरोपी को पीड़ित महिला के काम के प्रदर्शन पर रिपोर्ट देने या उसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखने से रोका जा सकता है।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)

- हाँ, जहाँ भी आवश्यक हो

10. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	शून्य
मजबूर/अनैच्छिक श्रम	शून्य
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
वेतन	शून्य
अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य

निगम तालिका में उल्लिखित विषयों पर सभी लागू कानूनों का अनुपालन करता है।

11. उपरोक्त प्रश्न 10 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

- लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. मानव अधिकारों की शिकायतों/शिकायतों को संबोधित करने के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।

निगम का मानना है कि उसने अपने सभी व्यवहारों में मानवाधिकारों के बुनियादी सिद्धांतों को बरकरार रखा है। यह इसके मानवाधिकार वक्तव्य के अनुरूप है। निगम नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मचारियों को आचार संहिता के बारे में संवेदनशील बनाता है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे किसी भी नीति या प्रक्रिया में किसी भी उल्लंघन/उल्लंघन के संबंध में किसी भी शिकायत को उठाएं, या किसी भी कार्य की रिपोर्ट करें जो निगम की आचार संहिता या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम नीति, रिश्तत विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति, धन शोधन विरोधी नीति, इनसाइडर ट्रेडिंग कोड, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी, धोखाधड़ी-रोधी नीति, सूचना और साइबर सुरक्षा नीति या कार्यस्थल पर कर्मचारी आचरण को नियंत्रित करने वाली कोई अन्य नीति जिसे समय-समय पर परिभाषित किया जा सकता है या कोई अन्य वैधानिक या नियामक कानून जो लागू हो सकता है।

2. किए गए किसी भी मानवाधिकार के दायरे और कवरेज का विवरण।

निगम की शासन प्रक्रिया के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है।

3. क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई का परिसर/कार्यालय अलग-अलग सक्षम आगंतुकों के लिए सुलभ है?

- निगम ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार समान अवसर नीति तैयार की है। निगम के सभी कार्यालयों को यह सलाह दी गई है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त पहुंच और अन्य प्रावधान किए जाएंगे। योगक्षेम भवन में स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय दिव्यांग जनों के लिए सुलभ है।
- निगम ने अपने केंद्रीय कार्यालय को विशेष सुविधाओं जैसे रैंप, रेल, विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए भौतिक अवरोधकों आदि के साथ संशोधित किया है ताकि इसे अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाया जा सके। दिव्यांग जनों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास विशेष रूप से डिजाइन किये गए शौचालय (सुलभ मार्ग वाले दरवाजों, ग्रैब रेल्स आदि के साथ)

उपलब्ध है। इसी तरह की सुविधाएं हमारे शेष कार्यालयों में अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप शामिल की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, निर्माण स्थलों पर पाथवे एप्रोच, मचान, निर्माण लिफ्ट आदि प्रदान करके कार्यस्थलों की उचित पहुंच सुनिश्चित की जाती है।

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन पर विवरण:

ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
बाल श्रम	शून्य
बलात् श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य
वेतन	शून्य
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य

काम पूरा करने के लिए वैल्यू चेन पार्टनर का मूल्यांकन करने में, टेंडर डॉक्यूमेंट में योग्य वैल्यू चेन पार्टनर को चुनने के लिए प्री-कालिफिकेशन क्राइटेरिया शामिल होता है और उसके बाद योग्य कॉन्ट्रैक्टर / कंस्ट्रक्शन एसोसिएट / वैल्यू चेन पार्टनर का चयन किया जाता है। काम पूरा होने के बाद, हम वैल्यू चेन पार्टनर से कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेते हैं। साथ ही, हम एक गोपनीय रिपोर्ट भी तैयार करते हैं जिसमें हम वैल्यू चेन पार्टनर के परफॉर्मेंस के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हैं।

5. उपरोक्त प्रश्न 4 में दिए गए आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

हम अपने वैल्यू-चेन पार्टनर्स के साथ नए और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़रूरी मैट्रिक्स को शामिल करते हैं। यह पक्का किया जाता है कि वैल्यू-चेन पार्टनर्स ने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पॉलिसी ली हो। साथ ही, सेफ्टी हेलमेट, बांडी हार्नेस, सेफ्टी शूज और दूसरे सेफ्टी नियमों वगैरह का इंतज़ाम भी पक्का किया जाता है। सही वॉशरूम, पीने का पानी वगैरह देकर साइट पर साफ़-सफ़ाई बनाए रखी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट के कागज़ात में सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करने का प्रावधान भी होता है।

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के लिए सम्मान और प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (ए)	38,884 GJ	
कुल ईंधन खपत (बी)		
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी) सौर		18307 GJ
नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (ए+बी+सी)	38,884 GJ	18307 GJ
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली की खपत (डी)	398032 GJ	422858 GJ
कुल ईंधन की खपत (ई)	501242GJ	390283 GJ
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ)		
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)	899274 GJ	813141 GJ
खपत की गई कुल ऊर्जा (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	938158 GJ	831448 GJ

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
टर्नओवर की प्रति रुपया ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व)	1.75	1.70
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर की प्रति रुपया ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत/प्रचालनों से राजस्व)	3.5551 KJ/USD PPP	3.5139 KJ/USD PPP
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता		
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	11.09GJ /per employee	9.07 GJ /per employee

*पीपीपी रूपांतरण दर 20.34 के रूप में ली गई है

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ।
हाँ, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मैं रमा के गुप्ता एंड कंपनी द्वारा उचित आश्वासन (reasonable assurance) का कार्य किया गया है।

- क्या निगम के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

नहीं, हमारे पास ऐसी कोई साइट या सुविधाएं नहीं हैं

- जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

निगम का पानी का उपयोग केवल मानव उपभोग के लिए प्रतिबंधित है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। उदाहरण के लिए, हमारे प्रबंधन विकास केंद्र (एमडीसी), बोरीवली में, एक वर्षा जल संचयन इकाई वर्षा जल संग्रहण स्थापित है। यह इकाई पास के बोर से जुड़ी है अच्छी तरह से देय जिससे बोरवेल का पुनर्भरण किया जाता है और बोरवेल के पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।

प्राचल	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	4405.61	19571
(ii) भूजल	45154.66	680535
(iii) थर्ड पार्टी वाटर	55732.66	559024
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य	7961.81	8311
पानी की निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i+ii+iii+iv+v)	113254.74	1267441
पानी की कुल खपत (किलोलीटर में)	113254.74	1267441
कारोबार के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (कुल पानी की खपत/संचालन से राजस्व) (किलो लीटर/आईएनआर करोड़)	0.211	2.59
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर का प्रति रुपया जल तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल जल खपत/संचालन से राजस्व)	0.00043 L/USD PPP	0.0054 L/USD PPP
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में पानी की तीव्रता		
जल तीव्रता (वैकल्पिक) – इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है	1.34 केएल /प्रति कर्मचारी	13.83 केएल /प्रति कर्मचारी

*पीपीपी रूपांतरण दर 20.34 के रूप में ली गई है

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ।
हाँ, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मैं रमा के गुप्ता एंड कंपनी द्वारा उचित आश्वासन (reasonable assurance) का कार्य किया गया है।

4. डिस्चार्ज किए गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

प्राचल	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार पानी का निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल के लिए	लागू नहीं	लागू नहीं
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल के लिए		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल के लिए	लागू नहीं	लागू नहीं
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तृतीय पक्षों को भेजा गया		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़ा गया कुल पानी (किलोलीटर में)(i + ii + iii + iv + v)		

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?

नहीं

5. क्या निगम ने शून्य तरल निर्वहन के लिए एक तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

नहीं

6. कृपया इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें

➤ लागू नहीं

पैरामीटर	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
NOx		लागू नहीं	लागू नहीं
Sox			
पार्टिकुलेट मैटर (PM)			
लगातार कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC)			
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)			
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें			

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?

नहीं

7. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

प्राचल	इकाई	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
कुल दायरा 1 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी एस एफ 6, एन एफ 3, में विभाजन, (यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO ₂ समकक्ष	33,065.26	27,014
कुल क्षेत्र 2 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी में विभाजन, SF ₆ , NF ₃ , यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO ₂ समकक्ष	78,500.74	84,102
कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 टर्नओवर की प्रति रुपया उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व) (मीट्रिक टन / ₹ करोड़)		0.2079	0.23
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर का प्रति रुपया कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित)		0.0004227 KG/USD	0.0004696 KG/USD
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता			
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		1.32 mT/Employee	1.21 mT/Employee

पी पी पी कन्वर्जन रेट 20.34 लिया गया है।

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

हाँ, में. रमा के गुप्ता एंड कम्पनी. द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उचित आश्वासन (reasonable assurance) का काम किया गया है।

8. क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

कर्मचारियों को इवी (इलेक्ट्रिक वाहन) खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 'प्लांट-अ-लाइफ' पहल के तहत 11,47,574 पौधे लगाए गए। हमने डेस्कटॉप के लिए बिजली बचाने वाला समाधान, IPM+ लागू किया है। IPM+ की मदद से कॉर्पोरेशन ने साल भर में लगभग 3.86 GWh ऊर्जा की बचत की है, जिससे CO₂ उत्सर्जन में 956 मीट्रिक टन की कमी आई है और 53,975 क्यूबिक मीटर पानी की बचत हुई है। हमारा लक्ष्य ऐसी इमारतें बनाना है जो ग्रीन बिल्डिंग के नियमों का पालन करती हों और कम से कम 3-स्टार रेटिंग हासिल कर सकें। मार्च 2026 तक, हमने 10,499 kWp सोलर PV सिस्टम लगाए हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन में 40,097 टन की कमी आई है।

9. निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)	49.63	920
ई-कचरा (बी)	87	940

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (सी)		
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)		
बैटरी अपशिष्ट (इ)		
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)		
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (जी)		
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (एच)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (संरचना द्वारा ब्रेक-अप, क्षेत्र से संबंधित सामग्री द्वारा) - कागज, स्क्रैप धातु, आदि	1332	512
कुल (ए + बी + सी + डी + ई + एफ + जी + एच)	1468.63	2372
टर्नओवर का प्रति रुपया अपशिष्ट तीव्रता	0.0027362	0.005
(कुल अपशिष्ट उत्पन्न/संचालन से राजस्व) (मीट्रिक टन / ₹ करोड़)		
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर की प्रति रुपया अपशिष्ट तीव्रता	0.000005565 kg/USD PPP	0.0000100 kg/USD PPP
(पीपीपी के लिए समायोजित कुल अपशिष्ट उत्पत्ति/प्रचालनों से राजस्व)		
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता		
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	0.02 mT /प्रति कर्मचारी	0.03 mT /प्रति कर्मचारी
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से बरामद कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी	-	-
(i) पुनर्चक्रित	-	-
(ii) पुनः उपयोग किया गया	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति संचालन	-	-
कुल	-	-
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी	-	-
(i) भस्मीकरण	-	-
(ii) भूमि भरना	-	-
(iii) अन्य निपटान संचालन	-	-
कुल	-	-

नोट: 89.08% कचरे का निपटान मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के ज़रिए किया गया है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर (MDC) कैंपस में निकलने वाले खाने और बगीचे के कचरे को खाद में बदला जाता है और पौधों की बढ़त के लिए MDC के बगीचे में इस्तेमाल किया जाता है। पेपरलेस HRMS/TE मॉड्यूल जैसे कदमों से कागज का कचरा कम हुआ है। रोज़ाना का कचरा नगरपालिका को सौंप दिया जाता है। *PPP कन्वर्ज़न रेट 20.34 लिया गया है।

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?(हाँ /नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

हाँ, में. रमा के गुप्ता एंड कम्पनी. द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उचित आश्वासन (reasonable assurance) का काम किया गया है।

10 आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

हम अपशिष्ट प्रबंधन में स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जबकि हमारे संचालन में मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर विकास, प्रौद्योगिकी अवसंरचना और डिजिटल सेवाएं शामिल हैं, हम जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को पहचानते हैं।

हार्डवेयर आइटम जो जीवन के अंत में हैं, उन्हें बायबैक समझौते के तहत हार्डवेयर आपूर्ति विक्रेता को सौंप दिया जाता है। बदले में विक्रेता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत ई-अपशिष्ट निपटान विक्रेता की नियुक्ति करता है जो सभी स्थानों से हार्डवेयर का इकट्ठा करता है। ई-कचरा निपटान विक्रेता से निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र लिया जाता है।

हालांकि हमारा काम मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सेवाओं पर केंद्रित है, फिर भी हम सभी क्षेत्रों में कचरे के ज़िम्मेदार प्रबंधन के महत्व को समझते हैं। हमने कागज़ की ज़रूरत को कम करने के लिए कई प्रक्रियाओं को डिजिटल और ऑटोमेट करने के उपाय अपनाए हैं। दफ्तरों में कागज़ का इस्तेमाल कम से कम करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। फॉर्म, सर्टिफिकेट आदि की सॉफ्ट कॉपी जारी की जा रही हैं। बेहतर सेवा देने और समय की बर्बादी कम करने के लिए पेंशन से जुड़े दस्तावेज़ों को स्कैन किया गया है। सभी कर्मचारी कागज़ की स्टेशनरी का समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं।

हम सर्टिफाइड और ऑडिट किए गए डिस्पोज़ल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करते हैं जो पर्यावरण से जुड़े कड़े नियमों का पालन करते हैं। इससे यह पक्का होता है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक कचरे की सही तरीके से रीसाइक्लिंग, डेटा सैनिटाइज़ेशन और पर्यावरण के अनुकूल डिस्पोज़ल हो, जिससे पर्यावरण पर हमारा असर कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स रिकवरी हो सके। हम इन प्रक्रियाओं का लगातार मूल्यांकन और सुधार करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

89.08% कचरे का निपटान मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के ज़रिए किया गया है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर (MDC) कैंपस में निकलने वाले खाने और बगीचे के कचरे को खाद में बदला जाता है और पौधों की बढ़त के लिए MDC के बगीचे में इस्तेमाल किया जाता है। पेपरलेस HRMS/TE मॉड्यूल जैसे कदमों से कागज़ के कचरे में कमी आई है। रोज़ाना का कचरा नगर पालिकाओं/स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाता है। सर्विस सेक्टर में होने के कारण, हमारे उत्पादों या प्रक्रियाओं से कोई खतरनाक या ज़हरीले केमिकल नहीं निकलते हैं। हम कचरा प्रबंधन के लिए एक SOP तैयार कर रहे हैं।

हमारे अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में शामिल हैं:

ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढांचा: हम संसाधन खपत को कम करने के लिए ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढांचे के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन: हमने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उचित पुनर्चक्रण और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित निपटान भागीदारों के साथ सहयोग करते हुए एक व्यापक ई-कचरा प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया है।

पेपरलेस पहल: हम पेपरलेस प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं और अपने दिन-प्रतिदिन के संचालन में भौतिक सामग्रियों पर निर्भरता को कम करने के लिए नई पहल करते हैं।

- 11 यदि निगम के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव-विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में / उनके आसपास संचालन / कार्यालय हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन / मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

हमारा कोई भी कार्यालय पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में स्थित नहीं है।

- 12 चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा किए गए परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:
लागू नहीं

- 13 क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें:

क्रम स.	उन कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा किया गया कोई भी जुर्माना/दंड/कार्रवाई बोर्ड या अदालतों द्वारा	सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर निगम लागू पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन करता है।				

जिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस की ज़रूरत होती है, उनमें नियमों के पालन के लिए संबंधित कानूनी एनवायरनमेंटल संस्था से ज़रूरी मंजूरी ली जाती है।

नेतृत्व संकेतक

- जल-संकट वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी, खपत और निर्वहन (किलो-लीटर में):
जल-संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा / संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
 - क्षेत्र का नाम - लागू नहीं

- ii. संचालन की प्रकृति - लागू नहीं
- iii. निम्नलिखित प्रारूप में पानी की निकासी, खपत और निर्वहन:- लागू नहीं

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

लागू नहीं

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
कुल दायरा 3 उत्सर्जन (जीएचजी का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में ब्रेकअप, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO ₂ समकक्ष	2983 TCo _{2e} (कर्मचारियों का आना-जाना - श्रेणी 7) 2105.86 TCo _{2e} (व्यावसायिक दौरा - श्रेणी 6)	लागू नहीं
कुल दायरा 3 टर्नओवर की प्रति रुपया उत्सर्जन तीव्रता		लागू नहीं	लागू नहीं
कुल दायरा 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		लागू नहीं	लागू नहीं

स्कोप 3 उत्सर्जन के लिए, इस चरण में केवल कर्मचारियों के आने-जाने और व्यावसायिक दौरों को ही शामिल किया गया है।

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

लागू नहीं

3. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में रिपोर्ट किए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव-विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं क्योंकि हमारा कोई भी कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित नहीं है

4. यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधानों का उपयोग किया है, या उत्सर्जन/प्रवाह निर्वहन/उत्पन्न अपशिष्ट के कारण प्रभाव को कम किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उसी का विवरण और ऐसी पहलों के परिणाम प्रदान करें:

संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए खास पहल या नई टेक्नोलॉजी और समाधानों में शामिल हैं: पानी बचाने वाले फिक्सचर, LED लाइट, ऑक्जिपेंसी सेंसर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, एनर्जी बचाने वाले उपकरण जैसे VRF टाइप AC मशीन और 5-स्टार AC मशीन, एनर्जी लेवल II ट्रांसफॉर्मर वगैरह। साथ ही, AC मशीनों में पर्यावरण के अनुकूल रेफ्रिजेंट गैस का इस्तेमाल और बिजली बनाने के लिए रूफटॉप सोलर का इस्तेमाल भी शामिल है। हमने पहले से बनी 26 इमारतों के लिए ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है और वित्त वर्ष 2025-26 में 32 और इमारतों के लिए ऐसा ही सर्टिफिकेशन पाने की योजना बना रहे हैं।

5. क्या इकाई के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है?

हाँ, कॉर्पोरेशन के पास बोर्ड से मंजूर 'बिज़नेस कंटीन्यूटी मैनेजमेंट' (BCM) प्लान है। इसे सिस्टम फेल्युअर, प्राकृतिक आपदाओं या साइबर हमलों जैसी रुकावटों के दौरान भी ज़रूरी कामकाज को जारी रखने के लिए बनाया गया है। इस प्लान का मकसद कामकाज रुकने के समय (डाउनटाइम) को कम करना, ज़रूरी कामों को सुरक्षित रखना, आर्थिक नुकसान घटाना और तेज़ी से रिकवरी करना है। BCM प्लान में ज़रूरी बिज़नेस कामों को जारी रखने या तेज़ी से बहाल करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ बताई गई हैं। कॉर्पोरेशन अपने 'बिज़नेस कंटीन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम' के लिए ISO 22301 प्रमाणित है, जो ऑपरेशनल तैयारी के प्रति उसकी मज़बूत प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसके अलावा, बोर्ड से मंजूर एक अलग 'IT डिज़ास्टर रिकवरी' (ITDR) पॉलिसी है, जो बिज़नेस की ज़रूरतों के हिसाब से IT सिस्टम, एप्लीकेशन और डेटा की सुरक्षा, बैकअप और रिकवरी के लिए गाइडलाइंस तय करती है। ज़रूरी प्रक्रियाओं के लिए नियमित रूप से बिज़नेस कंटीन्यूटी और डिज़ास्टर रिकवरी ड्रिल की जाती हैं, जिससे बिज़नेस में रुकावट के जोखिमों के खिलाफ कॉर्पोरेशन की क्षमता और मज़बूत होती है।

6. इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करना। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि व्यवसाय की प्रकृति जीवन बीमा है।

ऐसी कोई स्टडी नहीं की गई है। हालाँकि, कॉर्पोरेशन के लिए किए जाने वाले इंजीनियरिंग कामों में, हम पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए ज़रूरी उपाय कर रहे हैं, जैसे: कंक्रीट के काम के लिए RMC (रेडी मिक्स कंक्रीट) का इस्तेमाल, फ्लाइ ऐश ईटों का इस्तेमाल, साइट पर धूल कम करना, बारिश के पानी को इकट्ठा करना (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का इस्तेमाल और ऐसे बिल्डिंग मटीरियल का इस्तेमाल जिनसे कम कार्बन फुटप्रिंट निकलता हो, वगैरह। हाउसकीपिंग वेंडर अपने काम के लिए किसी भी हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं।

7. वैल्यू चेन पार्टनर्स (ऐसे पार्टनर्स के साथ किए गए बिज़नेस की वैल्यू के आधार पर) का प्रतिशत, जिनका पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के लिए आकलन किया गया।

हमने इस साल किसी भी वैल्यू चेन पार्टनर का आकलन नहीं किया है।

8. कितने ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न या खरीदे गए हैं:

अ. सूचीबद्ध इकाई द्वारा

ब. शीर्ष दस (क्रमशः खरीद और बिक्री के मूल्य के संदर्भ में) मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा।

शून्य

सिद्धांत 7: सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होने पर व्यवसायों को ऐसा करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो

आवश्यक संकेतक

1. अ. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

निगम का 15 से अधिक व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों से संबंध है

- ब. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) संस्था का सदस्य / संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (राज्य/राष्ट्रीय) की पहुंच
1	भारतीय प्रशिक्षण और विकास सोसायटी (आईएसटीडी)	राष्ट्रीय
2	राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क (एनएचआरडी)	राष्ट्रीय
3	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM)	राष्ट्रीय
4	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद (एएससीआई)	राष्ट्रीय
5	अखिल भारतीय प्रबंधन परिसंघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
6	भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई)	राष्ट्रीय
7	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
8	बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीआई)	राष्ट्रीय
9	मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट सोसाइटी, गुडगांव	राष्ट्रीय
10	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना।

किसी भी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है।

नेतृत्व संकेतक

1. निगम द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:

एलआईसी ने खुद को पसंद के बीमाकर्ता के रूप में स्थापित किया है और उदारीकरण के दो दशक से ज्यादा के बाद भी अपनी नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखना जारी रखा है, जिसमें प्रमुख व्यवसाय मिश्रण मुख्य रूप से एजेंसी बल के माध्यम से भाग लेने वाले व्यवसाय से आता है। इसके अलावा, एलआईसी ने जीवन बीमा के बारे में बढ़ी हुई जागरूकता का लाभ उठाया है और ग्राहकों के भौतिक से डिजिटल यानी 'फिजिटल' मोड में प्रवास के साथ डिजिटल जुड़ाव और सेवाओं की डिजिटलीकृत डिलीवरी का पीछा कर रहा है।

हम पॉलिसी धारक और बड़े पैमाने पर बीमा उद्योग के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा परिषद के माध्यम से नियामक को विभिन्न एक्सपोजर ड्राफ्ट, नियमों में प्रस्तावित संशोधन आदि पर इनपुट/विचार/सुझाव प्रदान करते हैं।

हम हर साल पूरे भारत में बीमा जागरूकता अभियान (आईएसी) आयोजित करते हैं। आईएसी के तहत हमने पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित किए हैं जो हमारी उपलब्धियों, हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो और पॉलिसीधारकों को दी गई विभिन्न सेवाओं पर प्रकाश डालते हैं। हम टीवी विज्ञापनों के साथ-साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रिंट विज्ञापनों के माध्यम से अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, लोगों से एनिमेटेड वीडियो के साथ-साथ अपने पहले वेतन के साथ बीमा खरीदने का आग्रह करते हैं, पूरे भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार / संगीत और सामान्य मनोरंजन चैनलों पर बीमा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। क्रिएटिव विभिन्न आईएसी के लिए तैयार किए जाते हैं जैसे, अपने केवाईसी को अपडेट करना और एनईएफटी विवरण जमा करना, नीतियों का पुनरुद्धार, नई योजनाएं / उत्पाद। बीमा के बारे में प्रासंगिक संदेश पोस्ट करके सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाती है।

हम नई पहलों की जांच-परख के लिए लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों का भी हिस्सा हैं।

सिद्धांत 8: व्यवसायों के समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन का विवरण (एसआईए)।

फ़ाउंडेशन यह पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि हर पहल से फ़ायदा पाने वालों की ज़िंदगी पर सार्थक और लंबे समय तक रहने वाला असर पड़े। हालाँकि असर का अध्ययन करने के लिए किसी बाहरी एजेंसी को शामिल नहीं किया गया है, तथापि फ़ाउंडेशन हर साल अपने कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और पहुँच का आकलन करने के लिए एक व्यापक आंतरिक मूल्यांकन करता है। ज़ोनल इन्स्पेक्शन टीमों नियमित रूप से GJF-समर्थित प्रोजेक्ट्स की निगरानी और समीक्षा करती हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि फंड का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से और सिर्फ उसी मकसद के लिए किया जाए जिसके लिए वे दिए गए थे। ये निरीक्षण यह समझने में भी मदद करते हैं कि प्रोजेक्ट्स समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों की कितनी अच्छी तरह मदद कर रहे हैं।

ये डिवीज़न सीधे लाभार्थियों के संपर्क में रहते हैं, जिससे लगातार फ़ीडबैक मिलता है और ज़मीनी स्तर पर नतीजों की बेहतर समझ बनती है। मरीज़ों के इलाज में मदद करने वाली पहलों के लिए, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के मकसद से संबंधित अस्पतालों से इलाज और खर्च की विस्तृत समरी रिपोर्ट ली जाती है।

इसके अलावा, GJF स्कॉलर्स और फ़ायदा उठाने वालों के अनुभव और विचार, फ़ाउंडेशन की कोशिशों से आए सकारात्मक बदलाव की प्रेरणादायक मिसाल हैं। लगातार मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के ज़रिए, फ़ाउंडेशन भरोसा बनाए रखने, सामाजिक असर को ज़्यादा से ज़्यादा करने और समुदायों में सार्थक बदलाव लाने की कोशिश करता है। GJF स्कॉलर्स से मिले अनुभव और विचार, फ़ाउंडेशन की पहलों से आए बदलावकारी असर की ज़बरदस्त मिसाल हैं। उनकी सफलता की कहानियाँ, अनुभव और आभार के शब्द फ़ाउंडेशन को काबिल लोगों को सशक्त बनाने और बेहतर भविष्य के लिए मौके बनाने का काम जारी रखने के लिए प्रेरित करते हैं।

2. आपकी इकाई द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) के लिए निम्नलिखित प्रारूप में परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें:

शून्य

3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें।

फ़ाउंडेशन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने और स्कॉलर्स को चुनने के लिए एक पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी सिस्टम बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। डिवीज़नल, ज़ोनल और सेंट्रल ऑफिस को शामिल करने वाला एक मज़बूत तीन-स्तरीय सिस्टम यह पक्का करता है कि हर प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन हो और फ़ाउंडेशन की पहलों का फ़ायदा देश भर के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों तक समान रूप से पहुँचे।

फ़ाउंडेशन द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी देने और विद्वानों के चयन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है। फ़ाउंडेशन (अखिल भारत) की धर्मार्थ गतिविधियों के सभी विवरण हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध हैं। कोई शिकायत नहीं है।

फ़ाउंडेशन लाभार्थियों और स्टेकहोल्डर्स के साथ मज़बूत बातचीत बनाए रखने में भी विश्वास रखता है। मिली किसी भी शिकायत या चिंता का समाधान डिविज़नल, ज़ोनल और सेंट्रल ऑफिस विभागों के आपसी सहयोग से तुरंत और संवेदनशीलता के साथ किया जाता है। इस तरह की तत्परता से भरोसा बढ़ता है, समुदाय के साथ रिश्ते मज़बूत होते हैं और यह सुनिश्चित होता है कि फ़ाउंडेशन की सेवाएँ समाज पर सकारात्मक और सार्थक प्रभाव डालती रहें।

फ़ाउंडेशन पारदर्शिता, जवाबदेही और समुदाय के कल्याण के प्रति अपनी मज़बूत प्रतिबद्धता से प्रेरित है। किसी भी शिकायत पर तुरंत ध्यान दिया जाता है और डिविज़नल, ज़ोनल और सेंट्रल ऑफिस विभागों के आपसी सहयोग से उसका समाधान किया जाता है। इस व्यवस्थित तरीके से यह सुनिश्चित होता है कि हर समस्या को सावधानी, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ सुलझाया जाए। बातचीत के खुले रास्ते और लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर, फ़ाउंडेशन उन समुदायों के साथ भरोसा मज़बूत करता है और सार्थक रिश्ते बनाता है जिनकी वह सेवा करता है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य द्वारा कुल इनपुट में इनपुट):

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी बीमा व्यवसाय में है।

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन – निम्नलिखित स्थानों में नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को कुल मजदूरी लागत के % के रूप में भुगतान किए गए वेतन का खुलासा करें

स्थल	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
ग्रामीण	0.59%	0.69%
अर्ध शहरी	27.43%	31.21%
शहरी	33.66%	36.71%
महानगर	38.32%	31.38%

इसके अलावा, एक बड़े एजेंसी नेटवर्क को तैयार और विकसित करके हमने ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। एजेंसी से जुड़े ये अवसर स्वरोज़गार देते हैं, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देते हैं और स्थानीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करते हैं।

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

सामाजिक प्रभाव आकलन में कोई नकारात्मक सामाजिक प्रभाव की पहचान नहीं की गई थी।

2. सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए नामित आकांक्षी जिलों में अपनी इकाई द्वारा किए गए सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

फ़ाउंडेशन देश भर में समावेशी और टिकाऊ सामुदायिक विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और भारत सरकार द्वारा पहचाने गए 'एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स' (आकांक्षी जिलों) पर विशेष ध्यान देता है। विकास के अंतर को कम करने और वंचित समुदायों को आगे बढ़ाने के अपने संकल्प को दिखाते हुए, फ़ाउंडेशन ने 31 आकांक्षी जिलों में कुल 13.88 करोड़ रुपये के निवेश से 55 असरदार प्रोजेक्ट्स लागू किए हैं। इन पहलों ने ज़रूरी बुनियादी ढांचे को मज़बूत करके और विकास व सशक्तिकरण के अवसर पैदा करके हज़ारों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। इन प्रोजेक्ट्स में स्कूल की इमारतें, कौशल विकास केंद्र, मल्टीपर्स हॉल, आदिवासी लड़कियों के लिए कमरे और टॉयलेट ब्लॉक, पैथोलॉजी यूनिट, डे-केयर सेंटर और महिला सशक्तिकरण की पहल शामिल हैं।

इसके अलावा, फ़ाउंडेशन ने ज़रूरी हेल्थकेयर और कम्युनिटी वेलफ़ेयर सेवाओं में मदद की है। इसमें एम्बुलेंस, मरीज़ों को लाने-ले जाने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन, स्कूली बच्चों के लिए गाड़ियाँ और खाना बाँटने वाली गाड़ियाँ शामिल हैं, ताकि ज़रूरतमंदों तक मदद पहुँच सके। इन सार्थक प्रयासों के ज़रिए, फ़ाउंडेशन शिक्षा, हेल्थकेयर, महिला सशक्तिकरण और कम्युनिटी वेलफ़ेयर को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही, देश के उन इलाकों में जहाँ सुविधाओं की कमी है, वहाँ सर्वांगीण और समान विकास के विज़न में योगदान दे रहा है।

3. (क) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप सीमांत/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/ नहीं)

नहीं, हमारे पास अधिमान्य खरीद नीति नहीं है। हालांकि, हम हाशिए या कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री और सेवाओं की खरीद के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।

(ख) आप किन सीमांत/कमजोर समूहों से खरीद करते हैं?

माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज़ (MSE) के तहत रजिस्टर्ड ग्रुप्स (जो सर्टिफिकेट दिखाते हैं) और MSE के तहत रजिस्टर्ड SC/ST वेंडर्स को प्राथमिकता दी जाती है। साल 2025-26 में, MSE के तहत SC/ST से की गई खरीद का प्रतिशत 2.73% था। हमारी खरीद प्रक्रिया में सभी वेंडर्स को समान अवसर देने को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, हम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ (MSMEs) और लोकल सप्लायर्स से प्राथमिकता के आधार पर खरीद करने के सरकारी नियमों का पालन करते हैं, जिससे लोकल इकॉनमी और बिज़नेस को बढ़ावा मिलता है।

(ग) यह कुल खरीद (मूल्य के आधार पर) का कितना प्रतिशत है?

	वर्तमान वित्त वर्ष 25-26			पिछला वित्त वर्ष 24-25		
	एमएसई/एससी/एसटी विक्रेताओं से खरीद (राशि करोड़ में)	कार्यालय द्वारा की गई कुल खरीद (राशि करोड़ में)	%	एमएसई/एससी/एसटी विक्रेताओं से खरीद (राशि करोड़ में)	कार्यालय द्वारा की गई कुल खरीद (राशि करोड़ में)	%
एमएसई विक्रेताओं से खरीद	224.14	425.60	52.66	1,253.94	3,029.63	41.38
एमएसई के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विक्रेता	11.63	425.60	2.73	230.28	3,029.63	7.60

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई (चालू वित्तीय वर्ष में) द्वारा स्वामित्व या अधिग्रहित बौद्धिक संपत्तियों से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:

लागू नहीं है क्योंकि हम आविष्कारों, या वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले किसी भी कलात्मक कार्यों के व्यवसाय में नहीं हैं, जिसके लिए बौद्धिक संपदा (आईपी) मालिकों को आईपी कानूनों के तहत कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। हालांकि, हमारे इन-हाउस विकसित अनुप्रयोग हमारे संचालन की आंतरिक वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान करते हैं और हम व्यापक उद्योग और समुदाय के साथ ज्ञान साझा करने और सहयोग में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।

लागू नहीं

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

एलआईसी जीजेएफ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए परियोजनाओं का समर्थन करता है जो देश भर में इसके उद्देश्यों - गरीबी या संकट से राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत या सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु से जुड़ी हैं। एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लाभार्थी हैं:

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: फाउंडेशन शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे में योगदान देता है जैसे कि निम्न आय वर्ग के लोगों के बीच डिजिटल कौशल विकसित करने के लिए कौशल केंद्र का निर्माण, छात्रावास, स्कूल भवन, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, स्कूल बस, विकलांग बच्चों को परिवहन सुविधा प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए व्यावसायिक चिकित्सा उपकरण और ऑडियो-विजुअल उपकरण, चिकित्सा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए, एलआईसी जीजेएफ द्वारा गोद लिए गए गांव गोविंदपुर में 100% साक्षरता के लिए साक्षरता अभियान। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 41,776 योग्य छात्रों को स्कॉलरशिप देने पर 105.35 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के योग्य छात्रों को हर साल स्कॉलरशिप दी जाती है।

अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती:

फाउंडेशन ने कई प्रोजेक्ट्स के लिए फंड दिया है, जैसे कि मेडिकल उपकरण, ICU एम्बुलेंस और मेडिकल वैन उपलब्ध कराना, अस्पताल

बनवाना, और कैंसर मरीजों का इलाज, जन्मजात हृदय की सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी और कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी में मदद करना। दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों द्वारा लगाए गए मेडिकल कैंप के ज़रिए भी गरीब मरीजों की पहचान की जाती है और उन्हें ज़रूरी इलाज दिया जाता है। फ़ाउंडेशन ने बड़े अस्पतालों, खासकर कैंसर अस्पतालों को मेडिकल उपकरण, एम्बुलेंस और इलाज में मदद दी है। इनमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (मुंबई), अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट (चेन्नई), किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी (बैंगलोर), रीजनल कैंसर सेंटर (तिरुवनंतपुरम), चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (कोलकाता), श्री विठ्ठलराव जोशी चैरिटीज़ ट्रस्ट - बी के एल वालावलकर हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर (चिपळूण), हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (गोरखपुर) और डॉ. शीला शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट मथुरा, बागची श्री शंकरा कैंसर फ़ाउंडेशन, भुवनेश्वर, श्री जगन्नाथ चैरिटेबल कैंसर इंस्टीट्यूट, गाज़ियाबाद, श्री शंकरा कैंसर फ़ाउंडेशन, बैंगलोर, श्रीमती नंदमुरी बसवातारका रामाराव मेमोरियल कैंसर फ़ाउंडेशन, खैरताबाद, इंदौर कैंसर फ़ाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, पिगदंबर, मालाबार कैंसर सेंटर सोसाइटी, थलासेरी, मोहननंद कैंसर डायग्नोस्टिक एंड वेलफ़ेयर सोसाइटी, आसनसोल, कैंसर रिलीफ़ सोसाइटी - राष्ट्रसंत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नागपुर, गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद।

वोकेशनल ट्रेनिंग और रोज़गार के साधन बनाना: फ़ाउंडेशन ने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाने और उन्हें ज़रूरी उपकरण उपलब्ध कराने के लिए फ़ंड दिया है, ताकि लोग रोज़गार के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग ले सकें। महिला हथकरघा बुनकरों की स्किल बढ़ाने और उन्हें रोज़गार के लिए सशक्त बनाने के मकसद से उनकी ट्रेनिंग के लिए भी फ़ंड दिया गया है। इन पहलों से लोगों को लंबे समय तक आमदनी देने वाले रोज़गार के मौके मिले हैं और वे ज़्यादा आत्मनिर्भर बने हैं।

आदिवासी प्रोजेक्ट्स: आदिवासी कल्याण के प्रति अपनी मज़बूत प्रतिबद्धता के साथ, फ़ाउंडेशन ने आदिवासी समुदाय को फ़ायदा पहुँचाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड दिया है। इसमें स्कूल की इमारतें, हॉस्टल, स्किल-बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग, टॉयलेट ब्लॉक, एम्बुलेंस और छात्रों के लिए स्कूल बस बनाने में मदद शामिल है। फ़ाउंडेशन ने 39 आदिवासी प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 9.05 करोड़ रुपये का फ़ंड दिया है।

आपदा राहत: संकट के समय में, फ़ाउंडेशन देश के साथ मज़बूती से खड़ा रहा है। जैसे COVID-19 राहत उपायों के तहत PM केयर्स फ़ंड, महाराष्ट्र सरकार के कोविड राहत फ़ंड, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल राहत फ़ंड आदि में योगदान दिया है।

प्राकृतिक आपदा में राहत: फ़ाउंडेशन ने चेन्नई और केरल में बाढ़, चक्रवात फ़ानी के दौरान और ओडिशा के चक्रवात-संभावित आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मयूरभंज ज़िले के उदाला में मल्टीपर्स चक्रवात शेल्टर बनाने में मदद की है। इसके अलावा, धरलाई राहत पीड़ितों, पंजाब में बाढ़ आदि के लिए भी फ़ंड दिया गया है।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष: केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा पूर्व सैनिकों, विधवाओं के कल्याण और पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए स्थापित भारतीय रक्षा बल के पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में योगदान दिया गया है।

जलवायु कार्रवाई: पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्रवाई के महत्व को पहचानते हुए, फ़ाउंडेशन ने स्कूल छात्रावास भवन, वृद्धाश्रम और विद्युत शवदाह गृह में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का समर्थन किया है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण और बिजली की लागत कम होगी।

स्वच्छ जल और स्वच्छता: स्वच्छ जल और स्वच्छता के तहत, फ़ाउंडेशन ने हरि तीर्थम, कन्याकुमारी में जल निकायों के नवीनीकरण और समुदायों के लिए ताजे पानी की उपलब्धता को सक्षम करने में योगदान देकर प्रभावशाली पहल की है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश और हरिद्वार के आगंतुकों को स्वच्छ पेयजल के लिए वाटर वेंडिंग मशीनें उपलब्ध कराने के लिए भी धन आवंटित किया गया।

कोल्हापुर की झुग्गी-बस्तियों में 'वन होम वन टॉयलेट स्कीम' के तहत शौचालय बनाने में योगदान दिया गया। देश भर के 113 स्कूलों में 169 शौचालय और कई स्कूलों में टॉयलेट ब्लॉक बनाने के लिए फ़ंड दिया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में LIC द्वारा गोद लिए गए गांव गोविंदपुर को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए दो सामुदायिक शौचालय बनाने में योगदान दिया गया। बद्री धाम में ई-टॉयलेट बनाने में योगदान दिया गया और गंगा नदी व उसके इकोसिस्टम को फिर से बेहतर बनाने के लिए 'क्लीन गंगा फ़ंड' में फ़ंड दिया गया। आश्रय केंद्र में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए फ़ंड दिया गया। इन कोशिशों ने उन इलाकों में, जहाँ सुविधाएँ कम हैं, साफ़-सफ़ाई, स्वच्छता और साफ़ पानी की उपलब्धता में काफ़ी योगदान दिया है।

आदिवासी कला का संरक्षण और सुरक्षा: फ़ाउंडेशन ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण और सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाई है। इसने ओडिशा के रायगडा ज़िले के तीन लंजिया सौरा गांवों में आदिवासी कला दीर्घाओं (गैलरी) के निर्माण में मदद की है। ये दीर्घाएँ सौरा पेंटिंग और आदिवासी समुदायों की समृद्ध कलात्मक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं।

भूमि पर जीवन: ज़मीन पर जीवन और पशु कल्याण के समर्थन में, फ़ाउंडेशन ने जंगली जानवरों के बचाव और उन्हें लाने-ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए फ़ंड दिया है। साथ ही, गुड़गांव के गोपालपुर खेड़ा गांव में जानवरों के बचाव और पुनर्वास के लिए एक पशु अभयारण्य में सोलर प्लांट लगवाया है और पेड़ लगाने के अभियान भी शुरू किए हैं।

इन विविध और असरदार पहलों के ज़रिए, LIC गोल्डन जुबली फ़ाउंडेशन लोगों के जीवन को बेहतर बनाता रहा है, समावेशी विकास को बढ़ावा देता रहा है और राष्ट्र-निर्माण तथा समुदाय के टिकाऊ विकास में सार्थक योगदान देता रहा है।

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए वाले समूहों के लाभार्थियों का %
1	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सामुदायिक विकास गतिविधियों के तहत 119 परियोजनाएं पूरी की गईं, जिनसे 59,383 लोगों को लाभ मिला; साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 10,660 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की गई।	59383	100%

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और मूल्य प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र का वर्णन करें

ग्राहक संबंध और ग्राहक सेवा की भावना हमारी शिकायत निवारण प्रणाली में शामिल है, जिसमें सभी स्पर्श बिंदुओं पर ग्राहक उन्मुख कर्मियों को रखने पर जोर दिया गया है। मानवीय हस्तक्षेपों को कम करने और शिकायतों को कम करने के लिए आईटी समर्थित सहायता प्रणाली प्रचालित की गई है। निगम के पास एक ग्राहक अनुकूल ऑनलाइन प्रणाली है जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम के ग्राहक पोर्टल पर पंजीकृत पॉलिसीधारक शिकायत दर्ज कर सकता है और हमारी वेबसाइट <https://licindia.in/> पर उपलब्ध 'एलआईसी की ई-सेवाओं' के माध्यम से अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकता है IRDAI की शिकायत प्रबंधन प्रणाली-बीमा भरोसा के तहत पंजीकृत शिकायतें LIC की शिकायत प्रबंधन प्रणाली के साथ समन्वयित हैं। ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए निगम के शाखा/मंडलीय/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारी हैं। उनके नाम हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। संबंधित जीआरओ अपने कार्यालयों में ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए सभी सोमवार को दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच उपलब्ध हैं। ग्राहक पूर्व अपॉइंटमेंट लेकर अन्य दिनों में जी.आर.ओ. से मिल सकते हैं। ग्राहक अपनी शिकायतें डाक, ई-मेल आदि के माध्यम से संबंधित सर्विसिंग कार्यालयों/जीआरओ को भी भेज सकते हैं।

पूरे भारत में सुबह 8.00 बजे से रात 8.00 बजे तक कुल 74 ग्राहक क्षेत्र संचालित होते हैं जो 'गुणवत्ता अनुभव' पर विशेष जोर देने के साथ ग्राहक की सभी सर्विसिंग आवश्यकताओं के समाधान के लिए 'वन-स्टॉप सेंटर' के रूप में काम करते हैं।

एलआईसी के पास एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर सेवा 24 * 7 उपलब्ध है। नंबर 022-68276827 है जिसमें एक व्यापक आईवीआरएस मेनु के साथ-साथ विशिष्ट प्रश्नों और सूचनाओं के लिए कॉल सेंटर के कार्यकारी के साथ बात करने और शिकायत के लिए सीसीएस (कॉल सेंटर सर्विसेज) टिकट बढ़ाने का विकल्प है। ये सेवाएं हिंदी, अंग्रेजी और आठ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।

हमारे पास LICHELP नामक एक एसएमएस पहल है, जहां पॉलिसीधारकों को 9222492224 पर एक एसएमएस LICHELP<POLICYNO> भेजने की आवश्यकता है। एसएमएस प्राप्त होने पर, पॉलिसी की सर्विसिंग शाखा से जुड़े ग्राहक क्षेत्र का एक अधिकारी, ग्राहक की शिकायत या अनुरोध के समाधान के लिए उनसे संपर्क करता है। हम पॉलिसी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में ग्राहकों को एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से अपडेट करते हैं।

जिन पॉलिसी होल्डर्स का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उनके लिए हमारे पास 8976862090 पर WhatsApp सर्विस उपलब्ध है, ताकि वे पॉलिसी से जुड़ी ज़रूरी जानकारी पा सकें।

अस्वीकृत मृत्यु दावों से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से, क्षेत्रीय और केंद्रीय कार्यालय स्तरों पर 'दावा विवाद निवारण समितियां' स्थापित की जाती हैं। समिति में एलआईसी के दो या अधिक वरिष्ठ अधिकारी और जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय के एक माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं।

एलआईसी के पास भारत सरकार के दो ऑनलाइन प्लेटफार्मों के तहत भूमिका-आधारित पहुंच है, 1) सीपीजीआरएएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) और 2) एनसीएच (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन) - इनग्राम मॉड्यूल (एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र) पॉलिसीधारकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए उपलब्ध है, जिनका सीधे जवाब दिया जाता है।

LIC ने IRDAI के (बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस) रेगुलेशन, 2024 के रेगुलेशन 5(5) और उसके तहत जारी मास्टर सर्कुलर (संशोधित) के अनुसार, पॉलिसीधारकों की सुरक्षा, शिकायत निवारण और क्लेम मॉनिटरिंग कमिटी (PPGR&CM) का गठन किया है।

2. उत्पादों और/सेवाओं का कारोबार, सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में, जिनके बारे में जानकारी होती है: लागू नहीं

3. लिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2025-2026		टिप्पणियां	वित्त वर्ष 24-25		टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डेटा गोपनीयता	1	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
विज्ञापन	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
साइबर सुरक्षा	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	49011	0	लागू नहीं	54636	0	लागू नहीं
प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अनुचित व्यापार व्यवहार*	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अन्य	17412	0	लागू नहीं	19654	0	लागू नहीं

नोट: FY 2025-26 के लिए कुल शिकायतों में तीनों पोर्टल्स - ICMS, CPGRAMS और NCH - पर प्राप्त शिकायतें शामिल हैं।

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों का विवरण:

शून्य

5. क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, निगम के पास डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा पर नीतियां और प्रक्रियाएं हैं। नीतियों का पूरा सेट सभी कर्मचारियों के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापस बुलाने के उदाहरणों की पुनः घटना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा जुर्माना / की गई कार्रवाई।

निगम ग्राहकों की साइबर सुरक्षा एवम डेटा गोपनीयता से सम्बंधित किसी भी समस्या या शिकायत के समाधान हेतु सक्रिय रूप से आवश्यक कदम उठाता है।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

अ) डेटा उल्लंघनों के उदाहरणों की संख्या

29.07.2025 को साइबर सुरक्षा में सेंध लगने की एक घटना की सूचना मिली थी।

आ) ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत लागू नहीं

इ) प्रभाव, यदि, कोई हो, डेटा उल्लंघनों का कोई प्रभाव नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. ऐसे चैनल/प्लेटफॉर्म जहाँ इकाई के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी सार्वजनिक डोमेन यानी हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर

उपलब्ध है। इसके अलावा, निगम अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करने, शिक्षित करने और हमारे ग्राहकों के साथ जुड़े रहने के लिए प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों का सक्रिय रूप से उपयोग करता है।

- ❖ मोबाइल ऐप: 'My LIC APP', 'LIC Digital APP'
- ❖ फेस बुक, LICIndiaForever
- ❖ यूट्यूब, LICIndiaForever
- ❖ इंस्टाग्राम, LICIndiaForever
- ❖ लिंकडीन, LICIndiaForever
- ❖ एक्स (ट्विटर) हैंडल: LICIndiaForever
- ❖ व्हाट्सएप: 8976862090
- ❖ कॉल सेंटर: 022- 6827 6827

LIC ने कई तरह की सेवाओं के लिए 'My LIC APP' लॉन्च किया है, जैसे कि KYC वेरिफिकेशन, ऑनलाइन पॉलिसी लोन, पॉलिसी रिन्यूअल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करना, ईमेल ID अपडेट करना, पता अपडेट करना, NEFT डिटेल्स अपडेट करना, प्रीमियम पेमेंट, बैंक डिटेल्स अपडेट करना, DGH के साथ ऑनलाइन रिवाइवल वगैरह।

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

बीमा एक इनटॉन्जिबल उत्पाद है इसलिए सामान्य उपयोग और सुरक्षा मानदंड इस पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि, जोखिम कवर की निरंतरता के लिए, प्रीमियम का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। जहां मोबाइल नंबर पॉलिसी रिकॉर्ड में पंजीकृत है, उन पॉलिसीधारकों को एसएमएस भेजे जाते हैं जो उन्हें भुगतान के लिए देय प्रीमियम के बारे में सूचित करते हैं। जहां पॉलिसी रिकॉर्ड में कोई मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है, हम पॉलिसीधारकों को डाक द्वारा प्रीमियम देय सूचना भेज रहे हैं, ताकि पॉलिसियों को लागू रखा जा सके और ग्राहक पॉलिसी के तहत बीमा लाभों का आनंद ले सकें। ग्राहकों को धोखेबाजों से सावधान रहने के लिए एसएमएस भेजे जाते हैं। किसी भी ऑनलाइन लेनदेन के लिए हमारे लिंक पर आने वाले ग्राहकों के लिए सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।

WhatsApp पर LIC की सर्विस शुरू की गई है, जहाँ पॉलिसीहोल्डर अपने बकाया प्रीमियम की जानकारी ले सकते हैं, लोन और लोन चुकाने का कोटेशन, प्रीमियम पेमेंट का सर्टिफिकेट, ULIP यूनिट स्टेटमेंट वगैरह पा सकते हैं। एक्टिव कस्टमर्स को समय-समय पर जानकारी भेजी जाती है ताकि उन्हें फ़र्जी कॉल्स और KYC जमा करने के नाम पर आने वाली झूठी कॉल्स के बारे में जागरूक किया जा सके। साथ ही, कस्टमर्स के साथ होने वाली बातचीत में फ़र्जी कॉल्स से जुड़ी चेतावनी (डिस्क्लेमर) भी शामिल होती है। हम इन-हाउस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देते हैं जो कस्टमर्स को समय-समय पर कई तरह की सर्विस देते हैं। सोशल मीडिया पर अलर्ट भेजे जाते हैं। हम क्षेत्रीय, हिंदी और अंग्रेज़ी अखबारों में विज्ञापन देकर क्लेम सेटलमेंट की ज़रूरतों के बारे में जानकारी देते हैं। हम Facebook और Instagram पेज जैसे सोशल मीडिया पर भी नियमित रूप से विज्ञापन डालकर कस्टमर्स को जानकारी और जागरूकता देते हैं। हम ईमेल, WhatsApp मैसेज, My LIC ऐप, डाक से भेजे जाने वाले लेटर और कभी-कभी IVRS या AI एजेंट वॉइस बॉट के ज़रिए भी जानकारी शेयर करते हैं।

3. आवश्यक सेवाओं के व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र स्थापित किए गए हैं।

पॉलिसीधारकों को उनके द्वारा अनुरोधित सेवाओं के बारे में एसएमएस के माध्यम से अपडेट रखा जाता है। समाचार पत्रों में प्राकृतिक आपदा के मामले में विज्ञापन दिया जाता है, जो ग्राहकों को दावे की प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायता करता है ताकि दावे का त्वरित और परेशानी मुक्त प्रोसेसिंग हो सके।

सेवा में व्यवधान / बंद होने के किसी भी जोखिम के मामले में मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ हमारे पास एक व्यवसाय निरंतरता योजना है।

4. क्या इकाई स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य के अलावा उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों / सेवाओं, इकाई या इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है?

बीमा उत्पादों और सेवाओं के बारे में ज़रूरी जानकारी हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध है।

इस जुड़ाव के कुल अनुभव पर ग्राहकों की राय जानने के लिए, ग्राहकों की बैठकों और भुगतान करने वाले अधिकारियों से मुलाकात के ज़रिए फ़ीडबैक लिया जाता है।

RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com,
ramakant@rkgroup.co.in

INDEPENDENT REASONABLE ASSURANCE REPORT ON IDENTIFIED SUSTAINABILITY INFORMATION IN THE BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT (BRSR) FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2026

To,
The Board of Directors
Life Insurance Corporation of India
Central Office, "Yogakshema",
Jeevan Bima Marg,
Mumbai - 400 021.

We have undertaken to perform a reasonable assurance engagement for Life Insurance Corporation of India (the "Corporation") vide appointment letter dated 24.04.2026 issued by the Corporation and accepted by us vide our engagement letter dated 24.04.2026 in respect of the agreed Sustainability Information referred in accordance with the Criteria stated in the "Criteria" paragraph below. The Identified Sustainability Information is included in the Business Responsibility and Sustainability Report ("BRSR") Section of the Integrated Annual Report of the Corporation for the financial year ended March 31, 2026 pursuant to the requirement of Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "LODR Regulations").

Criteria

The criteria used by the Corporation to prepare the Identified Sustainability Information is the "BRSR" as detailed in Annexure 1 to this report (the "Criteria"), which is a subset of the BRSR, consisting of a set of KPIs/ metrics under nine Environmental, Social and Governance ("ESG") attributes, as specified by SEBI vide its circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July 12, 2023 (the "SEBI Circular"), SEBI/HO/CFD-PoD-1/CIR/2025/42 dated 28th March, 2025, the Guidance note for BRSR read with National Guidelines for Responsible Business Conduct issued by

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com,
ramakant@rkggroup.co.in

Ministry of Corporate Affairs ("BRSR Framework") and Industry Standards on Reporting of BRSR Core vide SEBI circular no. SEBI/HO/CFD-PoD-1/D/CIR/2024/177 dated 20th December 2024.

Management's Responsibility

The Corporation's management is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the Identified Sustainability Information, taking into account applicable laws and regulations, if any, related to reporting on the Identified Sustainability Information, identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the Criteria. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and the measurement of the Identified Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error. The Management and the Board of Directors of the Corporation are also responsible for overseeing the Corporation's compliance with the requirements of the LODR Regulations, the SEBI Circular and BRSR Framework in relation to the sustainability information included in the Annual Report.

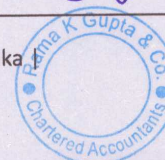
Inherent limitations in preparing the Identified Sustainability Information

The absence of a significant body of established practice on which to draw to evaluate and measure non-financial information allows for different, but acceptable, measures and measurement techniques and can affect comparability between entities. In addition, Greenhouse Gas ("GHG") quantification is subject to inherent uncertainty because of incomplete scientific knowledge used to determine emissions factors and the values needed to combine emissions of different gases.

Auditor's Independence and Quality Control

We are independent of the Corporation and have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkggroup.co.in

Accountants of India ("ICAI") and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement. Our firm applies Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements" and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express a reasonable assurance in the form of an opinion on the Identified Sustainability Information based on the procedures we have performed and evidence we have obtained. We conducted our engagement in accordance with the Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information", issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the ICAI. The standard requires that we plan and perform our engagement to obtain reasonable assurance about whether the Identified Sustainability Information are prepared, in all material respects, in accordance with the Criteria. A reasonable assurance engagement involves assessing the suitability in the circumstances of the Corporation's use of the Criteria as the basis for the preparation of the Identified Sustainability Information, assessing the risks of material misstatement of the Identified Sustainability Information whether due to fraud or error, responding to the assessed risks as necessary in the circumstances and evaluating the overall presentation of the Identified Sustainability Information.

The procedures we performed were based on our professional judgement and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records.

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.

Chartered Accountants

"JAIGURUDEV"



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.

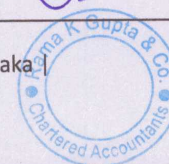
Mobile: 09425112778, 8770223278

Email: ramakantgupta@yahoo.com,
ramakant@rkgroup.co.in

Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, our work procedures included the following:

- Obtained an understanding of the Identified Sustainability Information and related disclosures.
- Obtained an understanding of the assessment criteria and their suitability for the evaluation and/or measurements of the Identified Sustainability Information.
- Made enquiries of Corporation's Management, including the various teams such as Sustainability team, and those with responsibility for managing Corporation's Annual Reporting.
- Obtained an understanding and performed an evaluation of the design of the key systems, processes, and controls for managing, recording and reporting on the Identified Sustainability Information. This did not include testing the operating effectiveness of management systems and controls.
- Based on above understanding, the risks that the Identified Sustainability Information may be materially misstated, determined the nature, timing, and extent of further procedures.
- Performed substantive testing on a sample basis of the Identified Sustainability Information within the standalone boundary to check that data had been appropriately measured with underlying documents recorded, collated, and reported. This included assessing records and performing testing, including recalculation of sample data to establish an assurance trail.
- Checked the consolidation for various sites and corporate office under the standalone reporting boundary (as mentioned in the Integrated Annual Report, which includes BRSR) for ensuring the completeness of data being reported.
- Assessed the level of adherence to the BRSR format issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) followed by the Corporation in preparing the BRSR.
- Obtained representations from the Corporation's Management.
- Assessed the BRSR for detecting, on a test basis, any major anomalies between the information reported in the BRSR on performance with respect to agreed information and relevant source data/information.
- Where applicable for the Identified Sustainability Information in the BRSR, we have relied on the information in the audited standalone financial statements of the Corporation for the year ended March 31, 2026.

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com,
ramakant@rkgroup.co.in

- Evaluated the reasonableness and appropriateness of significant estimates and judgments made by the Management in the preparation of the Identified Sustainable Information.

Exclusions

Our reasonable assurance engagement scope excludes the following and therefore, we do not express an opinion on the same:

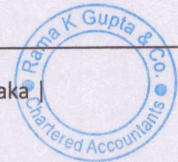
- Any disclosure other than those mentioned in the Identified Sustainability Information section above;
- Data and information outside the defined reporting period;
- Data related to Corporation's financial performance, strategy and other related linkages expressed in the Report;
- The Corporation's statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, forward looking statements provided by the Corporation and assertions related to Intellectual Property Rights and other competitive issues; and
- Mapping of the Report with reporting frameworks other than those mentioned in Reporting Criteria above.
- We have not performed any procedures with respect to prior periods information.

While we considered the effectiveness of management's internal controls when determining the nature and extent of our procedures, our assurance engagement was not designed to provide assurance on internal controls. The procedures did not include testing controls or performing procedures relating to checking aggregation or calculation of data within IT systems.

Opinion

Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained, the Identified Sustainability Information included in the BRSR for the financial year ended 31st March 2026 is prepared in all material respects, in accordance with the Criteria.

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com,
ramakant@rkggroup.co.in

Restriction on use or distribution

Our obligations in respect of this report are entirely separate from, and our responsibility and liability is in no way changed by, any other role we may have (or may have had) as auditors of the Corporation or otherwise, nothing in this report, nor anything said or done in the course of or in connection with the services that are the subject of this report, will extend any duty of care we may have in our capacity as auditors of the Corporation.

This report has been issued at the request of the Board of Directors of the Corporation to whom it is addressed, solely to enable them to comply with the requirements of the Circular and LODR Regulations and on reporting Corporation's sustainability performance and activities, for publishing the same in the Corporation's Integrated Annual Report, which includes the BRSR. Our report should not be used for any other purpose or by any person other than the addressee of our report. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

Place: Mumbai
Date: 17.06.2026



For Rama K. Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 005005C



CA Abhay Gupta
Partner
Membership No. 087679
UDIN: 26087679SDRVXU9956

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |

RAMA K. GUPTA & CO.

Chartered Accountants

"JAIGURUDEV"



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkggroup.co.in

Annexure I**BRSR Core Attributes**

BRSR Indicator	Type of Assurance
Principle 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment	
Attribute 1: Green-house gas (GHG) footprint	
Question 7: Details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity owned or controlled sources.	Reasonable
Total Scope 1 emissions	
Total Scope 2 emissions	
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee crore of turnover	
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
Attribute 2: Water footprint	
Question 3: Details of the following disclosures related to water:	Reasonable
Water withdrawal by source (in kiloliters)	
Total volume of water withdrawal (in kiloliters)	
Total volume of water consumption (in kiloliters)	
Water intensity per rupee crore of turnover (Total water consumption / Revenue from operations)	
Water intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity(PPP)	
Water intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
Question 4: Details related to water discharged:	
Water discharge by destination and level of treatment (in kiloliters)	

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka
 | Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |

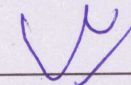


RAMA K. GUPTA & CO.
 Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkggroup.co.in

Total water discharged (in kiloliters)	
Attribute 3: Energy footprint	
Question 1: Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity:	Reasonable
Total energy consumed from renewable sources	
Total energy consumed from non-renewable sources	
Energy intensity per rupee crore of turnover (Total energy consumed / Revenue from operations)	
Energy intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Energy intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
Attribute 4: Embracing circularity - details related to waste management by the entity	
Question 9: Provide details related to waste management by the entity:	Reasonable
Total Waste generated for each category of waste (in metric tonnes)	
Waste intensity per rupee crore of turnover (Total waste generated/Revenue from Operations)	
Waste intensity per crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Waste intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, reusing or other recovery operations (in metric tonnes)	
For each Category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)	
Principle 3: Businesses should respect and promote the well-being of all employees, Including those in their value chains	
Attribute 5: Enhancing Employee Wellbeing and Safety	



Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
 Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.

Chartered Accountants

"JAIGURUDEV"



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkggroup.co.in

Question 1(C): Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent): Cost incurred on well-being measures as a % of total revenue of the company	Reasonable
Question 11: Details of safety related incidents for Employees and Workers:	
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	
Total recordable work-related injuries	
No. Of fatalities	
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	
Principle 5: Businesses should respect and promote human	
Attribute 6: Enabling Gender Diversity in Business	
Question 3(b): Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity	Reasonable
Question 7: Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:	
Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act. 2013 (POSH)	
Complaints on POSH as a % of female employees /workers	
Complaints on POSH upheld	
Principle 8: Businesses should promote inclusive growth and equitable development	
Attribute 7: Enabling Inclusive Development	
Question 4: Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:	Reasonable
a. Directly sourced from MSMEs/ small producers	
b. Directly from within India	
Question 5: Job creation in smaller towns — Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent/on contract basis) in smaller towns, as % of total wage cost.	
Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customer in a responsible manner	

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
 Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
 Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkggroup.co.in

Attribute 8: Fairness in Engaging with Customers and Suppliers

Question 7: Provide the following information relating to data breaches:	Reasonable
a. Number of instances of data breaches	
b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers	
c. Impact, if any, of the data breaches	
Question 8: Number of days of accounts payable $((\text{Accounts payable} \times 365) / \text{Cost of goods/services procured})$	

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Attribute 9: Open-ness of business

Question 9: Details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties:	Reasonable
Concentration of Purchases	
Concentration Of Sales	
Share of RPTs in	
a. Purchases (Purchases With related parties / Total purchases)	
b. Sales (Sales to related parties / Total Sales)	
c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties / Total loans & advances)	
d. Investments (Investments in related parties / Total Investments made)	



Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
 Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



Environmental, Social and Governance (ESG) Overview

As an organization, LIC recognizes that strong ESG practices are key to long-term value, financial strength and stakeholder trust. As a leading insurer and institutional investor, we support sustainable and inclusive growth. Our ESG approach continues to evolve in line with regulations and global best practices.



ESG Governance Framework



We follow a structured ESG framework guided by IRDAI and SEBI regulations, including BRSR requirements.



ESG oversight is integrated into senior management and Board decisions, making sustainability part of strategy, risk management and capital allocation.



Our approach aligns with global frameworks like the UN SDGs, UN PRI and UN PSI, helping us improve continuously and integrate ESG into all decision-making.



Social Responsibility:

Our social focus is built on inclusion, fairness and community well-being. We ensure accessibility for divyang employees and customers through ramps and inclusive facilities. Through our 'plant a life' initiative we have planted 11,47,574 saplings across India during the FY 25-26.

Customers:

We provide accessible services through digital tools like My LIC App and provide online grievance management systems for quick resolution through tools like ICMS, Bima Bharosa, CPGRAM etc.

Agents:

We provide paperless onboarding and digital marketing through tools like the 'LIC ANANDA' app. Agents are also provided with a welfare scheme LIC Abhikarta Suraksha Yojana which provides a free cover of 2 lakh INR on unfortunate death of the agent.

LIC Bima Sakhi (Mahila Career Agent Scheme) encourages women empowerment. This program is specifically designed to transform homemakers and young women into professional financial consultants.



Environmental Stewardship

We aim to achieve Net Zero and Water Neutral operations by 2050. Our environmental efforts support a low-carbon and resource-efficient future.

Key initiatives include:

- ✓ ESG Framework to manage environmental, social and governance issues approved by the Board on 5th Feb 2026.
- ✓ Climate Risk Management Framework to address climate risks in underwriting, investments and operations approved by the Board on 5th Feb 2026.
- ✓ Reducing emissions through energy efficient lighting, upgraded HVAC systems and renewable energy adoption.
- ✓ Promoting paperless operations through e-policies and digital onboarding and projects like DIVE & HRMS.
- ✓ Promoting green infrastructure, including rooftop solar panels and green buildings.
- ✓ Strengthening water management through conservation, rainwater harvesting, recycling and responsible waste disposal.

We track progress through regular monitoring, audits and improvements.

Employees:

One among many initiatives is "LIC Gyanpeeth", a Learning Management System with the aim to facilitate self-learning and self-skilling among our employees promoting a safe and inclusive work environment.



Vendors and Partners:

We follow responsible procurement, focusing on ethics, compliance, health and safety, and ESG-based vendor evaluation.

Governance and Ethical Conduct:

Strong governance ensures transparency and accountability. We maintain robust internal controls, audits and compliance systems.

Our focus areas include:

- Strengthening compliance and enterprise risk management
- Ensuring data protection and cyber security
- Integrating ESG and climate risks into risk management
- Promoting responsible investments
- Regularly updating ESG policies and disclosures

Monitoring, Measurement and Reporting

We monitor ESG performance through internal committees and Board oversight. Reporting follows SEBI BRSR, IRDAI guidelines and global frameworks. We are improving data quality and transparency, with independent assurance to strengthen stakeholder confidence.

Way Forward

We at LIC are adopting a phased approach for ESG, which enables our corporation to progressively embed sustainability into its core insurance, investment and risk management functions. By integrating ESG considerations into strategy, operations and governance, LIC seeks to enhance long-term financial stability, manage emerging risks and respond effectively to opportunities arising from the transition to a sustainable economy and continue to contribute to the nation's development.



Community Development Activities undertaken during FY 2025-26 through LIC Golden Jubilee Foundation



Educational Support: Awarded 10,660 new scholarships, nearly three times the number granted in the previous year.



Empowering Youth through Education: Enabled meritorious students from economically weaker sections to pursue higher education through sustained financial assistance.



Strengthening Healthcare Infrastructure: Supported hospitals and medical institutions through the provision of advanced medical equipment, ambulance, treatment.



Enhanced Geographic Reach: Extended support to beneficiaries across multiple States and Union Territories, strengthening the Foundation's national footprint.



Focus on Inclusive Development: Continued interventions in education, healthcare, skill development, and community welfare, benefiting underprivileged and marginalized communities.



Sustainable Social Impact: Reinforced the Foundation's commitment to creating long-term, sustainable improvements in the quality of life of underserved communities.

The Foundation continues to foster education, healthcare, women empowerment, and community well-being, contributing towards the vision of holistic and equitable development in some of the nation's most underserved regions.



Business Responsibility and Sustainability Report

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES:

I. Details of the listed entity:

1. Corporate Identity Number(CIN) of the Listed Entity

- Not Applicable
- IRDAI Registration Number – 512

2. Name of the Listed Entity

- Life Insurance Corporation of India (Constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956)

3. Year of incorporation

- 1956

4. Registered office address

- Central Office, Yogakshema, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021.

5. Corporate address

- Central Office, Yogakshema, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021.

6. E-mail

- ed_rms@licindia.com

7. Telephone

- 022-22022615

8. Website

- www.licindia.in

9. Financial year for which reporting is being done

- Financial Year 2025-26

10. Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed

- NSE (National Stock Exchange of India Limited) and BSE Limited.

11. Paid-up Capital:

- ₹ 6,324.99 crore divided into 632,49,97,701 Equity Shares of ₹ 10 each.

12. Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report-

- Ms Rosaline Kurien/ 022-22022615 / ed_rms@licindia.com

13. Reporting boundary – Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together).

- The disclosures under this report are made on a standalone basis, unless otherwise specified.

14. Name of Assurance Provider

- M/s Rama K Gupta & Co., Chartered Accountants

15. Type of assurance obtained:

- Assurance for Business Responsibility and Sustainability Report. The report issued by assurance provider is annexed as Annexure I of this report.

II. Products/services

16. Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):

Sr. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover of the entity
1.	Insurance Services including Pension and Health	Life Insurance	100%

17. Products/Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover):

Sr. No.	Product/Service	NIC Code	% of total Turnover contributed
1.	Life Insurance	65110	100%

III. Operations:

18. Number of locations where plants and/or operations/offices of the entity are situated:

Location	Number of plants	Number of offices	Total
National	NA	5,004	5,004
International	NA	121*	121

* Total no. of Offices (International):

Sr. No.	Unit	Corporate	Branch Office
1	LIC Fiji		1
2	LIC Mauritius		1
3	LIC UK*		1
4	Life Insurance Corporation (International) BSC (c)#	1	4
5	Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.	1	76
6	Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd.	1	23
7	Life Insurance Corporation of Bangladesh Ltd.	1	9
8	Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd.*	1	0
9	IFSC Insurance Office, GIFT City, Gandhinagar		1
Total :		5	116
		121	

#LIC (International) BSC (c), Bahrain company operates in GCC (Gulf Cooperation Council) countries of Bahrain, Kuwait* and UAE (Dubai & Abu Dhabi)

*closed to New Business

19. Markets served by the entity:

a. Number of locations

Locations	Number
National (Number of States/UT)	36 (28 states and 8 UTs in India)
International (Number of Countries)	10

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Nil

c. A brief on types of customers

Life Insurance is the primary business of the Corporation. We cater to a wide variety of customers across different segments. Based on various factors like demographics, need, financial goals, etc., the customers can be broadly categorized into the following groups:

- Individuals with regular income: They look for life cover, tax benefits, savings, etc. They prefer endowment, money back and term plans
- Self-employed business owners: They are interested in wealth creation with risk cover, seeking flexible premium options with a preference for ULIPs and pension plans.
- Minors, students and young professionals: They are mostly covered by term or simple endowment plans and look for low premium.
- Senior citizens: They look towards pension plans and seek guaranteed income and long term security.
- Group customers: They include corporate clients, Government organisations, Associations, NGOs, etc. The types of schemes sought cover group term life, gratuity, superannuation, leave encashment, etc.
- NRI Customers: They take life insurance for family security in India, prefer long term savings or term plans and see us as a secure and trusted brand.
- Rural and social sector customers: We have focussed products under government mandates like PMJJBY, etc., wherein affordable insurance is given for low income groups and tailored policies for farmers, labourers, etc.
- High net worth individuals: They are a distinct group and seek investment oriented plans like ULIPs, wealth plans or pension schemes with large coverage.

IV. Employees**20. Details as at the end of Financial Year 2025-26:****a. Employees and workers (including differently-abled):**

Employees					
Particulars	TOTAL (A)	MALE		FEMALE	
		No.(B)	%(B/A)	No.(C)	%(C/A)
Permanent (D)	84565	64161	75.87	20404	24.13
Other Than Permanent (E)	13	12	92.31	1	7.69
Total Employees (D+E)	84578	64173	75.87	20405	24.13
Workers					
Particulars	TOTAL (A)	MALE		FEMALE	
		No.(B)	%(B/A)	No.(C)	%(C/A)
Permanent (F)	There is no class of employees as "Workers" in the Corporation				
Other Than Permanent (G)					
Total Employees (F+G)					

b. Differently-abled Employees and workers:

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	888	723	81.42	165	18.58
2.	Other than Permanent (E)	0	0	0	0	0
3.	Total differently abled employees (D + E)	888	723	81.42	165	18.58
DIFFERENTLY ABLED WORKERS						
4.	Permanent (F)	There is no class of employees as "Workers" in the Corporation				
5.	Other than permanent (G)					
6.	Total differently abled workers (F + G)					

21. Participation/ Inclusion/ Representation of women

	Total (A)	Number and percentage of Females	
		Number (B)	%(B/A)
Board of Directors	10	1	10.00%
Key Management Personnel / Key Management Persons (KMP)*	10	0	0

*KMPs includes 4 whole time directors

22. Turnover rate for permanent employees and workers: (Disclose trends for past 3 years)

	Turnover rate for permanent employees for the past 3 years								
	FY 2025-26			FY 2024-25			FY 2023-24		
	MALE	FEMALE	TOTAL	MALE	FEMALE	TOTAL	MALE	FEMALE	TOTAL
Permanent Employees	8.36	7.23	8.09	8.60	7.14	8.25	6.80	5.67	6.54

Note:

- There is no class of Employees termed as 'workers' in the Corporation.
- The turnover rates include Superannuation numbers, as well.

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies

23. (a) Names of Holding / Subsidiary / Associate Companies

Sr. No.	Name of the Holding / Subsidiary / Associate Companies Column 'A'	Indicate whether Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
International				
1	Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Limited	Subsidiary	100%	No
2	LIC (International) BSC (c), Bahrain	Subsidiary	99.66%	No
3	Life Insurance Corporation (Nepal) Limited	Subsidiary	55%	No
4	Life Insurance Corporation (Lanka) Limited	Subsidiary	97.22%	No

Sr. No.	Name of the Holding / Subsidiary / Associate Companies Column 'A'	Indicate whether Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
5	Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Limited	Subsidiary	83.33%	No
National				
1	LIC Pension Fund Limited	Subsidiary	100	No
2	LIC Cards Services Limited	Subsidiary	100	No
3	IDBI Bank Limited	Associate	49.24	No
4	LIC Mutual Fund Trustee Private Limited	Associate	49.00	No
5	LIC Housing Finance Limited	Associate	45.24	No
6	LIC Mutual Fund Asset Management Limited	Associate	49.87	No
7	IDBI Trusteeship Services Limited	Associate	29.84	No
8	LIC HFL Asset Management Company Limited	Associate	5.38	No

VI. CSR Details

24. (i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: (Yes/No)

- No. CSR is not applicable as per section 135 of Companies Act, 2013.

Life Insurance Corporation of India was established by the Life Insurance Corporation Act, 1956 ('LIC Act 1956'), enacted by Parliament to nationalize the life insurance industry in India. As such, LIC is not a company governed by the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013. The Corporation is outside the purview of CSR activities mandated under the Indian Companies Act, 2013 even after the recent amendments to the LIC Act, 1956.

However, guided by its enduring commitment to social responsibility and nation-building, LIC established the LIC Golden Jubilee Foundation in the year 2006 during its Golden Jubilee year. The Foundation is registered as a Charitable Trust under the Bombay Public Trust Act, 1950, and has been voluntarily carrying out meaningful community development initiatives across the country.

The Foundation is dedicated to the objectives of relief of poverty and distress, advancement of education, medical relief and promotion of projects of general public utility. Through its people-centric approach, it extends support to disadvantaged, marginalized, and underprivileged sections of society and strives to create meaningful and sustainable change.

The initiatives undertaken by the Foundation span a wide spectrum of social welfare activities, including scholarships for deserving students, healthcare and medical support, rural education program, vocational and skill development initiatives and infrastructure support in the fields of education and health. Through these sustained efforts, the LIC Golden Jubilee Foundation continues to uphold LIC's legacy of compassion, service, and commitment towards inclusive growth and social empowerment.

The financial year 2025-26 has been a truly remarkable year for the Foundation, marked by several landmark achievements and meaningful social initiatives with major focus on education and healthcare. Through dedicated efforts and unwavering commitment, the Foundation has expanded its reach and positively impacted numerous lives across the country. Our initiatives in education, healthcare, skill development and community welfare have created sustainable change and strengthened our mission of inclusive growth. The

highest number of projects were sanctioned in this year – a total of **119 projects worth ₹ 77.74 Crores**. Health related projects received the highest ever allocation for ₹ 62.20 Crores. The number of new scholarships has **tripled to 10660**. These Scholarships are given to meritorious students from underprivileged families, enabling them to pursue their dreams with confidence and dignity. 2025-2026 saw the highest disbursement towards scholarships.

Since inception, the Foundation has sanctioned **1045 projects for ₹ 303 Crores as on 31.03.2026**. Of this, **417 projects pertain to educational areas, 437 to health care and 191 projects** pertain to advancement **towards General Public Utility**. The Foundation's journey stands as a shining example of how purposeful action can transform communities and build a brighter future for all.

(ii) **Turnover (in ₹)** - 5,36,748.56 crores

(iii) **Net Worth (in ₹)** - 1,75,356.38 crores

VII. Transparency and Disclosures Compliances

25. Complaints/ Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

Stake-holder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No) (If Yes, then provide web-link for grievance redressal policy)	FY 2025-26			FY 2024-25		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Investors (other than shareholders)	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	
Share-holders	Yes, KFin technologies Ltd. is the Registrar and Share transfer Agent (RTA) of the Corporation to aid in resolution of the grievances and queries pertaining to shareholder Services. The Corporation has a designated e-mail address (investors@licindia.com) and portal for shareholders to enable them to raise the grievances. Link for investor support: https://licindia.in/investors-support	922	3	Three (3) queries were pending as on 31.3.2026 and satisfactorily resolved on 01.04.2026	1671	1	The lone query pending as on 31.3.2025 was resolved on 01.04.2025
Employees	Yes, the Corporation has developed an internal mechanism system for redressal of grievances. For this purpose a portal available on the intranet called e-Samadhan where grievances can be registered by any employee which is forwarded to the Staff Grievance Officer.	351	11	NIL	369	12	All 12 complaints were resolved in FY 2025-26.
Customers	https://licindia.in/web/guest/policy-for-protection-of-interests-of-policyholders	66,424	0		74,290	NIL	
Communities	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	

Stake-holder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No) (If Yes, then provide web-link for grievance redressal policy)	FY 2025-26			FY 2024-25		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Value Chain Partners	Yes. Value chain partners can report their grievances, if any, to the nearest office and through other digital modes.	NIL	NIL		NIL	NIL	
Others-Ministry	Compliance to Ministry through Emails	141	1	Follow up in process	168	1	The lone complaint was resolved in FY 2025-26.

26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues:

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format:

Sr. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1	Regulatory and Compliance environment	Risk and Opportunity	Regulatory compliance is an integral part of LIC's work ethics. Failure to adhere to any applicable laws in a timely manner can lead to potential legal action, reputational damage or even financial losses. LIC, being a listed company strives to be compliant to all the applicable laws and regulations. By adopting to standards as laid down we believe that we will be able to protect the interest of all our stakeholders. We ensure that all our rules and regulations affecting all our stakeholders are within the legal and regulatory frameworks. As a public sector institution, we are also bound by RTI guidelines which act as an additional layer of scrutiny.	LIC has a well-established system to ensure regulatory compliance which ensures adherence to various regulatory requirements.	Financial implications of not addressing the risks identified can include penalties arising from regulators or other legal forums while addressing customer grievances. Losses can also arise from New Business front due to negative customer sentiments. Adherence to regulatory guidelines can enhance customer satisfaction there by increasing our customer loyalty which in turn can increase our persistency and inflow of new customers.

Sr. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
2	Human Capital Development	Risk and Opportunity	<p>Opportunity: As a key player in a knowledge industry, our human capital is a major source of strength and competitive advantage. Continuous up-skilling will enable us to strengthen our leadership position and combat all challenges facing the industry in a better way.</p> <p>Risk: In the current competitive scenario and rapidly changing marketing conditions, it is a challenge to retain young talent.</p>	<p>LIC is a mammoth Trans National organization with approximately eighty five thousand employees. On account of the size and geographical spread as well as keeping with the personnel policies there is continuous vertical and lateral movement in the organisation. All these factors necessitate that there has to be a continuous process of skill development and upscaling the knowledge base within the organization. The pandemic situation necessitated and propelled the organization to move towards self-learning through digital mode. This has enabled standardized content without dependence on physical infrastructure and facilitators and is available anywhere any time on intranet/internet. The current focus has been to make communication and collaboration easily available as part of the new work experience.</p> <p>Further, with the aim of self-learning/ self-skilling, a Learning Management System, 'LIC Gyanpeeth' was introduced for the employees.</p>	High employee turnover may lead to decrease in productivity, increase in hiring cost, particularly arising from recruitments at Senior Levels and low employee morale in general.
3	ESG and Climate Risk Management	Risk	<p>There is an increased awareness in Society for protection of environment.</p> <p>Stringent Regulations are emerging to ensure protection of environment. If we do not meet aspirations of the Society or fail to comply with relevant regulations, it may result into reputational loss and may also attract stringent penalty.</p>	To promote sustainable business practices, responsible management, and transparency, we have a Board approved ESG framework and Climate Risk Management framework within the organization. Various ESG related risks and Climate Risks have been identified and have been integrated with the Risk Management Framework. These risks are being assessed periodically by all the offices of the Corporation. There is an emerging Risk Module available for Risk Owners to identify new ESG and Climate Risks so as to include them in the Risk Management framework.	Negative

Sr. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
4	Privacy and Data Security	Risk	<p>Sustaining Customer trust requires robust Data Privacy and Cyber Security. As we undergo digital transformation, protecting customer data is critical to our being customer-centric and compliant to Data Protection laws.</p> <p>Cyber Security related incidents can impact our reputation, customers, and our business. It becomes essential therefore to continuously evaluate, mitigate and implement Cyber Security and Privacy related measures to protect customer data.</p>	<p>LIC accords Cyber Security and Data Privacy the highest importance and on an on-going basis is investing in newer and robust technologies and complying with the industry best cyber security policies, processes and regulations. The IT Strategy Committee of the Board and Executive level Committees ensures oversight over cyber security and data privacy matters. LIC undertakes audit, security assessments and validation of controls against cyber threats and its remediation. We are ISO 27001 certified and are under the process of implementation of DPDP Act.</p>	Financial and reputational loss can be damaging.
5	Business Continuity	Risk	<p>A systematically designed Risk Management framework and Business Continuity Plan is essential to ensure long term sustainability, improved market valuation and brand image' also strengthen stakeholder's trust. It supports better financial and operational performance and business resilience.</p>	<p>Corporation has a Board-approved Business Continuity Management (BCM) Plan designed to ensure continuity of critical operations in the event of disruptions such as system failures, natural disasters, or cyber incidents.</p> <p>The plan aims to minimize downtime, safeguard critical functions, reduce financial losses and enable swift recovery. The BCM Plan provides detailed procedures for the continuity or rapid restoration of critical business functions and the Corporation is certified under ISO 22301 for its Business Continuity Management System, reflecting its strong commitment to operational preparedness.</p>	Negative

SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Policy and management processes									
1. a. Whether your entity's policy/ policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	NA	Y	Y
c. Web Link of the Policies, if available	https://licindia.in/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct . Some of the policies of the Corporation are offered to employees only and are available on the intranet site of the Corporation.								
2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes /No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	NA	Y	Y
3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)	Our value chain partners are contractually obliged to comply with requirements pertaining to safety and healthy environment, prohibition of child labor and forced labor, non-discrimination, employment condition, provision of wages and working hours.								
4. Name of the national and international codes/ certifications/ labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fair trade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g. SA8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	Under Principle 4 , LIC has obtained: ISO 31000 for ERM ISO 22301 for BCP								
5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any	<p>a. We are committed to incorporating ESG principles in our business activities</p> <p>b. We are committed to conserving water, reducing energy use and reduce our carbon footprint as well as GHG emissions.</p> <p>c. We are an equal opportunity employer ensuring no discrimination on any grounds whatsoever.</p> <p>d. Spread life insurance widely and in particular to the rural areas and to the socially and economically backward classes with a view to reaching all insurable persons in the country and providing them adequate financial cover against death at a reasonable cost.</p> <p>e. Maximize mobilization of savings by making insurance linked savings adequately attractive.</p> <p>f. In investment of funds, the primary obligation to its policyholders, whose money it holds in trust, without losing sight of the interest of the community as a whole; funds to be deployed to the best advantage of the investors as well as the community as a whole, keeping in view national priorities and obligations of attractive return.</p>								

	<ul style="list-style-type: none"> g. Conduct business with utmost economy and with the full realization that the money belongs to the policyholders. h. Act as trustees of the insured public in their individual and collective capacities. i. Meet the various life insurance needs of the community that would arise in the changing social and economic environment. j. Involve all people working in the Corporation to the best of their capability in furthering the interests of the insured public by providing efficient service with courtesy. k. Promote amongst all agents and employees of the Corporation a sense of participation, pride and job satisfaction through discharge of their duties with dedication towards achievement of Corporate Objective.
6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.	<ul style="list-style-type: none"> a. In 2025-2026 alone, we have settled 8,30,399 individual death claims and 2,41,25,943 individual maturity claims with an outgo of 19,019.79 crores INR and 2,37,353.14 crores INR respectively thus providing financial security to dependent families, creditors, partners and key men in case of business insurance, etc. b. We cover 3,70,40,056 lives under the PMJJBY as on 31.03.2026. We have designed other micro insurance products to cater to weaker segments of society. c. Hereditary commission is paid to dependents of over 60297 agents who have expired and were eligible for renewal commission. d. 59% of village panchayats have been covered with at least one Bima Sakhi thereby providing training and employment of lady insurance agents as well as reaching out to the nooks and corners of the country to spread life insurance. e. To provide an impetus to insurance cover in the rural areas we have provided employment opportunities and 2,83,249 Bima Sakhis were in force as on 31.03.2026.
Governance, leadership and oversight	
7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure)	The Board has overall responsibility regarding business responsibility report and to identify and manage ESG issues of the Corporation.
8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy(ies)	Shri R Doraiswamy, CEO & MD; DIN: 10358884

<p>9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.</p>	<p>Yes, Board of Directors (“Board”) has overall responsibility of Corporation’s Governance and Sustainability practices. Board has constituted an Environment, Social & Governance (ESG) Committee. The Committee approves and ratifies the ESG goals, targets, strategy and monitors performance thereof including the ESG initiatives to ensure long-term value creation for the stakeholders and periodically reviews the ESG activities of the Corporation. The Board approved the ESG Framework & Climate Risk Management Framework on the recommendation of the ESG Committee.</p>
<p>10. Details of Review of NGRBCs by the Company</p>	
<p>Performance against above policies and follow up action</p>	<p>The Board/ Committee of Board/ Senior Management of the Corporation have approved the policies that have been stated above as required by extant regulations.</p>
<p>Indicate whether review was undertaken by Director/ Committee of the Board/ Any other Committee</p>	<p>Review done inter-departmentally.</p>
<p>Frequency (Annually/ Half-yearly/ Quarterly/ Any other – please specify)</p>	<p>Half Yearly</p>
<p>Compliance with statutory requirements of relevance to the principles and rectification of any non-compliances</p>	<p>The Corporation complies with all applicable regulations.</p>
<p>11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.</p>	<p>All policies of the Corporation are evaluated internally.</p>

12. If answer to question (1) above is ‘No’ i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
The entity does not consider the Principles material to its business (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	No	-	-
The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	NA	-	-
The entity does not have the financial or/human and technical resources available for the task (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	NA	-	-
It is planned to be done in the next financial year (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	NA	-	-
Any other reason (please specify)	-	-	-	-	-	-	**	-	-

**As a listed entity, LIC operates in a highly regulated environment. Further, the Corporation upholds the highest standards of responsible business conduct as prescribed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and Securities and Exchange Board of India (SEBI). The Corporation also regularly participates in various forums and committees constituted by said regulatory authorities. While there is no specific policy outlined for this principle, the Staff Regulations, 1960, governs all employees and officers who are required to act in accordance with high professional and ethical standards. The Corporation, through trade-bodies and associations, puts forth a number of suggestions with respect to the economy and the insurance sector in particular.

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE:

PRINCIPLE 1: Businesses should conduct and govern themselves with integrity and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Essential Indicators**1. Percentage coverage by training and awareness programs on any of the Principles during the financial year:**

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/Principles covered under the training and its Impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	4	1) Strategy Meet - Session on Business Strategy, Shareholder Value, Technology Transformation, Risk Management, HR Strategy, Financial Asset 2) Session on Artificial Intelligence and Machine Learning 3) Strategy Meet - Session on Business Strategy, Technology Transformation-IT, Actuarial Presentation, HR Strategy, Real Estate Management. 4) Directors' Development Program - III	96.43% 100% 100% 30 % (3 BoDs out of 10 attended)
Key Managerial Personnel	9	1) 44 th India Fellowship Seminar, Mumbai 2) Munich Re Global Life Insurance Seminar at Germany 3) ESG Leadership Development Program at MDC 4) 20 th Current Issues Seminar in Life Assurance (20 th CILA) 5) 45 th India Fellowship Seminar (IFS) 6) 25 th Global Conference of Actuaries (GCA) 7) National convention of company secretaries 8) Training Program for Investment Dept Officials 9) Retirement Training and ESG Leadership Development Program	50 % (5 KMPs out of 10 attended)
Employees other than BoD and KMPs	5,713	LIC Act, 1956 National Convention of ICSI Session on Capturing the movement of UPSI in SDD Orientation session for Nodal officers nominated for compliances	

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/Principles covered under the training and its Impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programmes
		IT & Cyber Security, Digital Transformation & Changing Landscape, IT Initiatives, Social Media, Business Etiquettes, Increase in persistency, focussing on augmenting premium receivables, BCP, ERM, KYC /AML/CFT sessions, IT/ Mobile Apps, MS Office, IRDAI Regulations / Regulatory Sensitisation, New Products / Product based Programs, Customer Service Sensitization / Complaint Resolution, Agents for Career Growth, Telephone & Email Etiquettes / Letter writing / Email Policy, Training for Retiring Officials, PLLI, Multifunctional Training, Health& Safety / Wellness / PoSH, Hassle free KYC for PWD, Compliance Certification Process, Induction training programmes for various cadres, Train the Trainers, RTI Act, Financial Awareness, Fundamentals of Financial Modelling and Forecasting, Investment Orientation, Corporate Governance and Regulatory Compliances, Fixed Income Derivatives, GST Invoice Management System, BRSR, Preventive Forensics, Bond mathematics & Introduction to Indian Treasury Market, Mastering Related Party Transactions & Key Regulations, Insolvency and Bankruptcy Code, Secure Coding Principle, Public Procurement, Leadership Development Program, Integrating Ethics, POSH, Human Rights and ESG, Digital Fraud Awareness, Training Session on Reservation Matters, Strengthening Grievance Redressal(GR), Sensitisation Program- Person with Disability PwD, Effective Procurement, Contracts Administration & Management.	81.53% [68946 employees trained]

Training Activities are carried out through In-House Training Centres and External Training Institutes.

In-house Training:

LIC has an extensive setup of well-equipped In-House Training Centres that cater to the training needs of its workforce, including field personnel, administrative staff and officers at various managerial levels. These centres feature modern infrastructure such as hostel facilities, classrooms, auditoriums, computer labs, LCD facilities, recreational and sports amenities. LIC's In-House Training Centres includes:

- Management Development Centre (MDC): The apex Training Institute of the Corporation.
- Zonal Training Centres (ZTCs): One located in each of LIC's eight Zones.
- Employee Training Centres (ETCs)/ Computer Training Centres (CTCs): One in each of the 113 Divisional Offices.
- Divisional Training Centres (DTCs): One in each of the 113 Divisional Offices for Agents.

External Training:

To introduce fresh perspectives, gain specialized industry expertise and stay aligned with global HR practices, LIC also nominates officials to participate in a variety of External Training Programs offered by renowned Institutions such as National Insurance Academy - NIA (Pune), Indian Institutes of Management – IIMs, Indian School of Business – ISB (Hyderabad), Institute of Directors – IOD (Mumbai), National Institute of Securities Markets – NISM (Mumbai), All India Management Association – AIMA (Delhi), Department of Financial Services – DFS (Delhi), Institute of Actuaries of India - IAI (Mumbai), National Forensic Sciences University – NFSU (Gandhinagar), Steel Authority of India Ltd – SAIL (Ranchi), Arun Jaitley National Institute of Financial Management – AJNIFM (Faridabad), Delhi Metro Rail Academy – DMRA (Delhi), The Institute of Company Secretaries of India – ICSI (Delhi), Administrative Staff College of India – ASCI (Hyderabad), College of Insurance – COI (Mumbai), Bombay Chamber of Commerce and Industry – BCCI (Mumbai), FIMMDA (Mumbai), Bloomasia Incorporated (Mumbai), Princeton Academy (Mumbai), Times Internet (Mumbai), ICICI Bank Ltd, Knolskape Solutions Pvt. Ltd (Bengaluru), NAHRD (Delhi) and Institute of Insurance and Risk Management – IIRM (Hyderabad), Space Education & Training Academy Nagpur IISWBM – Kolkata, Management Development Institute (MDI) Gurugram, BML MUNJAL, Delhi, etc.

The number of participants trained in various sessions conducted in-house by MDC and other training institutions number 1,51,176. The participants trained in external training institutes including NIA numbered 6,935. Thus 1,58,111 participants were trained with some having attended multiple training sessions on different subjects and also on change of roles during the same period.

Short duration Webinars:

To reach a wider segment of employees and the field force, a series of short-duration webinars were conducted, in collaboration with External Training Institutes as well as at our In-House Training Centers. These webinars cover a broad spectrum of topics such as:

- New digital initiatives, Cyber security and prevention of Cyber fraud
- New Business parameters and performance indicators
- Marketing development programs covering intermediaries, products and sales techniques.
- Underwriting rules including Key-Man Insurance, Employer-Employee Schemes, MWP Act, female life, minor life and non-medical
- Policy servicing, Revival, Persistency and Claim Settlement including Re-investment
- Preventive Vigilance.

LIC Gyanpeeth – Self Learning Management System Module:

- LIC Gyanpeeth is a digital self-learning and self-skilling platform introduced in 2020. It offers standardized training content without the need for physical infrastructure or facilitators, enabling employees to access learning materials anytime and from anywhere 24/7 through intranet or internet browsers.
- The self-learning portal is specifically designed to ensure uninterrupted training across various functional domains. Continuous enhancements and updates are being made to improve its effectiveness. As of 31st March, 2026, LIC Gyanpeeth contains 19 main modules, 166 sub-modules and 8,180 MCQs.
- 'LIC Gyanpeeth' has received an overwhelming response from employees, with approximately 75,057 (89.69%) employees earning a total of 24,29,843 LIC Gyanpeeth Certificates.
- Number of main module certificates issued under Gyanpeeth module was 2,91,712 and the number of sub modules for which certificates were issued numbered 21,38,131, together totaling 24,29,843 certificates being thus issued.

2. Details of fines/ penalties/ punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors/ KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format

(Note: The entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount (In ₹)	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)
Penalty/ Fine	NIL	Revenue Authorities like Income Tax Authority, GST Authorities, etc.	0.02 crore	Wrong Utilization of ITC, Non Issuance of e-Way Bill, Late Filing of TDS Return, Penalty on Service tax on expenses reimbursement to agent	No
Settlement	NIL	NIL	NIL	NIL	NA
Compounding fee	NIL	NIL	NIL	NIL	NA
Non-Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)	
Imprisonment	NIL	NIL	NIL	NIL	
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal /Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.-

Case Details	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions
NIL	NIL

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

The Corporation maintains an Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy. The Corporation also has a Whistle-blower policy. Additionally, as per the provisions of Rule 32 of LIC of India (Staff) Rules, 1960, no employee or any member of the family of the employee is allowed to accept the gifts of more than the trifling value. The link for anti-bribery and anti-corruption policy is as under:

<https://licindia.in/documents/d/guest/anti-bribery-and-anti-corruption-policy-1->

5. Number of Directors/ KMPs/ employees/ workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

	FY 2025-26	FY 2024-25
Directors	NIL	NIL
KMPs	NIL	NIL
Employees	2	1

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

	FY 2025-26		FY 2024-25	
	Number	Remarks	Number	Remarks
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	Nil	NA	Nil	NA
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	Nil	NA	Nil	NA

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines /penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest

Proceedings are underway in the 2 cases registered against employees.

8. Days of accounts payable: ((Accounts payable*365)/ Cost of goods / services procured):

	FY - 2025-2026	FY - 2024-2025
Number of days of accounts payable	23.53	12.12

9. Openness of business:

Details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties:

Some parameters are not applicable for Insurance/ service sector, and hence information is provided to the extent applicable. However, during the FY 2024-25 due to misinterpretation, it was provided.

Parameter	Metrics	FY 2025-2026	FY 2024-2025
Concentration of Purchases**	a. Purchases from brokers as % of total purchases	NA	16.64% secondary market trading
	b. Number of brokers where purchases are made from	NA	142
	c. Purchases from top 10 brokers as % of total purchases from brokers	NA	9.87%
Concentration of Sales**	a. Sales to brokers as % of total sales	NA	12.96% secondary market trading
	b. Number of brokers through whom sales are made	NA	142
	c. Sales to top 10 brokers as % of Total sales to brokers	NA	9.54%

Parameter	Metrics	FY 2025-2026	FY 2024-2025
Share of RPTs in	a. Purchases (Purchases with related parties/ Total Purchases)	2.15%	1.54%
	b. Sales (Sales to related parties/ Total Sales)	2.66%	1.89%
	c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties / Total loans & advances)	NA	NA
	d. Investments (Investments in related parties/ Total Investments made)	NA	NA

** Concentration of Purchases and Sales is Not Applicable as it pertains to Goods and not Services. Therefore not provided this year.

Leadership Indicators

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year:

Total training and awareness programmes held	Topics / principles covered under the training and its impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programme
3971 Sessions	Product Training, Comparison of Product, Skill development, study of Financial Markets.	20.72%
30 Sessions	Yoga, Cleanliness, Save Green, Swachhata Related Topics, Vigilance Awareness, New Plans, Fire Drill, Use of Hindi in Office Work.	48.64%

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes/ No) If yes, provide details of the same.

- Yes, Processes are in place.

Disclosure of interest as well as declaration on Directors' independence is being regularly obtained from Directors and submitted to the Board. Directors recuse themselves from participating in discussion or decisions on agenda Item(s) where they are deemed interested and when such matters are considered during meetings to avoid any conflict of interest. Further, Board of Directors on an annual basis provides an affirmation that they have complied with the code of conduct for Directors and Senior Management Personnel.

PRINCIPLE 2: Business should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators

1. Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.

R&D mainly focuses on product development, monitoring, modifying, closing as well as introducing newer versions with emphasis on its environmental and social impact too. Customer experience and satisfaction continue to be the bedrock on which initiatives in this aspect are worked out including diminishing the usage of paper across the Board.

Capital expenditure is incurred on replacing old energy inefficient appliances like ACs, light bulbs, lifts, etc with modern energy efficient equipment, Installation of solar equipment for leveraging renewable energy, Rain water harvesting to boost water conservation, etc. Its impact is felt in increased energy efficiency, harnessing recyclable resource like sunlight and conservation of water.

2. a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/No)**b. If yes, what percentage of inputs was sourced sustainably?**

(a) Yes. As a part of the Insurance industry, our operations primarily revolve around digital solutions. While our procedures do not directly mirror those of traditional manufacturing, we try to follow guidelines and practices that promote ethical and sustainable sourcing of technology-related inputs. Given the nature of our operations, traditional measures of sustainable sourcing and identifying percentage are not directly applicable. However, we actively participate in broader organisational initiatives to enhance and improve sustainability. Although, there is no specific procedure in place for sustainable sourcing, we follow the procurement policy of the Corporation which complies with guidelines of CVC thus promoting transparency, improving competition and ensuring equity among participants, encouraging 'Make in India'. Moreover, all the procurement is made in e-mode inviting tenders through online channel only eliminating the requirement of physical documents and effort for delivery of such documents.

(b) Not Applicable

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste

As the Corporation is in the Business of Insurance, there is limited scope for using recycled material. Insurance products per se, are intangible. However, our offices are encouraged to recycle e-waste. Servers, computers, cartridges, ribbons are the primary e-waste generated which is disposed through authorized vendors, who pick up the hardware e-waste from all locations after dismantling/degaussing. Re-cycling certificates are also obtained. For collection and disposal of e-waste and electrical waste, safe disposal collection boxes are kept at various offices. The hardware items which are end-of-life are handed over to the hardware supply vendor under buyback. The vendor, in turn, appoints an e-waste disposal vendor registered with the Central Pollution Control Board or any State Pollution Control Board, who picks up the hardware from all the locations. A certificate is taken by the e-waste disposal vendor in the prescribed form.

We provide products and services which do not have material usage of plastics, electronics or any other hazardous and non-hazardous materials. Therefore, post consumption waste generation is not significant. As a part of IT in insurance sector, our primary concern is managing digital waste and not physical products since no physical product is generated. We focus on minimizing our environmental impact through responsible e-waste disposal; secure data handling and promoting paperless operations. We are committed to sustainable practices in our software development lifecycle.

89.08% of waste has been disposed through Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC). Food Waste and Garden Waste generated in Management Development Centre (MDC) campus is converted into compost and used in MDC garden to promote plants growth. Initiatives like implementation of paperless HRMS/ TE Modules has reduced generation of paper waste. Daily waste is handed over to Municipality.

4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes/No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.

Extended Producer Responsibility (EPR) in the traditional sense is not applicable to us, as our activities are not directly associated with the production of physical goods.

However, to ensure alignment with environmental sustainability, we collaborate with certified e-waste disposal partners to ensure that our electronic waste is managed in an environmentally friendly manner.

Leadership Indicators**1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?**

Being in the services industry, life cycle assessment as in general parlance is not applicable to life insurance contracts. However, from the angle of product development, periodic evaluation or valuation is a norm. Every plan introduced has certain projections made across various parameters like mortality, morbidity, interest rates, administrative costs, etc. During the course of time, whenever it is felt that the assumptions made therein and the actual results emanating from the field are having a variance beyond the ranges provided for in different scenarios, corrective action is initiated. It may take the form of

changes in the parameters governing the same at one end to withdrawal of the plan at the other and coming forth with a revised one, if required.

2. **If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same.**

From the nature of the business as well as it being monitored on a regular basis, no significant social or environmental concerns or risks evolve from the same.

3. **Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).**

Recycled or reused material is not applicable as life insurance being an intangible product does not partake in such processes. 89.08% of waste is disposed through MSTC.

4. **Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled and safely disposed:**

Being an intangible product, such a contingency does not arise.

	FY 2025-26			2024-25		
	Re-Used	Recycled	Safely Disposed	Re-Used	Recycled	Safely Disposed
Plastics (including packaging)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
E-waste	NA	NA	54 MT	NA	NA	13.24 MT
Hazardous waste	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Other waste	NA	NA	NA	NA	NA	NA

5. **Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.**

Being an intangible product, such a contingency does not arise.

PRINCIPLE 3: Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

Essential Indicators

1. a. **Details of measures for the well-being of employees:**

Category	% employees covered by										
	Total (A)	Health Insurance		Accident Insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care Facilities	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)	Number (D)	% (D/A)	Number (E)	% (E/A)	Number (F)	% (F/A)
Permanent employees											
Male	64161	64161	100	64161	100			64161	100	NIL	NIL
Female	20404	20404	100	20404	100	20404	100			NIL	NIL
Total	84565	84565	100	84565	100	20404	100	64161	100	NIL	NIL
Other than Permanent Employees											
Male	12	2	16.66	0	0	0	0	0	0	0	0
Female	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
Total	13	2	15.38	0	0	1	100	0	0	0	0

b. Details of measures for the well-being of workers:

Category	% workers covered by										
	Total (A)	Health Insurance		Accident Insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care Facilities	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)	Number (D)	% (D/A)	Number (E)	% (E/A)	Number (F)	% (F/A)
Permanent Workers											
Male	There is no class of employees as "Workers" in the Corporation										
Female											
Total											
Other than Permanent Workers											
Male	There is no class of employees as "Workers" in the Corporation										
Female											
Total											

c. Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format –

	FY 2025-26*	FY 2024-25
Cost incurred on well-being measures as a % of total revenue of the Corporation	i. Group Personnel Accident Benefit – 0.00074% ii. Mediclaim – 0.05169% iii. High Cost Protracted Treatment – 0.000054% iv. Preventive Health Check-up– 0.0011%	i. Group Personnel Accident Benefit – 0.001934% ii. Mediclaim – 0.0931228% iii. High Cost Protracted Treatment – 0.000156% iv. Preventive Health Check-up – 0.002841%

These figures are exclusive of 18% GST

*The cost incurred on well-being measures as a percentage of total revenue of the Corporation for the FY 2024-25 was calculated on the basis of 'New Premium Income' whereas the percentage for the FY 2025-26 is calculated on the basis of total revenue of the Corporation, hence the variation in data for FY 2025-26 as compared to FY 2024-25.

2. Details of retirement benefits, for Current Financial Year and Previous Financial Year.

Benefits	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Current Financial Year			Previous Financial Year		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
PF(*)/ Pension	65.74% (55640 out of 84565)	There is no class of employees as "Workers" in the Corporation	The Corporation has its own LIC of India Provident Fund No.1 Rules and the same is managed by the Corporation.	100%- All eligible employees are covered	There is no class of employees as "Workers" in the Corporation	The Corporation has its own LIC of India Provident Fund No.1 Rules and the same is managed by the Corporation.
NPS	34.26%		Yes	100%- All eligible employees are covered		Yes

Benefits	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Current Financial Year			Previous Financial Year		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
Gratuity	100% (84565)	There is no class of employees as "Workers" in the Corporation	The Corporation is having a Group Gratuity policy and the same is managed by P&GS Department of the Corporation.	100%	There is no class of employees as "Workers" in the Corporation	The Corporation is having a Group Gratuity policy and the same is managed by P&GS Department of the Corporation.
ESI	Not Applicable		Not Applicable	Not Applicable		Not Applicable
Others – please Specify(#)	100% (84565)		All the schemes are managed by the Corporation. Management is having Group Mediclaim Policy from New India Insurance.	100%		All the schemes are managed by the Corporation. Management is having Group Mediclaim Policy from New India Insurance.

(#)Employees / Officers retiring from the services of the Corporation are entitled to various post-retirement benefits which are inclusive of Encashment of Privilege leave, Group Insurance Scheme, Group Mediclaim Scheme, Accumulation of Group Savings Linked Insurance Scheme, Pension benefits who have opted for it.

(*)Employees who are appointed in the services of the Corporation on or after 01.04.2010 are governed by National Pension System and are not covered under LIC of India Provident Fund No. 1 Rules and vice-versa.

3. Accessibility of work places:

Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

The Corporation has framed an Equal Opportunity Policy in accordance with the provisions of the Rights of People with Disabilities Act, 2016 and Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017. All offices of the Corporation have been advised to make provisions for barrier-free accessibility and other provisions for persons with disabilities in new and existing offices.

The Corporation has modified its Central office with special facilities such as ramps, rails, uniquely designed physical barriers, etc. We have specially designed washrooms (with accessible door, grab rails, etc.) to suit the special needs of differently-abled persons. We also have ramps, grab rails, etc in many offices owned by us to suit the needs of differently abled persons. Additionally, proper accessibility of workplaces is ensured on construction sites by providing pathway approach, scaffoldings, construction lifts, etc.

Assistive Technology for Visually Handicapped employees: The screen reading software "ORCA" is made available on all the LINUX desktops in all offices of the Corporation. In order to facilitate effective use of the said software, provision is done to make available suitable audio devices / headphones.

In pursuance of the instructions from Ministry of Finance, the Corporation has appointed Chief Liaison Officers for Persons with Disabilities to look into the redressal of grievances of such employees.

806 branches made accessible for PwDs by constructing Ramps across all the Zones as per the RPwD Act. Lifts arrangement are also there in many of our offices. Those buildings which do not have the lift facility are being taken up for installation of the same. 117 toilets have been constructed for PwDs till date. Accessibility indicator is included in the ESG Framework which is approved by the Board. All our offices are being made accessible with the help of ramps.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

Yes. The Corporation has adopted an Equal Opportunity Policy in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the rules framed thereunder and provide a framework which is committed towards the empowerment of persons with disabilities. The link for Equal Opportunity Policy is as under:

<https://licindia.in/web/guest/equal-opportunity-policy>

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

Gender	Permanent Employees		Permanent Worker	
	Return to work rate	Retention rate	Return to work rate	Retention rate
Male	100%	100%	There is no class of employees as “Workers” in the Corporation	
Female	100%	100%		
Total	100%	100%		

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.

Permanent Workers	There is no class of employees as “Workers” in the Corporation
Other than permanent workers	There is no class of employees as “Workers” in the Corporation
Permanent Employees	<p>Yes.</p> <p>Employee grievance redressal portal e-Samadhan is available on the intranet website of the Corporation. Complaints are forwarded on-line to Staff Grievance Officer. There is also a provision for appeal to next higher authority. Complaint resolution time frame is 90 days.</p> <p>There are also Internal Complaints Committees at Central Office, Zonal Offices, Divisional Offices handling grievances pertaining to Sexual Harassment according to the provisions mentioned in the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.</p>
Other than Permanent Employees	Yes.

7. Membership of employees/workers in association(s)/Unions recognized by the listed entity:

Category	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Total employees / workers in respective category	No. of employees in respective category, who are part of association(s) or Union	% (B / A)	Total employees/workers in respective category	No. of employees / workers in respective category, who are part of associations or Union	% (D/C)
	(A)	(B)	% (B / A)	(C)	(D)	% (D/C)
Total Permanent Employees	84,565	Corporation does not recognize any Union. Hence the data is not maintained.	NA	91,606	Corporation does not recognize any Union. Hence the data is not maintained.	NA
- Male	64,161		NA	69,740		NA
- Female	20,404		NA	21,866		NA
Total Permanent Workers	There is no class of employees as “Workers” in the Corporation					
- Male						
- Female						

8. Details of training given to employees and workers:

Category	FY 2025-26					FY 2024-25				
	Total (A)	On Health and safety measures		On Skill upgradation		Total (D)	On Health and safety measures		On Skill upgradation	
		No. (B)	%(B/A)	No. (C)	%(C/A)		No. (E)	%(E/D)	No. (F)	%(F/D)
Employees										
Male	64,161	*	*	52,566	81.93%	69,740	**	**	46,081	66.07%
Female	20,404	*	*	16,324	80.00%	21,866	**	**	15,196	69.50%
Total	84,565	48,368	57%	68,890	81.46%	91,606	**	**	61,277	66.89%

* 'Yoga & Health' Session was incorporated in all our In-House Training Programmes. The 11th International Day of Yoga (IDY) was celebrated across India on 21st June 2025. A one-day Employee Engagement Program (EEP) was conducted by all 113 Divisional Offices. This program targeted 57% of our employees — from Record Clerks to Administrative Officers — across the country. A Session on 'Health & Wellness' was a part of the EEP Agenda, which covered 48,368 employees. The program focused on fostering a sense of belonging, promoting teamwork and strengthening the emotional and professional connection between employees and the organization.

** For FY 2024-25 the information was not included.

9. Details of performance and career development reviews of employees and worker:

Category	Details of performance and career development reviews of employees					
	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Total (A)	No.(B)	%(B/A)	Total (C)	No.(D)	%(D/C)
Employees						
Male	64,161	64,161	100	69,740	69,740	100
Female	20,404	20,404	100	21,866	21,866	100
Total	84,565	84,565	100	91,606	91,606	100

10. Health and safety management system:

a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?

Yes. The Corporation has stringent guidelines to ensure the safety of employees and its property. This includes policy for fire safety, standard operating procedures for fire safety, which covers rules pertaining to fire-fighting equipment, fire drills, formation of fire safety committees in all our offices, periodical check on electric and fire safety parameters are conducted wherever required. Also, restrictive access to core Departments has been taken up. We have SOP's on security and fire safety measures with defined roles to be followed by each employee in case of any incidence. Drills are conducted regularly so that the employees respond swiftly and efficiently and have clear understanding of the procedures. Employees are covered under Group Insurance, Group term insurance and 24 Hours Group Personal Accident Policy. In addition to the above, the employees are covered under Group Mediclaim Scheme where employees and their families are covered for hospitalization, with an option to take additional cover for themselves and their families. Preventive Health check-up scheme and scheme of ex-gratia reimbursement of Medical Expenses in case of High cost treatment are also other benefits for the employees. Additionally, all employees are covered under mediclaim facility. Fire and safety Advisory (SOP) and Security manual are also in place.

b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

Not applicable since we are a financial services entity.

c. Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N)

Not applicable

d. Do the employees/ workers of the entity have access to non-occupational medical and health care services? (Y/N)

Yes. All employees are covered under health insurance and accident policy. The Corporation has well-defined medical and healthcare policies. Group term insurance cover and Personal Accident insurance cover are applicable for all employees. Initiatives like health checkup, yoga, eye checkup, bone density, etc and talks by specialists to educate and enable healthier and happier lifestyle are held.

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incident/Number	Category	FY 2025-26	FY 2024-25
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per 1 million-person hours worked)	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
Total recordable work-related injuries	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
No. of fatalities	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy workplace.

Security Guards and Watchmen are appointed for the security of office premises and employees. Baggage scanners are installed at the entrances of various offices. CCTV cameras have been installed in offices in sensitive departments of the Corporation. Fire safety Committees are constituted in all the offices, training imparted on a regular basis and evacuation drills are conducted. Standard operating procedures for Fire Safety are laid down. Every employee of the Corporation gives their rating, in the Monthly Ambience Poll, where the ratings are based on various parameters of cleanliness in the offices. Model DO & Model BO competitions are floated to encourage cleanliness and record maintenance. Activities including regular pest control services, cleaning of office premises and surrounding areas, disposal of scrap, identification and proper use of vacant spaces, plantation of saplings, rain water harvesting, installation of ramps and railings for the differently abled, installation of solar panels, etc. are being done to ensure safe and hygienic work place. As on date most of our offices are using LED lighting.

We have sensitized all our employees about the prevalent policy against Sexual Harassment at the workplace as well as the mechanism and the process is being followed for the redressal of complaints related to Sexual Harassment at workplace.

The Office premises are kept clean. Pest Control Services, Fire Fighting Equipments, Emergency Exits, Floor Marshals in each floor, Fire Drills, Security Services are some of the additional measures taken to ensure a safe work place. Fire & Safety Advisory (SOP) and Security manual are in place.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

Category	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Health & Safety	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

14. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	Inspection of all our offices is done by our inspection teams every year
Working Conditions	

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

To address safety related incidents, installation of baggage scanner machines and fire extinguishers and training by Security Officers is provided for security guards. Fire and Safety Advisory (SOP) and Security Manual are in place to address the issues related to safety related incidents.

Leadership Indicators

1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Y/N) (B) Workers (Y/N):-

(A) Employees: Yes. The Corporation extends benefits in the form of support to families in the event of an employee's death as under:

1. Group Insurance - 2004 if opted
2. Group Term Insurance which is paid to nominee / legal heirs. This is especially provided to protect the loss of commutation of pension, had the employee continued in the services of the Corporation till the date of his superannuation.
3. Risk and Savings Portion of Group Savings Linked Insurance
4. 24 hours Group Personal Accident cover in case death of the employee occurs due to accident.

Apart from this the following terminal dues are settled to the family of the deceased employee:

1. Gratuity is paid even if the employee had not completed five years of continuous service with the Corporation. In addition, gratuity is calculated as per LIC of India (Staff) Rules, 1960 and also as per Gratuity Act, 1972 and the higher is paid to the family members of the deceased employee.
2. Additional Gratuity is also paid if applicable.
3. Family Pension as applicable
4. Employees contribution towards Provident Fund
5. Corporation Contribution towards Provident Fund (for PF Optees)
6. Lump sum in lieu of PL Encashment.

An opportunity of employment is also extended to the spouse or age eligible child of the deceased employee on compassionate grounds, wherever applicable.

(B) Workers: There is no class of Employees termed as 'workers' in the Corporation.

2. Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

The Corporation ensures that taxes as applicable to the transactions within the remit of the Corporation are deducted and deposited in accordance with extant regulations. This activity is reviewed as part of the internal and statutory audit. The Corporation expects its value chain partners to uphold business responsibility principles and values of transparency and accountability. This is also part of Service Level agreement executed with Channel Partners.

GST is paid to Value Chain Partner/s and it is being ensured that the same has been remitted to GST Authorities. Statutory deductions are done from the Value Chain Partner's bill and the same has been deposited in the respective department.

Statutory registration certificates are verified at the time of onboarding. Clauses are included in the agreement requiring the vendors to comply with all applicable labour and tax laws. Provision for penalty, clauses included like withholding of payment and termination in case of non compliance, Periodic check are made for compliance. Copies of challan, returns, wage registers, PF/ESIC contribution proofs, tax filing including GST are obtained from vendors. Payments are released after receipt of statutory proof of statutory compliance documents. Invoices are reconciled with GST Portal data. Maintenance of proper records of all verification, correspondences for audit purposes is done.

3. **Provide the number of employees / workers having suffered high consequence work-related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:**

	Total no. of affected employees/ workers		No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	FY 2025-2026	FY 2024-2025	FY 2025-2026	FY 2024-2025
Employees	NIL	NIL	NIL	NIL
Workers	NA	NA	NA	NA

Note: There is no class of employees as “Workers” in the Corporation

4. **Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/No)**

Yes. Continuous learning opportunities are offered through both In-House Training Centres and External Training Institutes, enabling employees to develop their managerial, functional and behavioral skills throughout their careers within the Corporation. These platforms not only enhance existing competencies but also foster a culture of growth and development within the organization.

The Corporation has developed a self learning and skill enhancement intranet portal, “Gyanpeeth” which ensures uninterrupted training on various functional aspects and rules of the Corporation.

Special training programs are also conducted for employees approaching retirement to assist them in effectively managing their finances, health and overall well-being post-retirement.

5. **Details on assessment of value chain partners:**

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Health and safety practices	Conditions are built in contract/agreement to conform to directives issued by Government /other statutory agencies and are being ensured. Annual certification is also obtained from such value chain partners.
Working Conditions	It is ensured that workmen compensation policy is taken by the value chain partners. Also provision for safety helmet, Body Harness, Safety Shoes & other safety norms is ensured, where applicable. Maintaining site hygienic conditions by providing proper washroom, potable water, etc., is enabled.

6. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks/concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.**

Not applicable

PRINCIPLE 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

Life Insurance is the primary business of the Corporation. However financial planning solutions which are provided to individuals, provides the financial protection in case of exigencies like critical illnesses as well as Death. Along with the life cover, different insurance products cater to different needs of family and help individuals to secure family's financial future and achieve the long term financial goals.

Customers include individuals who are self-employed as well as salaried individuals and their dependents, key management persons, etc. Our life insurance products offers a protection to the family against untimely death of the bread winner, a protection cover for the loan taken in case of death, accident, critical illness, etc. It is also a tool for savings, investment and long term planning for child's education, marriage, untimely loss of key person in case of business organisations, etc.

Policyholders are one of our stakeholders and they are identified on the basis of their policy nos. They are contacted as and when required like premium/ loan/ loan interest payment/s due, SB/ Maturity/ Annuity payments falls due, etc. As we are dealing with claims, we identify the stakeholders whose policies are in paid up condition and maturing in next 6 months and stakeholders whose policies are in force and maturing in next 3 months. There are system generated outputs which the user department runs every month to send the intimation, reminders, etc to the concerned policy holders.

We also offer group insurance products to the organisations to cover the needs of managing gratuity, superannuation in addition to the life cover for their employees.

Based on the nature of our business of life insurance, our risks and opportunities revolve around Human Capital, responsible investing, Data Privacy & Security, access to Finance and Emerging Risks and Governance. Accordingly, our key stakeholders can be identified as Internal Stakeholders and External stakeholders. Internal stakeholders are our employees and agents whereas external stakeholders are those who contribute to our business directly or indirectly. Some of our key external stakeholders are: Investors and Shareholders, Customers (Policyholders), Government and Regulatory Bodies, Business Partners (CA/Broker/IMF/CSC) and Distribution Channels.

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group:

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalised Group	Channels of Communication (E mail, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website)	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Others - Please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement.
Investor and Shareholders/ Members	No	As per need: Emails, Annual General Meeting, Quarterly Results, Filings at Stock Exchanges, Press Releases, Media Interactions, Interviews for Newspapers	Quarterly and half yearly Results and Annual General Meeting. Filings of Corporate Announcements with the Stock Exchanges.	Providing the update on the Corporation's strategy, Redressal of grievances through various regulatory Mechanisms.
Employees	No	Direct contact, e-mail, Employee website, SMS, calls, Notice Board, VC Meetings, Conference	Regularly	Information sharing, and addressing queries. Regular engagement on work progress in the department, review of marketing activities and to understand concern and solutions thereof

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalised Group	Channels of Communication (E mail, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website)	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Others - Please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement.
Customers	No	Intimation letters, SMS, MY LIC app, WhatsApp Message and Emails in case of SB and maturity cases. Advertisement for Outstanding Claims and Servicing matters. LIC website Our field force like agents and development officers followup with policyholders for submission of requirements at regular intervals	Frequent or as and when required	To acquire new customers and provide services to existing ones; To intimate them about claim due and requirements to be submitted to enable processing of claims, Our concern is non availability of latest address and mobile numbers. To inform on New Online Plans introduced, review of marketing activities and to understand concern and solutions thereof Information when the payments are due to the policyholders as well as due from the policyholders and updates regarding the services requested by them
Business Partners (CA/ Broker/ IMF/ CSC)	No	Email, SMS, meetings and through Website, calls	Frequent or as and when required	Service existing business and scope for further expansion
Government & Regulatory Bodies	No	Email, Personal Meetings, Calls, Video Calls	As and when required	For Regulatory Compliance, inspections and in Grievance matters
Distribution Channels: Premium Points, Agents, CLIAS, COs, DSAs, Supervised Agents under CLIAS/ Cos	No	Multiple Channel of communication - Physical and Digital	Frequent or as and when required	To provide the services to existing policyholders and procurement of new business
Community	No	Newspaper, Advertisements, etc	On regular basis	Insurance awareness

Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

The Board and its Committees receive periodic updates on diverse topics, including stakeholder feedback. For engaging with government and regulatory bodies, meetings, conferences, forums and emails are utilized. Corporation responds to consultation papers from regulatory bodies within specified timelines. The Board has different Committees and each committee has a defined role and charter. We engage with customers regarding complaints, new initiatives, services and products through surveys, SMS, call centers, advertisements and social media. Customer analytics from surveys and feedback are used to derive insights, to enhance service offerings. Corporation values its employees and actively seeks their input on addressing grievances, concerns and ideas for reducing environmental impact and other matters.

Team of Investor Relations of the Corporation engages with the investors and market analysts. Key indicators of Analysts' Reports and feedback from Investors meet are placed to the Board of the Corporation. Grievances and queries raised by the

Shareholders/ Members and status of resolution are placed before the Stakeholders' Relationship Committee of the Board as well as placed before the Board of the Corporation. ESG (Environment, Social & Governance) Committee of the Board reviews the ESG activities of the Corporation. Queries, if any, raised by the shareholders on economic, environmental and social topics are placed for discussion. Policyholder Protection, Grievance Redressal and Claims Monitoring Committee of the Board monitor the activities related to interest of the policyholders.

2. Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.

Yes. Grievances and queries raised by the Shareholders and status of resolution are placed before the Stakeholders' Relationship Committee of the Board which meets as and when required or at least twice a year. It is then placed before the Board of the Corporation. Queries, if any, raised on economic, environmental and social topics are placed for discussion. The Corporation has for long understood the significance and utility of feedback from customers who form our most significant stakeholder. Feedback is sought from all employees in the form of contribution to idea box for which certificates and awards are given for the best ideas selected and implemented. This approach bring to our attention matters dealing with the minutiae at the grassroot level to macro issues at the higher levels resulting in informed changes in product and servicing aspects.

3. Provide details of instances of engagement with, and actions taken, to address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.

To address the concerns of vulnerable/marginalized stakeholders, the Corporation has implemented several key initiatives aimed at improving access and financial inclusion:

Customized Product Offerings: Insurance products for low-income individuals, rural populations and other under-served groups have been developed. These products are designed to offer affordable premiums with simplified features to ensure ease of understanding and access. Specially designed plans are available for our micro-insurance policyholders. Convenient modes of payment, including weekly mode of payment is available. Micro-insurance policyholders are serviced through NGOs and tied-agents.

Technology-Driven Outreach: Utilizing mobile and digital platforms expands the reach to rural and remote areas where traditional banking infrastructure is limited. Corporation's mobile applications offer easy access to information and policy services, ensuring stakeholders can manage their policies remotely.

Collaboration with NGOs: We partner with non-governmental organisations (NGOs) that work directly with marginalized groups. This helps us reach vulnerable/ marginalized stakeholder through trusted local networks, ensuring better engagement and trust-building.

Grievance Redressal: Corporation has established dedicated help lines and grievance redressal mechanisms for policyholders including marginalized stakeholder to voice concerns.

Training for Channel Partners: Corporation's Marketing Field force offers training to Channel Partners on how to engage with and serve vulnerable customers, ensuring that the front-line staff is equipped to address the unique challenges these stakeholders may face.

GJF: The Foundation is committed to being transparent and honest, consistently engaging for the upliftment of the economically weaker sections. The criteria for selection of projects and scholarship is transparent. LIC GJF supports projects for the economically weaker section of the society, aligned with its objectives – relief of poverty, education, medical relief and any other object of general public utility across the country. Mode of engagement with social and economically weaker sections is through service representatives at LIC Divisional offices located near to the project location. Based on these engagements, focused actions such as scholarship disbursements, skill development support and welfare initiatives were undertaken to empower underserved communities and create sustainable opportunities for growth. These efforts reflect the Foundation's enduring commitment to inclusion, compassion and social transformation.

PRINCIPLE 5: Businesses should respect and promote human rights**Essential Indicators****1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity:**

Category	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Total (A)	No. of employees/workers covered (B)	% (B / A)	Total (C)	No. of employees/workers covered (D)	% (D / C)
Employees						
Permanent	84,565	31,597	37.36%	91,606	33,371	36.43%
Other than permanent	13	NA	NA	14	0	0
Total Employees	84,578	31,597	37.36%	91,620	33,371	36.42%
Workers						
Permanent	There is no class of employees as "Workers" in the Corporation					
Other than permanent						
Total Workers						

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following Format:

Category	FY 2025-26					FY 2024-25				
	Total (A)	Equal to minimum wage		More than Minimum wage		Total (D)	Equal to Minimum wage		More than Minimum wage	
		No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)		No. (E)	% (E / D)	No. (F)	% (F / D)
Employees										
Permanent	84,565	NIL	NIL	84,565	100	91,606	NIL	NIL	91,606	100
Male	64,161	NIL	NIL	64,161	100	69,740	NIL	NIL	69,740	100
Female	20,404	NIL	NIL	20,404	100	21,866	NIL	NIL	21,866	100
Other than Permanent	13	NIL	NIL	13	100	14	NIL	NIL	14	100
Male	12	NIL	NIL	12	100	13	NIL	NIL	13	100
Female	1	NIL	NIL	1	100	1	NIL	NIL	1	100
Workers										
Permanent	There is no class of employees as "Workers" in the Corporation									
Male										
Female										
Other than Permanent										
Male										
Female										

3. Details of remuneration/salary/wages:

a. Median remuneration / wages:

FY 2025-26	Male		Female	
	Number	Median remuneration / salary / wages of respective category	Number	Median remuneration / salary / wages of respective category
Board of Directors (BoD)*	4	60,56,100.58	0	NA
Key Managerial Personnel (KMP) (excluding BoD)	6	58,27,293.99	0	NA
Employees other than BoD and KMP	64,152	20,85,996.18	20,404	23,23,205.77

*Details of remuneration submitted include that of only CEO&MD and Managing Directors of the Corporation. Further, it is submitted that pursuant to the Board approved policy on Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity ('Directors' Policy') the independent directors of the Corporation are eligible to receive sitting fees whereas Government Nominee Director is not eligible to receive any remuneration/sitting fees.

b. Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity:

	FY 2025-26	FY 2024-25
Gross wages paid to females as % of total wages	24.77%	24.48%

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)

Yes. Executive Director (Personnel) is responsible for the human resources administration and management shall oversee and address any issue arising from any human rights impact related to employees.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

The Corporation has developed an internal mechanism system for redressal of grievance. For this purpose a portal on the intranet site called e-Samadhan where grievances can be registered by any employee which will be forwarded online to the Staff Grievance Officer. There is also a provision for appeal to the next higher authority through the portal.

In accordance with The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention Prohibition and Redressal) Act, 2013, the department has initiated various steps to improve the status of women and worked for their economic empowerment. The female employees of the Corporation are treated at par with the male employees. A Committee known as Internal Complaint Committee has been constituted in all the offices of the Corporation.

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 2025-2026			FY 2024-2025		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of the year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of the year	Remarks
Sexual Harassment	16	5	As on the date of this report all 5 Complaints stand resolved	9	2	Closed in Financial Year 2025-2026
Discrimination at workplace	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Child Labour	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

	FY 2025-2026			FY 2024-2025		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of the year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of the year	Remarks
Forced Labour/ Involuntary Labour	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Wages / Salary	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Other human rights related issues	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Note: There is no class of employees as “Workers” in the Corporation

7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:

	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	16	9
Complaints on POSH as a % of female employees / workers	0.08%	0.041%
Complaints on POSH upheld	7	2

8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

The Corporation has laid down a detailed Whistle-blower process, including mechanism to prevent adverse consequences to the complainant. The aim of the Whistle-blower Policy is to Ensure that the ‘Whistle-blower’ and / or the person processing ‘Protected Disclosures’ is not victimized for doing so. The whistle-blower is entitled to the following protection:

- The Corporation shall ensure that no whistle blower who has made a disclosure under this Policy is victimized by initiation of any proceedings or otherwise, merely on the ground that such complainant had made a disclosure or rendered assistance in investigation under this Policy.
- Wherever the Whistleblower has alleged victimization/ harassment, the Vigilance Officer ensures that if the identity becomes known eventually he/she should not be harassed/ victimized by way of frequent transfers, etc.
- In case a Whistleblower seeks protection and reports that his life is in danger, the Vigilance Officer will examine the matter and send his recommendation to the CEO and Managing Director to take up the matter with the Nodal Officers of respective States/UTs appointed by the Ministry of Home Affairs/State Governments for the purpose of providing security cover to the Whistleblowers.
- The identity of the Whistleblower shall be kept confidential unless warranted for evidence in the Court/Disciplinary Proceedings.

Further, in accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Corporation has initiated various steps for preventing adverse consequences to the complainant in harassment cases. During the pendency of the inquiry, the Corporation can transfer the aggrieved woman or the respondent to any other workplace or grant leave to the aggrieved woman up to a period of three months or any other relief such as during the pendency of the inquiry, the respondent may be restrained from reporting on the work performance of the aggrieved woman or writing her confidential report.

9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)

Yes, wherever applicable.

10. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	NIL
Forced/involuntary labour	NIL
Sexual harassment	NIL
Discrimination at workplace	NIL
Wages	NIL
Others–please specify	NIL

The Corporation is in compliance with all applicable laws on the subjects mentioned in the table.

11. Details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / Concerns arising from the assessments at Question 10 above.

Nil, not applicable

Leadership Indicators

1. Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/complaints.

The Corporation is of the belief that it has upheld the basic principles of human rights in all its dealings. This is in alignment with its Human Rights Statement. The Corporation regularly sensitizes its employees through various training programmes. Employees are encouraged to raise any grievance they may have regarding any breach/violation in any policy or process, or report any act which is in contravention of the rules and regulations governed by the Corporation including the Prevention of Sexual Harassment at the workplace policy, Anti bribery and Anti-Corruption Policy, Anti Money Laundering Policy, Whistle Blower Policy, Anti-Fraud Policy, Information and Cyber Security Policy or any other policy governing employee conduct at the workplace that may be defined from time to time or any other statutory or regulatory laws as may be in force.

2. Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.

Internal audit is conducted for the governance process of the Corporation.

3. Is the premise/office of the entity accessible to differently able visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

The Corporation has framed an Equal Opportunity Policy in accordance with the provisions of the Rights of People with Disabilities Act, 2016 and Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017. It has been advised to all the offices of the Corporation that provisions shall be made for barrier-free accessibility and other provisions for persons with disabilities. The Corporate Office at Yogakshema building is accessible to differently abled persons.

The Corporation has modified its Central office with special facilities such as ramps, rails, uniquely designed physical barriers, etc. We have specially designed washrooms (with accessible door, grab rails etc.) to suit the special needs of differently-abled persons. We also have ramps, grab rails, etc in many offices owned by us to suit the needs of differently abled persons. Additionally, proper accessibility of workplaces is ensured on construction sites by providing pathway approach, scaffoldings, construction lifts, etc.

4. Details on assessment of value chain partners:

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Sexual Harassment	Nil
Discrimination at work place	Nil
Child labour	Nil
Forced labour/Involuntary labour	Nil
Wages	Nil
Others- please specify	Nil

Assessment of value chain partner/s for execution of the work includes, *inter alia*, a pre-qualification criteria in the tender document for selection of eligible value chain partner and thereafter selection of the eligible contractor / construction Associates / value chain partner is done. After completion of the work, we collect a certificate of compliance from the value chain partner. Also a confidential report is being given by us wherein we assess the Value Chain Partner based on their performance.

5. Details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.

We incorporate the relevant matrix in our new and existing contracts with our value-chain partners. It is ensured that workmen compensation policy taken by the value chain partners. Also it is ensured for provision of safety helmet, Body Harness, Safety Shoes & other safety norms etc. Maintaining Site Hygenic condition by providing proper washroom, potable water, etc., is done. There is also provision in the contract documents to follow safety protocols.

PRINCIPLE 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity:

Parameter	FY 2025-26	FY 2024-25
From Renewable Sources		
Total Electricity Consumption (A)	38,884 GJ	
Total Fuel Consumption (B)		
Energy Consumption through other Sources (C) Solar		18307 GJ
Total Energy Consumed from Renewable Sources (A+B+C)	38,884 GJ	18307 GJ
From Non-Renewable Sources		
Total Electricity Consumption (D)	398032 GJ	422858 GJ
Total Fuel Consumption (E)	501242GJ	390283 GJ
Energy Consumption through other Sources (F)		
Total Energy Consumed from Non-Renewable Sources (D+E+F)	899274 GJ	813141 GJ
Total Energy Consumed (A+B+C+D+E+F)	938158 GJ	831448 GJ
Energy Intensity per Rupee of Turnover (Total Energy Consumed/ Revenue from Operations) (GJ/INR crores)	1.75	1.70
Energy Intensity per Rupee of Turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Energy Consumed/ Revenue from Operations adjusted for PPP)	3.5551 KJ/USD PPP	3.5139 KJ/USD PPP
Energy Intensity in terms of physical output		
Energy Intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	11.09GJ /per employee	9.07 GJ /per employee

*PPP conversion rate is taken as 20.34

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, reasonable assurance has been carried out by M/s Rama K Gupta & Co. for the FY 2025-26.

2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide remedial action taken, if any.

No, we do not have any such sites or facilities

3. Details of disclosures related to water:

The organisation's water usage is restricted for human consumption only. Efforts have made to ensure that water is utilized judiciously. For e.g., at our Management Development Centre (MDC), Borivali, a rain water harvesting unit for collecting the rain water is installed. This unit is connected to the nearby bore well due to which the bore-well is recharged and quality of bore well water has improved significantly.

Details of water-usage are as follows:

Parameter	FY 2025-26	FY 2024-25
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
(i) Surface water	4405.61	19571
(ii) Ground water	45154.66	680535
(iii) Third party water	55732.66	559024
(iv) Sea Water / Desalinated Water	0	0
(v) Others	7961.81	8311
Total volume of water withdrawal (in Kilolitres) (i+ii+iii+iv+v)	113254.74	1267441
Total volume of water Consumption (in Kilolitres)	113254.74	1267441
Water Intensity per Rupee of Turnover (Total Water Consumption/ Revenue from Operations) (Kilo litres/INR Crores)	0.211	2.59
Water Intensity per Rupee of Turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Water Consumption/Revenue from Operations adjusted for PPP)	0.00043 L/USD PPP	0.0054 L/USD PPP
Water Intensity in terms of physical output		
Water Intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	1.34 kL /per employee	13.83 kL /per employee

*PPP conversion rate is taken as 20.34

Note: Indicate if any independent assessment/evaluation/assurance has been carried out by an external agency?

Yes, reasonable assurance has been carried out by M/s Rama K Gupta & Co. for the FY 2025-26.

4. Provide the following details related to water discharged:

Parameter	FY 2025-26	FY 2024-25
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) To Surface water	-	-
- No treatment	-	-
- With Treatment – Please specify level of Treatment	-	-
(ii) To Ground Water	-	-
- No treatment	-	-
- With treatment – please specify level of treatment	-	-
(iii) To Sea Water	-	-
- No treatment	-	-
- With Treatment – Please specify level of Treatment	-	-
(iv) Sent to Third Parties	-	-
- No treatment	-	-
- With Treatment – Please specify level of Treatment	-	-
(v) Others	-	-
- No treatment	-	-
- With treatment – please specify level of treatment	-	-
Total water discharged (in Kilolitres) (i+ii+iii+iv+v)	-	-

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency?

No

5. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

No

6. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity

Not Applicable

Parameter	Please specify Unit	FY 2025-26	FY 2024-25
NOx		Not Applicable	
Sox			
Particulate Matter (PM)			
Persistent Organic Pollutants (POP)			
Volatile Organic Compounds (VOC)			
Hazardous Air Pollutants (HAP)			
Others – Please specify			

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency?

No

7. Details of green house gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity:

Parameter	Unit	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Scope 1 Emissions (Breakup of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	33,065.26	27,014
Total Scope 2 Emissions (Breakup of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	78,500.74	84,102
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from Operations) (MT/INR Crores)		0.2079	0.23
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from Operations adjusted for PPP)		0.0004227 KG/USD	0.0004696 KG/USD
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output			
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		1.32 mT/Employee	1.21 mT/Employee

*PPP conversion rate is taken as 20.34

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, reasonable assurance has been carried out by M/s Rama K Gupta & Co. for the FY 2025-26.

8. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details.

Employees are encouraged to purchase EV Vehicles. Under Plant-a-Life initiative 1147574 saplings were planted. We have implemented IPM+, a power saving solution for desktops. IPM+ has helped the Corporation successfully achieve energy savings of approximately 3.86 GWh during the year, which corresponds to a reduction of 956 metric tonnes of CO2 emissions/savings of 53975 cubic metre of water. Construction of buildings conforming to green building norms with an aim to obtain at least a 3 star rating is the goal. Upto March 2026, we have installed 10499 Kwp Solar PV resulting in carbon reduction of 40097 tons.

9. Details related to waste management by the entity:

Parameter	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Waste Generated (in Metric Tonnes)		
Plastic Waste (A)	49.63	920
e-Waste (B)	87	940
Bio-Medical Waste (C)		
Construction and Demolition Waste (D)		
Battery Waste (E)		
Radioactive Waste (F)		
Other Hazardous Waste. Please specify, if any. (G)		
Other Non-Hazardous Waste generated (H). Please specify, if any. (Break-up by composition, by materials relevant to the sector) – Paper, Scrap Metal, etc	1332	512
Total (A + B + C + D + E + F + G + H)	1468.63	2372
Waste Intensity per Rupee of Turnover (Total Waste Generated/Revenue from Operations) (MT/INR Crores)	0.0027362	0.005
Waste Intensity per Rupee of Turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Waste Generated/Revenue from Operations adjusted for PPP)	0.000005565 kg/USD PPP	0.0000100 kg/USD PPP
Waste Intensity in terms of physical output		
Waste intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	0.02 mT /per employee	0.03 mT /per employee
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in Metric Tonnes)		
Category of waste	-	-
(i) Recycled	-	-
(ii) Re-used	-	-
(iii) Other recovery operations	-	-
Total	-	-
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in Metric Tonnes)		
Category of waste	-	-
(i) Incineration	-	-
(ii) Land-filling	-	-
(iii) Other disposal Operations	-	-
Total	-	-

Note: 89.08% of waste has been disposed through Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC). Food Waste and Garden Waste generated in Management Development Centre (MDC) campus is converted into compost and used in MDC garden to promote plants growth. Initiatives like implementation of paperless HRMS/ TE Modules has reduced generation of paper waste. Daily waste is handed over to Municipality.

*PPP conversion rate is taken as 20.34

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, reasonable assurance has been carried out by M/s Rama K Gupta & Co. for the FY 2025-26.

10. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

We are committed to adopting sustainable practices in waste management. While our operations primarily involve software development, technology infrastructure and digital services, we recognize the importance of responsible waste handling.

The hardware items which are end-of-life are handed over to the hardware supply vendor under buyback agreement. The vendor, in turn, appoints an e-waste disposal vendor registered with the Central Pollution Control Board or any State Pollution Control Board, who picks up the hardware from all locations. A certificate is taken from the e-waste disposal vendor in the prescribed form.

Although our operations focus on software development, technology infrastructure, and digital services, we recognize the critical importance of responsible waste handling across all areas. We have implemented alternate measures for digitising and automating various processes to reduce the need for paper. Minimising the usage of paper across offices is an ongoing activity. Soft copies of forms, certificates, etc., are being issued. Pension documents have been scanned for better servicing and for reducing time lag. Paper stationery is being used judiciously by all employees.

We collaborate with certified and audited disposal partners who adhere to strict environmental standards to ensure the proper recycling, data sanitization, and environmentally sound disposal of all electronic waste, minimizing our environmental impact and maximizing resource recovery. Our commitment extends to ongoing evaluation and improvement of these processes.

89.08% of waste has been disposed through Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC). Food Waste and Garden Waste generated in Management Development Centre (MDC) campus is converted into compost and used in MDC garden to promote plants growth. Initiatives like implementation of paperless HRMS/ TE Modules has reduced generation of paper waste. Daily waste is handed over to municipalities/local bodies. Being a service sector we do not generate hazardous or toxic chemicals from our products or processes. We are developing an SOP for Waste Management.

Our waste management practices include:

- **Energy-Efficient Infrastructure:** We prioritize the use of energy-efficient infrastructure to minimize resource consumption.
- **Electronic Waste Management:** We have implemented a comprehensive e-waste management program, collaborating with certified disposal partners to ensure proper recycling and disposal of electronic waste.
- **Paperless Initiatives:** We encourage paperless practices and have taken up new initiatives to reduce reliance on physical material in our day-to-day operations.

11. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, bio-diversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details:

None of our offices are located in ecologically sensitive areas

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

Not applicable

13. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules there under (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances:

Sr. No.	Specify the law / regulation/ guidelines which was not complied with	Provide details of non-compliance	Any fines / penalties / action taken by regulatory agencies such as pollution control Boards or by courts	Corrective action taken, if any
Based on the nature of business the Corporation complies with applicable environmental norms.				

For building construction projects requiring environmental clearance, necessary clearance is obtained from the concerned statutory environmental body for compliance as per norms.

Leadership Indicators

1. **Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water-stress (in kilo-litres):**

NIL

For each facility/plant located in areas of water-stress, provide the following information:

- Name of the area - **Not applicable**
- Nature of operations - **Not applicable**
- Water withdrawal, consumption and discharge in the following format: **Not applicable**

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Not Applicable

2. **Details of total Scope 3 emissions & its intensity:**

Parameter	Unit	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Scope 3 Emissions (Breakup of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	2983 TCo ₂ e (Employee Commute Cat 7) 2105.86 TCo ₂ e (Business Tour Cat 6)	NA
Total Scope 3 emission intensity per rupee of turnover		NA	NA
Total Scope 3 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		NA	NA

For Scope 3 emissions, employee commute and business tours have only been taken in this phase.

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, not applicable.

3. **With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 11 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on bio-diversity in such areas along-with prevention and remediation activities.**

Not applicable since none of our offices are located in ecologically sensitive areas

4. **If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge/waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives:**

Specific initiatives or innovative technology or solutions to improve resource efficiency include, inter alia, use of water efficient

fixtures, LED lights, occupancy sensors, rain water harvesting, energy efficient equipments like VRF type AC machines and 5 star AC machines, Energy level II Transformer, etc as well as use of environment friendly refrigerant gas in the AC machines and Roof Top Solar for generating units of Electrical Energy. We have obtained Green Building certification for 26 existing buildings and are planning to get the same for 32 buildings in FY 2025-26

5. Does the entity have a business continuity and disaster management plan?

Yes, the Corporation has a Board-approved Business Continuity Management (BCM) Plan designed to ensure continuity of critical operations in the event of disruptions such as system failures, natural disasters, or cyber incidents. The plan aims to minimize downtime, safeguard critical functions, reduce financial losses and enable swift recovery. The BCM Plan provides detailed procedures for the continuity or rapid restoration of critical business functions and **the Corporation is certified under ISO 22301 for its Business Continuity Management System**, reflecting its strong commitment to operational preparedness. In addition, a separate Board-approved IT Disaster Recovery (ITDR) Policy defines guidelines for the protection, backup and recovery of IT systems, applications and data, aligned with business requirements. Regular business continuity and disaster recovery drills are conducted for critical processes, enhancing the Corporation's resilience against business interruption risks.

6. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard?

There has been no adverse impact on environment as nature of business is life insurance.

No such study is done. However, for applicable engineering works undertaken for the Corporation, we are taking adequate mitigation measures not to deteriorate the environment by implementing the following measures viz: using RMC (Ready Mix Concrete) for concreting, using fly ash bricks, minimizing the dust at site, doing rain water harvesting, using a Sewage Treatment Plant (STP) and using building materials which give low carbon footprint, etc. Housekeeping Vendor/s also do not use any harmful chemicals for their operations.

7. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.

We have not assessed any value chain partner this year.

8. How many Green Credits have been generated or procured?

- By the listed entity
- By the top ten (in terms of value of purchase & Sales respectively) Value Chain Partners.

Nil

PRINCIPLE 7: Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations.

The Corporation has Affiliations with more than 15 trade and industry chambers/ associations.

b. List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.

Sr. No.	Name of the trade and industry chambers / associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
1	Indian Society for Training & Development (ISTD)	National
2	National HRD Network (NHRD)	National
3	Associated Chambers of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM)	National
4	Administrative Staff College of India, Hyderabad (ASCI)	National
5	All India Management Association (AIMA)	National
6	Insurance Institute of India (III)	National

Sr. No.	Name of the trade and industry chambers / associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
7	Confederation of India Industry (CII)	National
8	Bombay Chamber of Commerce and Industry (BCCI)	National
9	Management Development Institute Society, Gurgaon	National
10	Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE)	National

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

No adverse orders passed on us by any Regulatory Authority related to anti-competitive conduct.

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

LIC has positioned itself as the insurer of choice and continues to sustain its leadership position after more than two decades of liberalization with dominant business mix sourced primarily through the agency force. Further, LIC has capitalized on heightened awareness and is pursuing digital engagement and delivery of services with migration of the customers from physical to the digital, i.e., 'phygital' mode.

We offer inputs/ views/ suggestions on various Exposure Drafts, proposed amendments to Rules, etc., to the Regulator through Life Insurance Council considering the best interests of the Policyholder and the Insurance Industry at large.

We conduct Insurance Awareness Campaigns (IAC) every year pan India. Under IAC we have published advertorials in the magazines highlighting our achievements, our product portfolio and various services tendered to the policyholders. We enhance awareness about our products through Print Advertisements in Newspapers and Magazines at the national and regional level on a pan India basis with TV commercials urging people to purchase insurance with their first salary along with animated video(s), highlighting the need of insurance on national and regional news/ music and general entertainment channels across India. Creative(s) are prepared for various operational matters such as, updating KYC and submission of NEFT details, revival of the policies, new plans/products. Awareness is created through the social media, by posting relevant messages, about insurance.

We are also a part of various committees/working groups formed by the Life Insurance Council for vetting of new initiatives.

PRINCIPLE 8: Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.

The Foundation remains deeply committed to ensuring that every initiative creates meaningful and lasting impact in the lives of beneficiaries. While no external agency has been engaged for conducting impact studies, the Foundation undertakes a comprehensive internal impact assessment every year to evaluate the effectiveness and reach of its programs. The Zonal Inspection Teams regularly monitors and reviews GJF-supported projects to ensure that the funds are utilized responsibly and strictly for the intended purpose. These inspections also help assess how effectively the projects are supporting beneficiaries from economically weaker sections of society.

The Divisions are in direct contact with the beneficiaries, enabling continuous feedback and a better understanding of on-ground outcomes. For patient treatment support initiatives, detailed treatment and cost summary reports are obtained from the respective hospitals to ensure transparency and accountability.

In addition, testimonials from GJF scholars and beneficiaries serve as inspiring reflections of the positive transformation brought about through the Foundation's efforts. Through these consistent monitoring and evaluation practices, the Foundation strives to uphold trust, maximize social impact and continue making meaningful difference in communities. Testimonials received from GJF scholars stand as powerful reminders of the transformative impact of the Foundation's initiatives. Their success

stories, experiences and words of gratitude inspire the Foundation to continue empowering deserving individuals and creating opportunities for a brighter future.

2. Information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity:

Nil

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

The Foundation is committed to maintaining a transparent, fair and inclusive system for the sanctioning of projects and selection of scholars. A robust three-tier mechanism involving the Divisional, Zonal, and Central Offices ensures that every proposal is carefully evaluated and that the benefits of the Foundation's initiatives reach economically weaker sections across the country in an equitable manner.

Transparency remains at the heart of all charitable activities undertaken by the Foundation. Detailed information regarding the Foundation's pan-India initiatives is made accessible at the Foundation's page available on the website of the Corporation at www.licindia.in, reinforcing openness and accountability in all operations.

The Foundation also believes in maintaining strong communication channels with beneficiaries and stakeholders. Any grievance or concern received is addressed promptly and sensitively through the coordinated efforts of the Divisional, Zonal, and Central Office departments. This responsive approach helps build trust, strengthen community relationships, and ensure that the Foundation's services continue to make a positive and meaningful impact on society.

The Foundation is guided by a strong commitment to transparency, accountability, and community welfare. Any grievance received is promptly attended to and resolved through the coordinated efforts of the Divisional, Zonal and Central Office departments. This structured approach ensures that every concern is handled with care, fairness, and sensitivity. By maintaining open channels of communication and a people-centric approach, the Foundation continues to strengthen trust and foster meaningful relationships with the communities it serves.

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:

Not applicable, since the Corporation is in Insurance business.

5. Job creation in smaller towns – Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost

Location	FY 2025-26	FY 2024-25
Rural	0.59%	0.69%
Semi-Urban	27.43%	31.21%
Urban	33.66%	36.71%
Metropolitan	38.32%	31.38%

In addition to the above, by recruiting and nurturing a wide spread agency ecosystem we have created employment opportunities in rural and semi urban areas in addition to other areas. These agency opportunities provide self employment, enhance financial inclusion and contribute to the socio economic development of local communities.

Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):

No negative social impact was identified in the Social Impact Assessment

2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:

The Foundation remains deeply committed to inclusive and sustainable community development across the country, with a special focus on the Aspirational Districts identified by the Government of India. Demonstrating its dedication towards

bridging developmental gaps and uplifting underserved communities, the Foundation has implemented 55 impactful projects across 31 Aspirational Districts with a total contribution of ₹ 13.88 Crores. These initiatives have touched thousands of lives by strengthening essential infrastructure and creating opportunities for growth and empowerment. The projects undertaken include construction of school buildings, skill development centres, multipurpose halls, rooms and toilet blocks for tribal girls, pathology units, day care centres, and women empowerment initiatives.

In addition, the Foundation has supported critical healthcare and community welfare services through ambulances, mobile medical vans for patient transportation, vehicles for transportation of school children and food distribution vehicles to ensure assistance reaches those in need. Through these meaningful interventions, the Foundation continues to foster education, healthcare, women empowerment, and community well-being, contributing towards the vision of holistic and equitable development in some of the nation's most underserved regions.

3. (a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups? (Yes/No)

No, we do not have a preferential procurement policy. However, we follow the government guidelines regarding procurement of materials and services from suppliers comprising marginalized or vulnerable groups.

(b) From which marginalized /vulnerable groups do you procure?

Preference given to groups registered under Micro and Small enterprises (MSE) on production of certificates and to SC/ST Vendors registered under MSE. In 2025-26 the percentage procured was 2.73% from SC/ST under MSE. Our procurement practices prioritize equal opportunity for all vendors. Additionally, we adhere to government guidelines regarding preferential procurement from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and local suppliers, thereby supporting local economies and businesses.

(c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?

	Current FY 25-26			Previous FY 24-25		
	Procurement from MSE/SC/ST Vendors (Amount in Crs)	Total Procurement made by the office (Amount in Crs)	%	Procurement from MSE/SC/ST Vendors (Amount in Crs)	Total Procurement made by the office (Amount in Crs)	%
Procurement from MSE Vendors	224.14	425.60	52.66	1,253.94	3,029.63	41.38
SC/ST Vendors under MSE	11.63	425.60	2.73	230.28	3,029.63	7.60

4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge:

Not applicable as we are not in the business of inventions, nor is any artistic works used in our business, for which Intellectual property (IP) owners are granted certain exclusive rights under IP laws. However our in-house developed applications contribute to the internal growth and competitiveness of our operations and we actively engage in knowledge sharing and collaboration with the broader industry and community.

5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved:

Not applicable.

6. Details of beneficiaries of CSR Projects:

LIC GJF supports projects for the economically weaker sections of the society which are aligned with its objectives i.e. – relief or poverty or distress, education, medical relief or any other object of general public utility, across the country. The beneficiary area of projects funded by the LIC Golden Jubilee Foundation are:

Quality Education: Contribution by the Foundation for education infrastructure such as construction of skill centre for developing digital skills amongst the people from lower income group, hostels, school building, computer labs, libraries, school bus, providing transportation facility to the disabled childrens, vocational training centre, occupational therapy tools and audio visual equipment for specially abled children for their rehabilitation through therapy and vocational training programmes, literacy campaign in LIC GJFs adopted village Govindpur for 100% literacy. An amount of ₹ 105.35 Crores has been spent towards providing scholarship to around 41776 deserving students for pursuing higher education. Scholarships are released every year to the deserving students belonging to the economically weaker sections.

Good Health and well-being: The Foundation has funded projects providing medical equipments, ICU ambulance, medical vans, construction of hospitals, providing treatment for cancer patients, congenital heart surgery, bone marrow transplant surgery and cochlear implant surgery. The poor patients are also identified through medical camps arranged by the hospitals in far off rural areas and provided necessary treatment. The Foundation has provided assistance in form of medical equipments Ambulance, treatment support to major hospitals especially Cancer hospitals such as Tata Memorial hospital, Mumbai, Adyar Cancer Institute, Chennai, Kidwai Memorial Institute of Oncology, Bangalore, Regional Cancer Centre, Thiruvananthapuram, Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, Shri Vithalrao Joshi Charities Trusts - B K L Walawalkar Hospital Diagnostic & Research Centre, Chiplun, Hanuman Prasad Poddar Cancer Hospital & Research Institute, Gorakhpur, Dr. Sheela Sharma Memorial Charitable Trust, Mathura, Bagchi Sri Shankara Cancer Foundation, Bhubaneswar, Shri Jagannath Charitable Cancer Institute, Ghaziabad, Sri Shankara Cancer Foundation, Bangalore, Smt Nandamuri Basava Taraka Rama Rao Memorial Cancer Foundation, Khairatabad, Indore Cancer Foundation Charitable Trust, Pigdambar, Malabar Cancer Centre Society, Thalassery, Mohonananda Cancer Diagnostic and Welfare Society, Asansol, Cancer Relief Society – Rashtrasant Tukdoji Cancer Hospital & Research Centre, Nagpur, Gujarat Cancer & Research Institute, Ahmedabad.

Vocational Training and livelihood generation: The Foundation has funded construction of vocational training centers, equipments for setting vocational training centers, etc., which shall enable the beneficiary to get trained for livelihood generation. Funded for training for women handloom weavers is done for enhancing their skills as well as empowering them for livelihood generation. These initiatives have empowered beneficiaries with sustainable income-generating opportunities and enhanced self-reliance.

Tribal Projects: With a strong commitment towards tribal welfare, the Foundation has funded projects benefitting the tribal community by providing assistance for construction of school building, hostels, skill oriented vocational training, toilet blocks, ambulance, school bus for transportation for students and funded 39 tribal projects amounting to ₹ 9.05 Crores.

Disaster relief: During times of crisis, the Foundation has stood firmly with the nation like through COVID-19 Relief Measures by contributing towards PM Cares fund, Govt. of Maharashtra Covid relief fund, Tata Memorial hospital relief fund, etc.

Relief towards Natural Calamity: The Foundation has provided assistance during Chennai floods, Kerala floods, Cyclone Fani and construction of multipurpose Cyclone shelter at Udala in Mayurbhanj District for the people residing in the cyclone prone tribal areas of Odisha. Also funds allocated for Dharalai relief victims, Punjab floods, etc.

Armed Forces Flag Day Fund: Contribution to Armed Force Flag Day Fund for welfare of Ex-Servicemen of the Indian Defence Force established by Kendriya Sainik Board for welfare of the veterans, widows and rehabilitation of ex-servicemen has been made.

Climate Action: Recognizing the importance of environmental sustainability and Climate Action, the Foundation has supported installation of solar power plant at school hostel building, old age home and electric crematorium, thereby promoting renewable energy and reducing environmental and electricity costs.

Clean Water & Sanitation: Under Clean Water and Sanitation, the Foundation has undertaken impactful initiatives by contributing towards renovation of water bodies at Hari Thirtham, Kanyakumari and enabling availability of fresh water for communities. Funds were also allocated for providing water vending machines for clean drinking water to visitors of Badrinath, Kedarnath, Rishikesh and Haridwar.

Contribution towards construction of toilets under 'One Home One Toilet Scheme' in slums of Kolhapur. Funded for construction of 169 toilets in 113 schools across the country, toilet blocks in various school. Contribution towards construction of two community toilets at LIC's adopted village of Govindpur in Sonbhadra district of Uttar Pradesh to make the village free from open defecation. Contribution towards construction of E-Toilets at Badri Dham and funded for Clean Ganga Fund to rejuvenate river Ganga and its ecosystem. Funding done for sewage water treatment plant at Ashraya Centre. These efforts have significantly contributed towards hygiene, sanitation, and access to clean water in under-served areas.

Preservation and protection of tribal art: The Foundation has also played an important role in the Preservation and Protection of Tribal Art and Culture by supporting the construction of tribal art galleries dedicated to preserving and promoting Saura paintings and the rich artistic heritage of tribal communities in three Lanjia Saura villages of Raygada district, Odisha.

Life on Land: In support for Life on Land and Animal Welfare, the Foundation has funded ambulances for rescue and transportation of wild animals, installed solar plant at an animal sanctuary in Village Gopalpur Khera, Gurgaon for animal rescue and rehabilitation, as well as taken initiatives for tree plantation drives.

Through these diverse and impactful interventions, the LIC Golden Jubilee Foundation continues to touch lives, foster inclusive growth and contribute meaningfully towards nation-building and sustainable community development.

Sr. No.	CSR Project	No. of persons who benefitted from CSR Projects	% of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
1	119 Projects completed under community development activities with 59383 beneficiaries and scholarship disbursed to 10660 scholars belonging to the economically weaker sections during the FY 2025-26	59383	100%

PRINCIPLE 9: Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback

The spirit of customer relations and customer care has been ingrained in our complaint redressal system with emphasis on placing customer oriented personnel at all touch points. IT enabled support system is operationalized to reduce manual interventions and minimize grievances. The Corporation has a customer friendly online system wherein a policyholder registered on the customer portal of LIC of India can register a complaint and track its status through 'LIC's e-services' available on our website <https://licindia.in/>. The complaints registered under IRDAI's Grievance Management System – Bima Bharosa are synced with LIC's complaint management system. The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office levels to redress grievances of policyholders. Their names are available on our website. The respective GROs are available at their Offices for personal interviews with customers on all Mondays between 2.30 PM and 4.30 PM. Customers can meet the GROs on other days also with prior appointment. Customers may also send their grievances through post, e-mail, etc., to the respective servicing offices / GROs.

A total of 74 Customer Zones are operative across India from 8.00 AM to 8.00 PM which works as 'one-stop Centre' for resolution of all servicing needs of a customer, with special emphasis on 'Quality Experience'.

LIC has a single Centralized Call Centre service available 24*7. The number is **022-68276827** with a comprehensive IVRS menu as well as an option to speak with a Call Centre executive for specific queries and information and raise CCS (Call Centre Services) Ticket for complaint. These services are available in Hindi, English and eight regional languages.

We have an SMS initiative called LICHELP, where policyholders need to send an SMS LICHELP<POLICYNO> on 9222492224. On receipt of an SMS, an official from the Customer Zone mapped to the servicing branch of the policy, contacts the customer for resolution of his complaint or request. We update the customers at each stage of the policy process through an SMS or an e-mail.

We have WhatsApp services on 8976862090 for the policy-holders whose mobile number is registered to get requisite information about policies.

With an objective of attending grievances related to repudiated death claims, 'Claims Dispute Redressal Committees' are set up at the Zonal and Central Office levels. The committee consists of two or more senior officers of LIC and an Honorable Retired Judge of the District Court/High Court.

LIC has a role-based access under two online platforms of the Government of India viz. 1) CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) and 2) NCH (National Consumer Helpline) – INGRAM module (Integrated Grievance Redressal Mechanism) available to policyholders to lodge their grievances, which are responded to directly.

LIC has constituted Policyholders' Protection, Grievance Redressal and Claims Monitoring Committee (PPGR&CM) in terms of Regulation 5(5) of the IRDAI's (Corporate Governance for Insurers) Regulation, 2024 and master circular issued thereunder, as amended.

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:

Not Applicable.

3. Number of consumer complaints in respect of the following:

	FY 2025-2026		Remarks	FY 2024-2025		Remarks
	Received during year	Pending Resolution at end of the year		Received during the year	Pending Resolution at end of the year	
Data Privacy	1	0	NA	0	0	NA
Advertising	0	0	NA	0	0	NA
Cyber-Security	0	0	NA	0	0	NA
Delivery of Essential Services	49011	0	NA	54636	0	NA
Restrictive Trade Practices	0	0	NA	0	0	NA
Unfair Trade Practices	0	0	NA	0	0	NA
Other	17412	0	NA	19654	0	NA

Note: FY 2025-26 the total grievances includes grievances received on all 3 portals viz ICMS, CPGRAMS, NCH

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:

Nil

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

Yes, The Corporation has policies and procedures on Data privacy and cyber security. The complete set of policies is available on the intranet for all employees.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services.

The Corporation takes proactive measures for any issue or complaint related to cyber security and data privacy of customers.

7. Provide the following information relating to data breaches:

a) Number of instances of data breaches:

One incident of cyber security intrusion was reported on 29.07.2025

b) Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers:

N.A.

c) Impact, if any, of the data breaches:

No Impact

Leadership Indicators

1. Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).

Information related to all the products and services provided by the Corporation are available in the public domain i.e. our website, www.licindia.in. In addition, the Corporation actively uses print media, social media and digital platforms to disseminate information on its products and services, to educate and to stay connected with our customers.

- ❖ Mobile App: My LIC App, LIC Digital App
- ❖ Face book: LICIndiaForever
- ❖ YouTube: LICIndiaForever
- ❖ Instagram: LICIndiaForever
- ❖ LinkedIn: LICIndiaForever
- ❖ X (Twitter) handle: LICIndiaForever
- ❖ Whatsapp: 8976862090
- ❖ Call Centre : +91-022- 6827 6827

LIC has launched the My LIC APP for its customers, providing various services such as KYC verification, online policy loan, policy renewals, update contact details, update email id, update address, update NEFT details, premium payment, update bank details, online revival with DGH, etc.

2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

Insurance is an intangible product so the normal usage and safety norms do not apply to it. However for continuance of risk cover, premiums must be paid on time. SMS are sent to the policyholders informing them about premium due for payment, wherever mobile number is registered in policy record. Where no mobile number is registered in policy records, we are sending premium due intimation to the policyholders by post, in order to keep policies in force and to enable the customer to enjoy the insurance benefits under the policy. SMS are sent to customers to be careful with fraudsters. Security measures are in place for customers visiting our links for any online transactions.

Introduction of services of LIC on WhatsApp is made available where Policyholders can know their premium dues, get Loan and Loan repayment quotation, Premium paid certificate/s, ULIP Unit statement/s, etc. Periodical communication is sent to active customers to educate them on spurious calls and false calls for submission of KYC. Also spurious call disclaimer forms part of our customer communications. We promote in-house digital platforms that provide various customer services to customers periodically. Alerts are conveyed on Social Media. We are publishing advertisement in regional, Hindi and English Newspapers informing about the requirements for settlement of claims. We also inform and educate customers by hosting our ads on social media such as Facebook, Instagram page, etc. regularly. We share information vide email, whatsapp message, My LIC app, postal letters and also occasionally through IVRS, AI agent voice BOT.

3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/ discontinuation of essential services.

Policyholders are kept updated through SMS about the services requested by them. In case of natural calamity advertisement is given in the newspapers, informing customers' assistance with claim processing to enable faster and hassle free processing of the claim.

We have a Business Continuity Plan in place with Standard Operating Procedures in case of any risk of disruption/discontinuation of service.

4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole?

The required information about insurance products and services is accessible on our website www.licindia.in.

To capture customer's feedback on the overall experience of the engagement, feedback is sought through customer meets and visits to Paying Authorities.

RAMA K. GUPTA & CO.

Chartered Accountants

"JAIGURUDEV"

**Head Office:** 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.**Mobile:** 09425112778, 8770223278**Email:** ramakantgupta@yahoo.com,
ramakant@rkgroup.co.in

INDEPENDENT REASONABLE ASSURANCE REPORT ON IDENTIFIED SUSTAINABILITY INFORMATION IN THE BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT (BRSR) FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2026

To,
The Board of Directors
Life Insurance Corporation of India
Central Office, "Yogakshema",
Jeevan Bima Marg,
Mumbai - 400 021.

We have undertaken to perform a reasonable assurance engagement for Life Insurance Corporation of India (the "Corporation") vide appointment letter dated 24.04.2026 issued by the Corporation and accepted by us vide our engagement letter dated 24.04.2026 in respect of the agreed Sustainability Information referred in accordance with the Criteria stated in the "Criteria" paragraph below. The Identified Sustainability Information is included in the Business Responsibility and Sustainability Report ("BRSR") Section of the Integrated Annual Report of the Corporation for the financial year ended March 31, 2026 pursuant to the requirement of Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "LODR Regulations").

Criteria

The criteria used by the Corporation to prepare the Identified Sustainability Information is the "BRSR" as detailed in Annexure 1 to this report (the "Criteria"), which is a subset of the BRSR, consisting of a set of KPIs/ metrics under nine Environmental, Social and Governance ("ESG") attributes, as specified by SEBI vide its circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July 12, 2023 (the "SEBI Circular"), SEBI/HO/CFD-PoD-1/CIR/2025/42 dated 28th March, 2025, the Guidance note for BRSR read with National Guidelines for Responsible Business Conduct issued by

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com,
ramakant@rkggroup.co.in

Ministry of Corporate Affairs ("BRSR Framework") and Industry Standards on Reporting of BRSR Core vide SEBI circular no. SEBI/HO/CFD-PoD-1/D/CIR/2024/177 dated 20th December 2024.

Management's Responsibility

The Corporation's management is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the Identified Sustainability Information, taking into account applicable laws and regulations, if any, related to reporting on the Identified Sustainability Information, identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the Criteria. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and the measurement of the Identified Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error. The Management and the Board of Directors of the Corporation are also responsible for overseeing the Corporation's compliance with the requirements of the LODR Regulations, the SEBI Circular and BRSR Framework in relation to the sustainability information included in the Annual Report.

Inherent limitations in preparing the Identified Sustainability Information

The absence of a significant body of established practice on which to draw to evaluate and measure non-financial information allows for different, but acceptable, measures and measurement techniques and can affect comparability between entities. In addition, Greenhouse Gas ("GHG") quantification is subject to inherent uncertainty because of incomplete scientific knowledge used to determine emissions factors and the values needed to combine emissions of different gases.

Auditor's Independence and Quality Control

We are independent of the Corporation and have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.**Chartered Accountants**

"JAIGURUDEV"

**Head Office:** 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.**Mobile:** 09425112778, 8770223278**Email:** ramakantgupta@yahoo.com,
ramakant@rkggroup.co.in

Accountants of India ("ICAI") and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement. Our firm applies Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements" and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express a reasonable assurance in the form of an opinion on the Identified Sustainability Information based on the procedures we have performed and evidence we have obtained. We conducted our engagement in accordance with the Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information", issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the ICAI. The standard requires that we plan and perform our engagement to obtain reasonable assurance about whether the Identified Sustainability Information are prepared, in all material respects, in accordance with the Criteria. A reasonable assurance engagement involves assessing the suitability in the circumstances of the Corporation's use of the Criteria as the basis for the preparation of the Identified Sustainability Information, assessing the risks of material misstatement of the Identified Sustainability Information whether due to fraud or error, responding to the assessed risks as necessary in the circumstances and evaluating the overall presentation of the Identified Sustainability Information.

The procedures we performed were based on our professional judgement and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records.

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.

Chartered Accountants

"JAIGURUDEV"



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkgroup.co.in

Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, our work procedures included the following:

- Obtained an understanding of the Identified Sustainability Information and related disclosures.
- Obtained an understanding of the assessment criteria and their suitability for the evaluation and/or measurements of the Identified Sustainability Information.
- Made enquiries of Corporation's Management, including the various teams such as Sustainability team, and those with responsibility for managing Corporation's Annual Reporting.
- Obtained an understanding and performed an evaluation of the design of the key systems, processes, and controls for managing, recording and reporting on the Identified Sustainability Information. This did not include testing the operating effectiveness of management systems and controls.
- Based on above understanding, the risks that the Identified Sustainability Information may be materially misstated, determined the nature, timing, and extent of further procedures.
- Performed substantive testing on a sample basis of the Identified Sustainability Information within the standalone boundary to check that data had been appropriately measured with underlying documents recorded, collated, and reported. This included assessing records and performing testing, including recalculation of sample data to establish an assurance trail.
- Checked the consolidation for various sites and corporate office under the standalone reporting boundary (as mentioned in the Integrated Annual Report, which includes BRSR) for ensuring the completeness of data being reported.
- Assessed the level of adherence to the BRSR format issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) followed by the Corporation in preparing the BRSR.
- Obtained representations from the Corporation's Management.
- Assessed the BRSR for detecting, on a test basis, any major anomalies between the information reported in the BRSR on performance with respect to agreed information and relevant source data/information.
- Where applicable for the Identified Sustainability Information in the BRSR, we have relied on the information in the audited standalone financial statements of the Corporation for the year ended March 31, 2026.

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com,
ramakant@rkgroup.co.in

- Evaluated the reasonableness and appropriateness of significant estimates and judgments made by the Management in the preparation of the Identified Sustainable Information.

Exclusions

Our reasonable assurance engagement scope excludes the following and therefore, we do not express an opinion on the same:

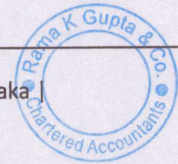
- Any disclosure other than those mentioned in the Identified Sustainability Information section above;
- Data and information outside the defined reporting period;
- Data related to Corporation's financial performance, strategy and other related linkages expressed in the Report;
- The Corporation's statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, forward looking statements provided by the Corporation and assertions related to Intellectual Property Rights and other competitive issues; and
- Mapping of the Report with reporting frameworks other than those mentioned in Reporting Criteria above.
- We have not performed any procedures with respect to prior periods information.

While we considered the effectiveness of management's internal controls when determining the nature and extent of our procedures, our assurance engagement was not designed to provide assurance on internal controls. The procedures did not include testing controls or performing procedures relating to checking aggregation or calculation of data within IT systems.

Opinion

Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained, the Identified Sustainability Information included in the BRSR for the financial year ended 31st March 2026 is prepared in all material respects, in accordance with the Criteria.

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com,
ramakant@rkggroup.co.in

Restriction on use or distribution

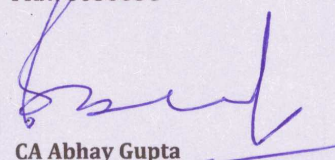
Our obligations in respect of this report are entirely separate from, and our responsibility and liability is in no way changed by, any other role we may have (or may have had) as auditors of the Corporation or otherwise, nothing in this report, nor anything said or done in the course of or in connection with the services that are the subject of this report, will extend any duty of care we may have in our capacity as auditors of the Corporation.

This report has been issued at the request of the Board of Directors of the Corporation to whom it is addressed, solely to enable them to comply with the requirements of the Circular and LODR Regulations and on reporting Corporation's sustainability performance and activities, for publishing the same in the Corporation's Integrated Annual Report, which includes the BRSR. Our report should not be used for any other purpose or by any person other than the addressee of our report. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

Place: Mumbai
Date: 17.06.2026



For Rama K. Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 005005C



CA Abhay Gupta
Partner
Membership No. 087679
UDIN: 26087679SDRVXU9956

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |

RAMA K. GUPTA & CO.

Chartered Accountants

"JAIGURUDEV"



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh
Galaxy City, Ayodhya Bypass Road,
Bhopal (M.P.) 462022.

Mobile: 09425112778, 8770223278

Email: ramakantgupta@yahoo.com,
ramakant@rkggroup.co.in

Annexure I**BRSR Core Attributes**

BRSR Indicator	Type of Assurance
Principle 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment	
Attribute 1: Green-house gas (GHG) footprint	
Question 7: Details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity owned or controlled sources.	Reasonable
Total Scope 1 emissions	
Total Scope 2 emissions	
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee crore of turnover	
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
Attribute 2: Water footprint	
Question 3: Details of the following disclosures related to water:	Reasonable
Water withdrawal by source (in kiloliters)	
Total volume of water withdrawal (in kiloliters)	
Total volume of water consumption (in kiloliters)	
Water intensity per rupee crore of turnover (Total water consumption / Revenue from operations)	
Water intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity(PPP)	
Water intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
Question 4: Details related to water discharged:	
Water discharge by destination and level of treatment (in kiloliters)	

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkggroup.co.in

Total water discharged (in kiloliters)	
Attribute 3: Energy footprint	
Question 1: Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity:	Reasonable
Total energy consumed from renewable sources	
Total energy consumed from non-renewable sources	
Energy intensity per rupee crore of turnover (Total energy consumed / Revenue from operations)	
Energy intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Energy intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
Attribute 4: Embracing circularity - details related to waste management by the entity	
Question 9: Provide details related to waste management by the entity:	Reasonable
Total Waste generated for each category of waste (in metric tonnes)	
Waste intensity per rupee crore of turnover (Total waste generated/Revenue from Operations)	
Waste intensity per crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Waste intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, reusing or other recovery operations (in metric tonnes)	
For each Category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)	
Principle 3: Businesses should respect and promote the well-being of all employees, Including those in their value chains	
Attribute 5: Enhancing Employee Wellbeing and Safety	

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



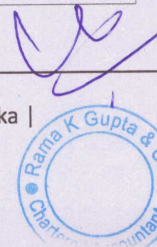
RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkggroup.co.in

Question 1(C): Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent): Cost incurred on well-being measures as a % of total revenue of the company	Reasonable
Question 11: Details of safety related incidents for Employees and Workers:	
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	
Total recordable work-related injuries	
No. Of fatalities	
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	
Principle 5: Businesses should respect and promote human	
Attribute 6: Enabling Gender Diversity in Business	
Question 3(b): Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity	Reasonable
Question 7: Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:	
Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act. 2013 (POSH)	
Complaints on POSH as a % of female employees /workers	
Complaints on POSH upheld	
Principle 8: Businesses should promote inclusive growth and equitable development	
Attribute 7: Enabling Inclusive Development	
Question 4: Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:	Reasonable
a. Directly sourced from MSMEs/ small producers	
b. Directly from within India	
Question 5: Job creation in smaller towns — Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent/on contract basis) in smaller towns, as % of total wage cost.	
Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customer in a responsible manner	

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
 Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkggroup.co.in

Attribute 8: Fairness in Engaging with Customers and Suppliers

Question 7: Provide the following information relating to data breaches:	Reasonable
a. Number of instances of data breaches	
b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers	
c. Impact, if any, of the data breaches	
Question 8: Number of days of accounts payable ((Accounts payable*365) / Cost of goods/services procured)	

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Attribute 9: Open-ness of business

Question 9: Details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties:	Reasonable
Concentration of Purchases	
Concentration Of Sales	
Share of RPTs in	
a. Purchases (Purchases With related parties / Total purchases)	
b. Sales (Sales to related parties / Total Sales)	
c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties / Total loans & advances)	
d. Investments (Investments in related parties / Total Investments made)	



Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
 Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |